RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 191
नई दिल्ली, शनिवार, 16 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

नैंसी ड्रू अपनी पहचान दोबारा हासिल करने के बारे में है : मैकमैन
विविध-12

www.dailypioneer.com

देश में वायरस की लंबी छलांग, पीछे छूटा चीन

- देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 86,000, 2600 से ज्यादा मौतें
- लॉकडाउन-1 के ऐलान के समय 25 मार्च को चीन में थे कुल 81,440 जबकि भारत में थे महज 500 केस

दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 के मामलों का परिक्षण करते स्वास्थ्य कर्मी।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में अब भारत पड़ोसी देश चीन से आगे निकल गया है। भारत में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा शुक्रवार को बढ़कर करीब 86 हजार पहुंच गया है। इस तरह कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में अब विश्व में भारत का स्थान 11वां हो गया है। हालांकि इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की दर चीन में जहां 5.5 प्रतिशत है तो यहां 3.2 फीसद है। खास यह कि देश में इस बीमारी से अब तक लगभग 30,000 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 2,746 की मौत हो चुकी है। चीन में इस बीमारी से 4,633 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका, चीन, स्पेन और रूस इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। कोरोना का सबसे पहला केस चीन में मिला था।

उसके बाद चीन में 25 मार्च को 81,440 केस थे। उस समय भारत में केवल 500 मामले आए थे और उसी दिन भारत ने पहले पहले चरण के लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब, लॉकडाउन के 52 दिनों में और कोरोना का पहला केस आने के 106 दिन बाद भारत में कोरोना केस चीन से अधिक हो गए हैं। देश के सात राज्य- महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा केस हैं, पिछले 24 घंटों में 1,576 मामले सामने आए हैं। यहां अब कुल मामले 29,100 पहुंच गए हैं। तमिलनाडु में 434 नए मामले आए हैं और कुल 10,108 केस हो गए हैं। दिल्ली में 425 नए केस आए हैं और कुल मामले बढ़कर 8,895 हो गए हैं। गुजरात में भी 340 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं और यहां कुल केस 9,932 हो गए हैं।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी क्रमशः 4,595, 4,688 और 3902 नए मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल से 84 नए केस आए और यहां कुल संख्या बढ़कर 2,461 पहुंच गई है। बिहार और कर्नाटक में आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। बिहार में छह नए मामलों के साथ 1005 कोविड-19 पीड़ित हो गए हैं, जबकि 45 नए मामले सामने आने के बाद कर्नाटक की संख्या बढ़कर 1,032 हो गई है। देश में शुक्रवार को कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 49, गुजरात 20, दिल्ली 9 और पश्चिम बंगाल में 8 मौतें हुईं। देश में यह सबसे ज्यादा है। गोवा, जो भारत में कोरोना मुक्त बनने वाले पहले राज्यों में शामिल (शेष पेज 9)

आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त-अन्नदाता पर कृपा

- कृषि, डेयरी मधुमक्खीपालन, औषधीय खेती को बढ़ावा दोगुनी आमदनी और भंडारण का इंतजाम
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा संशोधन, कानूनी शिकंजे से मुक्त होंगे अनाज, खाद्य तेल और दाल

नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अनुराग ठाकुर।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सरकार ने कृषि एवं इससे जुड़े डेयरी, मछलीपालन, मधुमक्खीपालन और औषधीय खेती जैसे क्षेत्रों के लिये 1.63 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की शुक्रवार को घोषणा की।

पैकेज का लक्ष्य कृषि उपज के बेहतर रखरखाव, परिवहन और दूसरी जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिये क्षमता निर्माण को मजबूती देना है। साथ ही सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी कृषि उपज को 'नियंत्रणमुक्त' करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन करने जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से पस्त अर्थव्यवस्था को उठाने के लिये घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त जारी करते हुए शुक्रवार को एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी संरचना कोष की घोषणा की। इस कोष से उन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा, जो फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन व भंडारण आदि से संबंधित हैं। इसके अलावा सूक्ष्म खाद्य इकाइयों, पशुओं के टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, औषधीय खेती, मधुमक्खी पालन और फलों एवं सब्जियों के लिये भी योजनाओं की घोषणा की गयी। सीतारमण ने कहा कि कृषि बुनियादी संरचना कोष के तहत संग्राहकों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप को एक लाख करोड़ रुपये के कोष से सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस कोष का गठन किया जायेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी के इलाकों के आस-पास पर्याप्त संख्या में शीत भंडार गृहों तथा उपज के बाद के प्रबंधन संबंधी बुनियादी संरचनाओं के अभाव के कारण मूल्य श्रृंखला में अभाव उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन, औषधीय, जैविक तथा पोषक जड़ीबूटी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये दो लाख सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों की मदद को लेकर 10 हजार करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की। इसके अलावा सरकार समुद्री और भूक्षेत्र में मत्स्यपालन के लिये 20 हजार करोड़ रुपये की (शेष पेज 9)

लॉकडाउन फोर के लिए राज्यों ने बनाया रोडमैप

- स्थानीय जरूरतों के आधार पर रियायतों व पाबंदियों की तैयारी, केंद्र को भेजे सुझाव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने के लिए केंद्र योजनाएं बना रहा है। वहीं राज्यों ने मेट्रो और विमान सेवाएं समेत सार्वजनिक परिवहन शुरू करने तथा संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देने जैसे प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चली छह घंटे लंबी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इस मुद्दे पर राय देने को कहा था। लॉकडाउन 4.0 'जमीनी स्तर पर हालात को सामान्य दिखाएगा।' मौजूदा लॉकडाउन-25 मार्च को लागू किए जाने के बाद तीसरा-रविवार को खत्म हो रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफे को देखते हुए इसे फिर बढ़ाया जाएगा लेकिन अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कुछ उपायों के साथ, जिसके तहत आर्थिक गतिविधियों को और छूट प्रदान किया जाएगा।

कई राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शामिल हैं, ने आर्थिक गतिविधियों को खोलने की वकालत की है। उदाहरण के लिए आंध्र ने संक्रमण मुक्त इलाकों में सभी आर्थिक और सार्वजनिक गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की प्रतिक्रिया और सुझाव पाने के बाद कहा कि संक्रमित इलाकों को छोड़कर दिल्ली में कुछ आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली पर से और पाबंदियां हटाने की भी मांग की।

राजस्व के लिए किसी हद तक पर्यटन पर निर्भर रहने वाला राज्य केरल भी मेट्रो, लोकल ट्रेन, घरेलू उड़ानें, रेस्टोरेंट तथा होटलों को फिर शुरू करना चाहता है। इस राज्य में देश के पहले तीन कोरोना वायरस के मामले आए थे लेकिन इसने तेजी काम किया और अब आए 560 मामलों में से 500 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं तथा अभी तक केवल चार मौतें हुई हैं। एक अधिकारी के मुताबिक इन तथ्यों को देखते हुए राज्य के अनुरोध में काफी दम दिखता है। कर्नाटक (शेष पेज 9)

मजदूरों की पैदल यात्रा पर रोक से कोर्ट का इनकार

- केंद्र ने कहा-बसें चल रहीं लेकिन बारी का इंतजार न कर पैदल ही निकल रहे लोग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिये असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

केन्द्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि देश भर में इन प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये सरकार परिवहन सुविधा मुहैया करा रही है लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैदल ही चल देने की बजाये अपनी बारी का इंतजार करना होगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रास्ते में फंसे कामगारों की पहचान कर उनके लिये खाने और आवास की व्यवस्था करने का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने हेतु दायर आवेदन पर विचार करने से इंकार कर दिया। इस मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि क्या इन कामगारों को सड़कों पर पैदल ही चलने से रोकने का कोई रास्ता है।

मेहता ने कहा कि राज्य इन कामगारों को अंतरराज्यीय बस सेवा उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन अगर लोग परिवहन सुविधा के लिये अपनी बारी का इंतजार करने की बजाये पैदल ही चलना शुरू कर दें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि राज्य सरकारों के बीच समझौते से प्रत्येक व्यक्ति को अपने गंतव्य तक यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजमार्ग पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं में श्रमिकों के मारे जाने की घटनाओं (शेष पेज 9)

मुम्बई-नासिक हाइवे से गुजरता प्रवासी मजदूरों का जत्था।

रेलवे, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए। हाई कोर्ट ने सरकार इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और सुनिश्चित करे कि मजदूरों को पैदल ना जाना पड़े। बता दें कि दिगी समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त प्रवासी मजदूर पैदल ही (शेष पेज 9)

म्यांमा ने 22 से अधिक उग्रवादी भारत को सौंपे

नई दिल्ली। म्यांमा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की निगरानी में हुए गुप्त अभियान के बाद एनडीएफबी (एस) के स्वयंभू गृह सचिव राजेन डिमरी समेत 22 से अधिक उग्रवादियों को शुक्रवार को भारत सौंप दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा उग्रवादियों को एक विशेष विमान से भारत लाकर मणिपुर और असम में पुलिस बलों के हवाले कर दिया गया, जहां उन्हें वांछित घोषित किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि 10 उग्रवादी मणिपुर जबकि शेष असम में वांछित थे।उन्होंने कहा कि इसे म्यांमा की सेना के साथ विचार-विमर्श करने वाले डोभाल की अगुवाई में एक अभूतपूर्व कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के पूर्वी पड़ोसी देश ने पहली बार इस तरह विद्रोहियों को भारत के हवाले किया है।अधिकारियों ने कहा कि इसे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य संबंध में गहराई के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

बाजार

सेंसेक्स	31,097	↓ 25
निफ्टी	9,136	↓ 5
सोना		/10g
चांदी		/kg

क्विक न्यूज

सेना भवन में कोरोना की घुसपैठ, सैनिक संक्रमित

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने सेना के मुख्यालय में भी घुसपैठ कर ली है। शुक्रवार को एक सैनिक के कोविड-19 पॉजिटिव मिलने के बाद, मुख्यालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया। एक अधिकारी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कोविड-19 की जांच में एक सैनिक संक्रमित पाया गया। इसके बाद, सेना भवन के प्रभावित हिस्से को साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही, कोरोना संक्रमित सैनिक के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और उन्हें क्वॉरंटीन करने जैसे प्रोटोकोल का पालन भी किया जा रहा है।

चीन-नेपाल साठगांठ पर कटाक्ष

लिपुलेख रोड पर नेपाल के विरोध के पीछे कोई और: सैन्य प्रमुख

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करने के मकसद से उत्तराखंड में नवनिर्मित सड़क पर नेपाल के आपत्ति जताने पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इशारों-इशारों में चीन पर निशाना साधा है।

सैन्य प्रमुख ने कहा कि नेपाल और चीन की साठगांठ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लिपुलेख रोड पर नेपाल किसी और के कहने पर ऐतराज जता रहा है। उनकी यह टिप्पणी लद्दाख और सिक्किम में भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में हुए संक्षिप्त संघर्ष की पृष्ठभूमि में आया। उनकी इस टिप्पणी को चीन के लिए स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पिछले सप्ताह उद्घाटन किए गए 80 किलोमीटर की रोड पर काठमांडू के ऐतराज को नकारते हुए नरवाणे ने कहा कि लिपुलेख से (शेष पेज 9)

मानसून एक्सप्रेस चार दिन लेट

- पांच को पहुंचेगी केरल, अमूमन एक जून को केरल तट पर दस्तक देता है मानसून

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मानसून एक्सप्रेस इस साल चार दिन देर से पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इस सीजन में केरल तट पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दस्तक देने की अपेक्षित तारीख 5 जून है, जबकि यह अमूमन 1 जून को आ जाता है।

दूसरी ओर, निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट का आकलन है कि 28 मई को मानसून केरल के ऊपर आ सकता है। इसमें दो दिन आगे-पीछे हो सकता है। स्काईमेट ने कहा है कि शुरुआत की तारीख का देश के अन्य हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, केरल में इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्य तिथि की तुलना में इस साल थोड़ी देरी से होने की संभावना है लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर चार दिन पहले अगले 48 घंटों में मानसून पहुंच जाने की उम्मीद है। आम तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है लेकिन इसमें लगभग सात दिनों की देर-सबेर रहती है। पिछले साल केरल में मॉनसून की शुरुआत में सात दिन की देरी हुई थी। पिछले 10 वर्षों में 2009 में सबसे पहले 23 मई को मानसून आ गया था जबकि सबसे देर में 8 जून 2016 को यह केरल पहुंचा था।

मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केरल में मॉनसून के आगमन में देरी के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे असामान्य रूप से एक के बाद एक आने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो सीधे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और इसका असर यहां होने वाली मानसून की बारिश पर पड़ता है। इस साल बीते 15 अप्रैल को मौसम विभाग ने अपना शुरुआती पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा था कि इस साल देश में (शेष पेज 9)

लोग कोरोना से जान बचाने में जुटे थे, आबकारी विभाग शराब घोटाले में

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के करोड़ों लोग जिस समय कोरोना के कारण अपनी जान बचाने में जुटे हुए थे उस समय हरियाणा का आबकारी विभाग घोटाले के अंजाम देने में जुटा हुआ था। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरी एकजुटता के साथ अपनी मनमानियां की।

आमतौर पर सरकारी विभागों में जहां महीनों फाइलें धूल फांकती रहती है वहीं हरियाणा में आबकारी विभाग ने 26 मार्च को इतनी तेजी दिखाई की एक ही दिन में शराब के 436 परमिट जारी कर डाले। यह परमिट जारी करने वालों में कई ऐसे कर्मचारी थे जो मुख्यालय में तैनात अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार और सफेदपोशों के करीबी थे।

22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन शुरू हो गया। 26 मार्च को हरियाणा में आबकारी विभाग ने अपना खेल शुरू कर दिया।

केवल 26 मार्च को जारी हुए 436 परमिट

अंतिम दिन जींद, रेवाड़ी, रोहतक में हुआ खेल

सोनीपत में स्वीकार हुए शतप्रतिशत आवेदन

हरियाणा की मुख्य सचिव ने वर्क फ्राम होम के आदेश जारी किए थे और आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण भाव से एक ही दिन में 436 परमिट जारी कर डाले। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च को एक्साइज परमिट के लिए 471 आवेदन आए। जिनमें से औपचारिकता पूर्ण करते हुए केवल 11 को खारिज किया गया और 24 को पेंडिंग छोड़ दिया गया। 26 मार्च को जारी किए गए परमिट का मुख्य केंद्र जींद, रेवाड़ी, रोहतक रहा जहां 50 से अधिक परमिट जारी किए गए। इसके अलावा सोनीपत, सिरसा, पानीपत, नारनौल, कुरूक्षेत्र, करनाल व गुरुग्राम आदि ऐसे जिले हैं जहां शतप्रतिशत आवेदन स्वीकार करते हुए थोक के भाव में शराब परमिट जारी कर दिए गए। इस परमिट के बल पर फैक्टरी में तैयार की गई शराब को होलसेल दुकानों तक पहुंचाया गया।

मुख्यालय पर मौजूद रहे संरक्षक तो जिलों में हुआ खेल

लॉकडाउन में जिला स्तर पर शराब के परमिट जारी किए जाने का खेल मुख्यालय की मूक सहमति के साथ ही सिरे चढ़ा है। रेवाड़ी, सोनीपत आदि समेत अन्य जिलों में यह परमिट जारी करने वाले ज्यादातर अधिकारी ऐसे हैं जिनके करीबी चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय पर आबकारी विभाग तथा अन्य विभागों में उच्च पदों पर आसीन हैं। जिनके साथ करीब संबंधों का लाभ उठाकर बेखौफ होकर यह खेल खेला गया।

एक दिन में इन जिलों में जारी किए परमिट

जिला का नाम	जारी परमिट
अंबाला	03
भिवानी	47
फरीदाबाद	41
गुरुग्राम (ईस्ट)	15
गुरुग्राम (वैस्ट)	07
हिसार	06
जगाधरी	07
झज्जर	24
जींद	65
कैथल	25
करनाल	20
कुरूक्षेत्र	13
मेवात	06
नारनौल	07
पानीपत	09
रेवाड़ी	50
रोहतक	57
सिरसा	20
सोनीपत	14

गुहला व सीवन में पंचायती जमीन पर नहीं लगेगी धान की फसल

50 हॉर्स पॉवर बिजली के कनैक्शन वाले किसान नहीं लगा सकते धान

मोहित गुलाटी। कैथल

बैठक में दिशा-निर्देश देते उपायुक्त सुजान सिंह।

उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा जिला के दो खंड सीवन व गुहला की पंचायती जमीन पर धान की फसल लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ-साथ इन दोनों खंडों में किसानों को 50 प्रतिशत भूमि पर धान की बजाए मक्का, बाजरा, दालें आदि लगानी अनिवार्य है, जो किसान ऐसा नहीं करेगा, उसे कृषि योजनाओं से जुड़ी किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी फसल की खरीद भी नहीं की जाएगी।

उपायुक्त सुजान सिंह लघु सचिवालय में मेरा पानी-मेरी विरासत योजना की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा गुहला व सीवन खंड डार्क जोन में हैं, इसलिए भावी पीढ़ी के लिए जल बचाना जरूरी है। किसानों को अपनी 50 प्रतिशत भूमि पर धान की बजाए मक्का, बाजरा व अन्य फसलें लगानी चाहिए, ऐसा करने से जहां जल संरक्षण होगा, वहीं किसानों को सरकार की ओर से प्रति एकड़ 7 हजार रुपये की राशि भी दी जाएगी। अन्य फसल लगाने से किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। मक्का लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा यंत्र भी मुहैया कराए जाएंगे। जो किसान धान की बजाए मक्का, बाजरा या अन्य फसल लगाएगा और खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाना चाहेगा तो उसे 85 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिला के जिन किसानों के पास 50 हॉर्स पॉवर इलैक्ट्रिक मोटर कनैक्शन है, वे सभी किसान धान की फसल नही लगा सकते। धान की फसल की बजाए वे मक्का, बाजरा, दालें आदि फसल लगा सकते हैं।

मनोहर पार्ट टू : सरकार के गले की फांस बना शराब घोटाला

जांच के मुद्दे पर भी एकमत नहीं भाजपा व जजपा

विपक्ष ने एकजुटता के साथ सरकार को घेरा

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

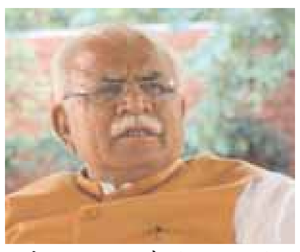

हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुआ शराब घोटाला मनोहर सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर पूरी आक्रामकता के साथ सरकार को घेर रहा है वहीं सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन भी जांच को लेकर एकमत नहीं है। केवल गृहमंत्री अनिल विज शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत अन्य कैबिनेट मंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं।

हरियाणा की मनोहर सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार पहली बार किलोमीटर स्कीम घोटाले में घिरी लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुहिम नहीं बना पाया। अब लॉकडाउन के दौरान सुर्खियों में आया शराब घोटाला सरकार के लिए नई मुसीबत बन गया है। इस घोटाले को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शराब घोटाले की जांच के मुद्दे पर आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज के विरोधाभासी बयान पहले ही सार्वजनिक हो चुके हैं। अनिल विज ने अपने बल पर एसआईटी तो बनाई लेकिन अफसरशाही ने अधिसूचना जारी करते समय उसे एसईटी बना दिया।

दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा इनेलो विधायक अभय चौटाला इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग उठा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शराब घोटाले की परतें जहां पूरे प्रदेश में खुलती जा रही है वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर चुप हैं।

प्रदेश के आधा दर्जन जिले शराब घोटाले की चपेट में

चंडीगढ़। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की परतें धीरे-धीरे खुलती जा रही हैं। पूर्व विधायक, जजपा नेता सतविंदर राणा की गिरफ्तारी से जहां कई सफेद पोश रॉडार पर आ गए हैं वहीं शराब घोटाले में लगातार हो रही गिरफ्तारियों से पुलिस व सिविल प्रशासन के अफसरों को भी पसीने आ रहे हैं। हरियाणा में अब तक पांच जिले शराब घोटाले की चपेट में आ चुके हैं। यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत के खरखौदा स्थित मालखाने से जहां करोड़ों रुपये शराब गायब हुई वहीं पानीपत के समालखा में शराब चोरी का खेल हुआ। इसी केस में सतविंदर राणा की गिरफ्तारी हुई है। नारनौल में लॉकडाउन के दौरान उजागर हुए शराब घोटाले में पता चला है कि पुलिस कर्मियों ने 70 पेटी शराब यह कहकर निकाली कि बरामद की गई शराब नष्ट किया जाएगा। पुलिस कर्मियों ने शराब को नष्ट करने की बजाए बेच डाला। इस मामले में दो पुलिस कर्मी निलंबित हो चुके हैं। लॉकडाउन से पहले फतेहाबाद में भी शराब की ढाई लाख बोतलें गायब होने का मामला सामने आया है। फतेहाबाद के डीईटीसी वीके शास्त्री ने घोटाले की रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भेज दी है, लेकिन उस पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

दीपेंद्र हुड्डा का दावा, लॉकडाउन में 52 ठेकों से बेची गई शराब

चंडीगढ़। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को शराब घोटाले और किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया है। सांसद बनने के बाद पहली बार शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी के आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के 52 ठेकों से अवैध शराब बेची गई थी। शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित करने की बजाय एसईटी बनाकर प्रदेश वासियों की आंखों में धूल झौंकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना यह शराब नहीं बिक सकती। शराब घोटाले पर गठित एसआईटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार के नेताओं के खिलाफ कैसे जांच कर पाएगी। यह बड़ा सवाल है।

शराब तस्करों के साथ वायरल हो रहे फोटो पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सतविंद्र राणा जननायक जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और कलायत से जजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है। भूपेंद्र सिंह के जो फोटो वायरल किए जा रहे हैं, वह अब के नहीं हैं। प्रदेश में हजारों करोड़ का शराब घोटाला होने का दावा करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार किसानों व व्यापारियों से ज्यादा चिंता शराब ठेकेदारों की है। इसलिए इस शराब घोटाले की जांच सीबीआई अथवा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से करानी चाहिए।

सुरजेवाला ने घोटालों पर पूछे सीएम से सवाल

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में हुए शराब घोटाले के साथ-साथ अन्य घोटालों के मुद्दे पर भी सरकार को घेर लिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के साढ़े पांच साल के कार्यकाल में किसी मामले या घोटाले की जांच न संपूर्ण हुई और न ही नतीजा सामने आया। इसका सबूत धान घोटाला पार्ट-एक, माइनिंग घोटाला, गुरुग्राम-फरीदाबाद-अरावली पहाड़ कॉलोनाइजेशन घोटाला, एससी छात्रवृत्ति घोटाला, कुछ महीने पहले हुआ धान घोटाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा शराब घोटाला भी इसी लीपा-पोती व जांच पर परदा डालने की नीति की भेंट चढ़ जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा मुफ्त की वितरित

करनाल। आयुष विभाग करनाल द्वारा एम बाल भवन आश्रम, मधुबन और बाल कारागार में रह रहे बच्चों को और वहां कार्यरत कर्मचारियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां मुफ्त वितरित कीं। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सतीश खटकड़ ने स्वयं अपनी देखरेख में दवाओं के वितरण का कार्य कराया। डॉ. राजबीर लांगायन, डॉ. नितिन रोहिला, नरेश कुमार फार्मासिस्ट और बबलीन ने दवाइयां वितरित की। प्रोटेक्शन अधिकारी सुमन नैन भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में पुलिस विभाग, जिला कारागार, नगर निगम और पंचायती राज विभाग को भी दवाइयां वितरित की गई हैं। महानिदेशक आयुष हरियाणा के निर्देशानुसार में हरियाणा में यह व्यवस्था बनाई जा रही है।

लॉकडाउन में भी रक्तदाताओं का हौसला बरकरार

कुरुक्षेत्र। लॉकडाउन में भले ही आमजन को घरों में सिमटकर रहने को मजबूर कर दिया हो, परंतु लॉकडाउन में भी रक्तदाताओं का हौसला बरकरार रहा। बीते 52 दिनों में रक्तदाताओं ने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान आयोजित किए गए 23 रक्तदान शिविरों में 508 यूनिट रक्तदान किया है। जानकारी देते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक व हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. शैलेन्द्र ममगाईं शैली ने बताया कि लॉकडाउन में भी अस्पताल की ब्लड बैंक टीम डा. विनोद तंवर, नरेश सैनी ने सामाजिक संस्थाओं व रेडक्रॉस के सहयोग से 23 रक्तदान शिविर आयोजित किए। डॉ शैली ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सिविल अस्पताल में आयोजित इन सभी 23 शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। नरेश सैनी द्वारा रक्तदाताओं को रक्तदान करने से पूर्व सेनेटाइज किया गया। डॉ शैली ने बताया कि एकत्रित 508 यूनिट रक्त में से 472 यूनिट रक्त जरूरतमंदों को वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हस्पताल में इस समय भी 122 यूनिट रक्त स्टॉक में रखा हुआ है।

पैकेज में कुम्हार समाज के लिए स्पेशल राहत दे सरकार

कुरुक्षेत्र। प्रजापति जागरूक सभा के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार रंबा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुम्हार समाज का कारोबार ठप्प हो चुका है। ऐसे में सरकार को चाहिए कुम्हार समाज को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कुम्हार समाज के लोग भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। वे सिरसला रोड स्थित अपने कार्यालय में बातचीत कर रह थे। रामकुमार रंबा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित कुम्हार समाज के लोग बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। अब जब लॉकडाउन में सारे कारोबार ठप्प हो चुके हैं, ऐसे में बर्तन बनाने का कार्य भी लगभग बंद पडा है। ऐसे समय में कैसे कुम्हार समाज के लोग अपना गुजर बसर करें। पहले भी सरकार द्वारा तो कुम्हारों को आवे पंजावे की जगह देने की बात कह रखी है, लेकिन पंचायतें गांवों की राजनीति के चलते कुम्हारों को जमीन नहीं दे रहे हैं, जिससे बर्तन बनाने का काम ठप्प है। लॉकडाउन में भी रामकुमार रंबा पूरा सहयोग कर रहा है। रंबा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो राहत पैकेज की घोषणा कही है। इसमें कुम्हार समाज के लिए भी विशेष रूप पैकेज बनाया जाए, जिससे यह वर्ग भी अपने-अपने परिवार को ठीक से पाल सके।

नंगे पैर जा रहे मजदूरों को चप्पल बांटीं

सोनीपत। जिला प्रशासन के विशेष आग्रह पर गोविंद रसोई द्वारा जीटी रोड गन्नौर सब्जी व फल मंडी से सरकारी व्यवस्था द्वारा बसों द्वारा पलायन कर रहे करीब दो हजार प्रवासी मजदूरों को भोजन खिलाया और रास्ते के लिए भोजन के पैकेट वितरित किये। गोविंद रसोई द्वारा पलायन कर रहे करीब 20 मजदूरों व उनके बच्चों को चप्पल वितरित की, जोकि नंगे पैर जा रहे थे। खाना वितरित करने का कार्य जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में किया गया। प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरण में सेफ इंडिया फाऊंडेशन की गन्नौर इकाई से सतीश चौधरी व संदीप सिंघल का विशेष योगदान रहा। सेफ इंडिया फाऊंडेशन व रोटरी क्लब आफ सोनीपत एक्सीलेंस व महाराजा अग्रसेन समाज कल्याण समिति सोनीपत द्वारा संचालित गोविंद रसोई द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब व लाचार लोगों के बीच 4369 लोगों को खाना वितरित किया। इस कार्य में प्रवीण वर्मा, आकाश त्यागी, सन्नी, महेंदर अरोरा, अरविंद मित्तल, मनीष बंसल, अशोक गुप्ता, शालू त्यागी, राम कुमार जिंदल, टिका राम मित्तल, पवन अग्रवाल, सचिन गर्ग, सतपाल गुप्ता, राजेश गर्ग, प्रदीप खन्ना, विजय कुमार, अशोक गर्ग, संजय स्वामी, मनोज जैन, मनीष कुच्छल, चन्द्र भान, अनिपाल, राधा स्वामी सत्संग मंडल की सेवक मंडली और निरंकारी सेवा मंडल व श्रीराम शरणम् आश्रम आदि ने सहयोग दिया।

स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 से लड़ने वाले प्रथम पंक्ति के योद्धा

पूंडरी। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंडरी में आयुर्वेदिक दवाई वितरित की गई। जो कोविड-19 जैसी बीमारी के लिए भी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ती है। चिकित्सा अधिकारी डॉ महेश व डॉ ब्रिती गर्ग की मौजूदगी में आयुष विभाग की तरफ से डॉक्टर समीर मदान व डॉक्टर किरणदीप व आयुष चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु संशमनी वटी एवं अणु तेल की किट वितरित की। अतुल कुमार निदेशक आयुष विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार कोविड-19 में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु इनका सेवन करने का निर्देश दिया गया है।

निर्धारित नियमों के तहत मिलेगी लॉकडाउन में सभी को छूट : किरण

शाहाबाद मारकंडा। एसडीएम डा. किरण सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित एडवाइजरी सभी के लिए जारी की गई है। सभी अधिकारी, कर्मचारी व आमजन इस एडवाईजरी की पालना कर कोरोना वायरस को हराने में सहयोग करें।

वे शुक्रवार को अपने कार्यालय में शाहबाद मार्किट यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि शहर में सरकार व प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सारणी व नियमों के अनुसार ही दुकाने खोली जाएगीं। अगर कोई दुकानदार निर्धारित रोस्टर से अलग दुकान खोलेगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिठाई और बेकरी की दुकाने पूरे सप्ताह खोलने की छूट दी गई है। अन्य सभी दुकाने प्रशासन द्वारा निर्धारित नियम तथा चिन्हित बाएं और दाएं के हिसाब से ही खोली जाएंगी।

कोरोना वायरस से हुई सोनीपत में पहली मृत्यु

सोनीपत। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने सोनीपत जिला में कोविड-19 कोरोना वायरस से पहली मृत्यु की पुष्टि की है। विभाग ने ठरू गांव की एक महिला की मृत्यु का कारण कोरोना वायरस का पॉजिटिव होना बताया है। उपायुक्त डा. सिंह ने कहा शुक्रवार को सोनीपत जिला में एक नया पॉजिटिव मामला मिला है। नया केस मयूर विहार में मिला है। मयूर विहार का 40 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है। यह युवक दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कार्यरत है। इस एक नये पॉजिटिव केस के जुड़ाव से सोनीपत जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 132 हो गया है। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने कहा कि शुक्रवार की सायंकाल तक जांच के लिए 5005 सैंपल लिए जा चुके हैं।

महिलाओं ने गली में गंदा पानी भरने पर जताया विरोध

सीहमा में बीच रास्ते भरा कीचड़, ग्रामीणों का निकलना हुआ दुभर

पायनियर समाचार सेवा। नारनौल

खंड सीहमा के सबसे बड़े दोपालका व वाल्मीकि मोहल्ले में बीच रास्ते गंदा पानी व कीचड़ भरा होने से ग्रामीणों का निकलना दुर्भर हो रहा है। समस्या को लेकर शुक्रवार सुबह मोहल्ले की औरतों और पुरुषों ने पंचायत का विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर विरोध जताया।

रास्ते में भरे कीचड़ से परेशान सीहमा के महिला-पुरुष विरोध जताते हुए।

पूर्व सरपंच चंद्रकला, निर्मला, कृष्णा, सोना, संतरा, बीरमति, मास्टर कुलदीप, देवदत्त, महावीर जांगिड़, बिरेंद्र, आशु, सुरेंद्र आदि ने बताया कि दोपालका मोहल्ला व वाल्मीकि बस्ती जाने वाले गांव के मुख्य रास्ते के बीच में नालियां टूटी होने से रास्ते में पानी व कीचड़ भरा रहता है। कई बार बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे कीचड़ में गिरकर चोटिल हुए हैं। कीचड़ में मच्छर पनप रहे हैं जिसके कारण मलेरिया फैलने का अंदेशा है। समस्या के समाधान के बारे में कई बार सरपंच को मौका दिखाकर अवगत कराया जा चुका है लेकिन समस्या 5 साल से जस की तस है।

सीहमा सरपंच हरनाम सिंह ने बताया कि समस्या सही है लेकिन उसी मोहल्ले के कुछ लोग सड़क निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं। गत दिनों पंचायत ने समस्या समाधान के लिए टाइल-मिट्टी रास्ते पर गिरानी चाही तो एक दबंग व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। दबंगों ने पक्की नालियों पर घर के आगे स्लैब बनाकर नालियां बंद करके पानी रोका हुआ है। सीहमा बीडीपीओ देशबंधु ने बताया कि उनके ध्यान में यह समस्या नहीं आई है।

कैथल के ढांड में पिता व दो साल की बेटी पॉजिटिव

कॉलोनी सील, संपर्क में आए 21 लोगों के लिए सैंपल

पायनियर समाचार सेवा। कैथल

कालोनी में जांच करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम व बंद पड़ा बाजार।

कस्बा ढांड में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिस, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई और वाहनों का काफिला कस्बे में राधा कृष्ण कॉलोनी की तरफ दौड़ पड़ा। कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति अश्वनी कुमार व उसकी बेटी लगभग दो वर्षीय छवि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। जबकि उनके परिजनों को क्वारेंटाइन सेंटर ले जाया गया।

गौरतलब है कि ढांड निवासी अश्वनी कुमार जो दिल्ली में सीए (चार्टड अकाउंटेंट) का काम करता है लॉकडाउन के दौरान 10 मई को दिल्ली से अपने घर राधा कृष्ण कॉलोनी ढांड पर आया था और कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग को सैंपल दिए थे, जिसके बाद उसे 11 मई को हॉम क्वारेंटाइन किया था। शुक्रवार को पिता-पुत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबूलेंस से कुरुक्षेत्र के शाहबाद के आदेश मेडिकल अस्पताल में आइसेलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही परिवार को क्वारंटाइन करने के साथ ही राधा कृष्ण कॉलोनी सील कर दी है।

अश्वनी कुमार के संपर्क में आने वाले अश्वनी के पिता पवन कुमार, सरोज पत्नी पवन कुमार, सरूचि पत्नी अश्वनी कुमार, अभिषेक पुत्र पवन कुमार सभी परिवार के सदस्य सभी निवासी ढांड। घर में सफाई का कार्य करने वाला विक्की उर्फ विक्रम पुत्र रामकुमार वासी ढांड, नैतिक पुत्र रमन कुमार निवासी राधा कृष्ण मंदिर ढांड, दिनेश पुत्र सूरजभान निवासी ढांड, सुशील पुत्र रामकुमार निवासी ढांड, सतबीर नाई हाल निवासी ढांड के साथ उसके पुत्र, पुत्री व मां को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्वारंटाइन किया गया, क्योंकि अश्वनी ने सतबीर की दुकान पर कटिंग व शैव बनवाई थी। इसके साथ संपर्क में आए लोगों की जांच कर सूचि बनाई जा रही है।

ढांड एफसीआई के गोदाम में फैली दहशत : कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में संकट के बादल छाए हुए है, इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र रोड बाईपास स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में माल ढुलाई के लिए मालगाड़ी पहुंची तो जैसे ही मजदूरों ने एक डिब्बे को खोला तो उसमें से एक आदमी छुपा बैठा था। जिसकी सूचना तत्काल एफसीआई अधिकारियों ने पुलिस को दी। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम सफी बताया। उसने बताया कि वह कई दिनों से आजादपुर दिल्ली में फंसा हुआ था, जिसके कारण उसने वहां से वह मालगाड़ी के डिब्बे में छुपकर बाहर आया।

अधिकारियों की लापरवाही का खामयाजा भुगत रहे आढ़ती : ध्यानचंद

मंडी में बारिश से डैमेज हुए कट्टों से गेहूं की छटाई करने में लगे हैं आढ़ती

पूंडरी। अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आढ़ती बारिश से कट्टों में भीग चुकी गेहूं, जिसे खरीद एजेंसियों द्वारा रिजक्ट किया गया है और अब ले नहीं रही है। उसे आढ़ती कट्टों में से निकालकर सुखाने व कट्टों में जो गेहूं पुरी तरह डैमेज हो चुकी है, उसकी छंटाई कराने में लगे हुए है। गेहूं कट्टों के पहले बिल काट चुके आढ़ती अब डैमेज गेहूं की जगह साफ गेहूं खरीद करके कट्टों को भी पुरा करने में लगे हुए है, ताकि एजेंसियों को बिल के हिसाब से पूरे कट्टे गेहूं उठवाया जाए।

आढ़ती फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन के प्रधान ध्यानचंद, नरेश गर्ग, भूषण गर्ग, बबलू, सतीश कुमार, नीरज कुमार, राजेश व बलकार सिंह रोष प्रकट करते हुए बताया कि इस बार अधिकारियों की लापरवाही का खामयाजा आढ़ती भुगत रहे हैं। शुरू से ही सरकार की गेहूं खरीद नीति ही सही नहीं थी। रही सही कसर एजेंसियों के खरीद अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी करके पूरी कर दी। 20 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई। अधिकारियों द्वारा खरीद करने के बाद तीन-तीन दिनों तक बारदाना नहीं दिया गया, उसके बाद 10 से 15 दिनों तक गेहूं का उठान नहीं किया गया, जबकि हर वर्ष मौसम खराब होता है और बारिश भी होती है, लेकिन अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर देरी से उठान और वो भी धीमी गति से शुरू किया।

मौसम खराब होने पर बारिश होते ही मंडी में पड़े लगभग 3 लाख कट्टे गेहूं बारिश में भीग गये। जो कट्टे नीचे में पड़े हुए थे, उनमें बारिश का पानी भर जाने से जरमीनेट होकर डैमेज हो गये। जिससे आढ़तियों को अब तक कट्टे संभाले व उठान करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लॉकडाउन 4 : केंद्र से मांगी मेट्रो चलाने की इजाजत

सीएम ने भेजे जनता के सुझाव, परिवहन मंत्री गहलौत बोले- हम तैयार, अंतिम फैसला लेगी केंद्र सरकार

● चुनिंदा रूटों पर चलाई जा सकती हैं ट्रेन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आगामी 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण से दिल्ली मेट्रो रफ्तार भर सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम कुछ प्रतिबंधों के साथ चुनिंदा कॉरिडोर पर अपनी ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने कहा कि मेट्रो संचालन को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा।

सोमवार से परिचालन के लिए मेट्रो पूरी तरह तैयार है। वहीं डीएमआइसी के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल मेट्रो में यात्रा करने के दौरान विस्तृत प्रोटोकॉल को मीडिया और जनता के साथ साझा किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के सूत्रों के अनुसार, लॉकडाउन-4 में मेट्रो पूरी तरह बदली नजर आएगी। मेट्रो संचालन के साथ ही कई तरह के नए नियम जोड़े जाएंगे, जिनका पालन हर मेट्रो यात्री के लिए जरूरी होगा।

मेट्रो में सफर के दौरान हर किसी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क वाले यात्री को स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्टेशन पर जब यात्री प्रवेश करेगा तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बुखार, सर्दी-जुकाम होने की सूरत में यात्री को मेट्रो स्टेशन के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा।

मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक, 18 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान मेट्रो के हर कोच में बैठने की व्यवस्था इस तरह होगी कि शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन हो। ट्रेन के प्रत्येक कोच में दो सीट के बीच में एक स्टीकर लगा होगा, जिस पर नहीं बैठने की हिदायत लिखी होगी।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भी अपनी ओर से एक योजना बनाकर प्रस्तुत की है। इसके आधार पर वह यात्रियों की जांच करेगी।

दिल्ली मेट्रो चलने की संभावनाओं के बीच परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो संचालन को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम मेट्रो चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मेट्रो का संचालन होगा, पूरी एहतियात बरती जाएगी। यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। मेट्रो कोच के साथ-साथ स्टेशनों को भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इस दौरान डिजिटल लेन-देन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कोशिश होगी रुपये का लेनदेन न हो।

गहलोत में यह भी बताया कि मेट्रो के संचालन के दौरान अगर किसी स्टेशन पर भीड़भाड़ अधिक होगी तो लोगों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। इस दौरान सिर्फ मुख्य मेट्रो स्टेशन ही खुलेंगे, बाकी को बंद रखा जाएगा, जिससे मौजूद कर्मचारियों का सदुपयोग अधिक से अधिक कर सकें। गौरतलब है कि मेट्रो संचालन को लेकर शुक्रवार को कैलाश गहलोत, दिल्ली मेट्रो रेल निगम व दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें सीमित संख्या में संचालन शुरू करने को लेकर रणनीति तय हुई।

बॉर्डर पार करने को गाजीपुर में जुटे सैकड़ों प्रवासी मजदूर

फोटो: रंजन डिमरी

विशेष रेल गाड़ियों से रेलवे स्टेशनों पर उतरे प्रवासी मजदूर सपरिवार दिल्ली तो पहुंच गए लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के बाद इन्हें यहां भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए स्टेशन से डीटसी बसों का इंतजाम किया है परंतु आने वालों की संख्या के हिसाब से यह पर्यापत नहीं। नतीजा साधनों के अभाव में मजदूरों की भीड़ गाजीपुर पर जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग को टूटता देखकर पुलिस ने उन्हें ट्रकों में बैठाकर बॉडर पार करने के लिए रवाना किया।

नाले में कचरा निस्तारण जवाब दे सरकार : कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सेप्टिक टैंकों से एकत्रित अपशिष्ट को शोधित किए बिना ही नजफगढ़ नाले में छोड़ दिया जाता है जो बाद में यमुना नदी में बह जाता है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि नजफगढ़ के संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में सेप्टिक टैंकों से एकत्र किया गया अपशिष्ट किसी नाले में या खुली नालियों में न छोड़ा जाए। मामले की सुनवाई 27 मई को होगी।

छटपटाती दिल्ली-कोरोना के 425 नए मामले, 19 की मौत

● दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगभग 9 हजार, 123 की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 123 हो गई है जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8854 हो गई है।

आंकड़ों के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली में 472 नए मामले आए थे जो एक दिन में सबसे अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से 123 लोगों की मौत हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन

मृतकों के आंकड़े में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी मौत की प्राथमिक वजह कोविड-१९ है। ये आंकड़े विभिन्न अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर मरने वालों की समीक्षा करने वाली समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। बृहस्पतिवार को दिल्ली में मृतकों की सं या 115 थी और 8,470 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को 425 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की सं या बढ़कर 8,895 हो गई है।

आंकडें नहीं बढ़ोतरी दर को देखें : जैन

कोरोना के रोजाना सैंकड़ो नए मामले सामने आ रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जहां तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की बात है, तो हमें इसके आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए बल्कि इसके बढ़ने के प्रतिशत को देखना चाहिए। इसके वृद्धि की दर करीब 5 प्रतिशत था। अभी यहां कोरोना मरीजों के बढ़ने का दर 5 से 5.5 प्रतिशत है। कभी इसके बढ़ने की दर 20 प्रतिशत थी। फिर 12 हुई और अब 5-6 प्रतिशत है।जैन ने कहा कि पहले उम्मीद थी कि गर्मी शुरू होगी तो कोरोना चला जाएगा। उन्हें भरोसा था कि एक मई इसका आखरी दिन होगा और हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगाता है कि यह जाने वाला नहीं है।

शराब पर कोरोना शुल्क वसूली पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क वसूलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे।

क्वॉरंटीन सेंटरों से सेहतमंद जमातियों को मिलेगी छुट्टी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

क्वॉरंटीन सेंटरों से सेहतमंद जमातियों को छुट्टी मिलेगी। उच्च न्यायालय को शुक्रवार को जानकारी दी गई कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने तबलीगी जमात के उन सदस्यों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने जरूरी क्वॉरंटीन की अवधि पूरी कर ली है और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं।

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि तबलीगी जमात के करीब 3300 सदस्यों को रिहा किया जाए जिन्हें करीब 40 दिनों से अलग-अलग आइसोलेनशन केंद्रों में रखा गया है और कोविड-१९ की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्यों दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के ऐसे सदस्यों को रिहा करने का निर्णय कर लिया है जिनमें लक्षण नहीं हैं।

चार और नए मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि

● नोएडा में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या हुई 242

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

चार नए मरीजों की पुष्टि के साथ जपनद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 242 पर पहुंच गई। वहीं सेक्टर 150 निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे।

शुक्रवार को जिला प्रशासन की तरफसे जारी रिपोर्ट के मुताबिक चार नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों में सेक्टर 12 निवासी 78 वर्षीय वृद्ध भी शामिल हैं। वहीं फेस टू स्थित नंगला गांव में 21 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट में सेक्टर.5 का रहने वाले 22 वर्षीय युवक और 41 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ सुनील दोहरे ने बताया कि शुक्रवार को दस मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है।

डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में पांच महिला मरीज शारदा अस्पताल की हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों में दस साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं 76 वर्षीय वृद्ध और 36 वर्ष व्यक्ति को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नोएडा के दो मरीज जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा था उन्हें भी शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। सेक्टर 150 निवासी वृद्ध भी हार गए। बताया जा रहा है कि पहले से ही उन्हें कैंसर था और कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन के नियम बदले : डीएम

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नए मानकों के अनुसार सारे कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण किया है।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नए कंटेनमेंट जोन की सूची भी जारी कर दी है। नए मानकों के अनुसार कई आवासीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया गया है। अब नए मानक के मुताबिक, अंतिम संक्रमित मरीज की सैंपलिंग डेट के 21 दिन बाद तक उसके आवासीय क्षेत्र में सीलिंग लागू रहेगी। अभी तक जिला प्रशासन इसी परिभाषा का पालन कर रहा था, अब नए मानक माने जाएंगे।

बिजली विभाग ने भेजा टेंशन का बिल भारी रकम देख उड़ गए होश

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

लॉकडाउन के दौरान औसत तौर पर बिजली के बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की टेंशन बढ़ गई है।

बिजली विभाग ने भरा गया बिजली का बिल समायोजित नहीं कर बढ़े हुए बिल भेजकर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता समझ नहीं पा रहे है कि गलत बिलों को कहां से ठीक कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान बिजली विभाग ने औसत बिल जमा करने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बिजली विभाग का कहना था कि जो बिल पहले महीने आया है लॉकडाउन के दौरान उसे जमा करा दो। बाद में युनिटी की रीडिंग के हिसाब से बिजली की बिल जारी किया जाएगा।

इसी प्लान को लेकर सभी लोगों ने बिजली विभाग की डिमांड के आधार पर बिजली का बिजल जमा करा दिया। अब बिजली विभाग एक महीने पहले जमा कराया गया बिजली का बिल समायोजित नहीं कर पूरा बिल वसूलने के लिए बिलिंग कर रहा है। बिजली विभाग ने एक नई टेंशन आम लोगों को दे दी है।

लॉकडाउन में भी निगम ने खोले काउंटर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

नगर निगम के केश काउंटर पर आज से टैक्स जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके लिए सैनिटाइजर और सॉशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है।

लॉकडान के दौरान नगर निगम ने भवन स्वामियों को अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कई प्रयोग किए। पहले सभी उपभोक्ताओं से कहा गया है लॉकडाउन के दौरान वह ऑन लाइन हाउस, सीवर और वॉटर टैक्स जमा करा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी वेबसाइट और बैंक के जरिए ऑन लाइन टैक्स जमा कराने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। नगर निगम को इससे काफी झटका लगा। दरअसल नगर निगम में ऑन लाइन टैक्स जमा करने के लिए किसी ने भी कोई रूचि नहीं दिखाई।

इसी को लेकर अब निगम प्रशासन को लॉकडाउन के दौरान टैक्स जमा सीधे कैश काउंटर की सुविधा दी गई है। आज से ही लोगों ने टैक्स जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

टैक्स जमा कराने वालों को लॉकडाउन की गाइड लाइन के हिसाब से ही काउंटर पर लाइन में लगने से पहले उन्हें सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए जा रहे है। इसके बाद काउंटर पर पैसा जमा कराया जा रहा है।

गर्मी में दिल्ली की प्यास बुझाने का एक्शन प्लान

●जलबोर्ड ने सामने रखा सरकार की तैयारियों का ब्योरा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

गर्मियों में राजधानी के लोगों को पानी आपूर्ति की परेशानी नहीं हो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने समर एक्शन प्लान जारी किया।

गर्मियों में दिल्ली की अंदर पानी की मांग बढ़ जाती है इस कारण देखा गया कि कई इलाकों में पानी की लेकर घमासान मच जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि कोरोना वायरस में पानी की स्वच्छता की महत्ता और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस समर प्लान में जलशोधन से संयंत्रों के रखरखाव का कार्य पूरा हो चुका है।

अब केवल गंभीर परिस्थितियों में ही इनकों बंद करने की जरूरत पड़ेंगी। वहीं पुराने पंपों, पैनलों और बिजली के उपकरणों को भी बदल दिय गया है ताकि जल अपूर्ति में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जल उपचार संयंत्रों के अनुरक्षण पानी की कमी वाले इलाकेंमें जल आपूर्ति की शिकायतों के निपटारे में तीव्रता एवं कुशलता लाने का कार्य कर रहा है। चड्ढा ने कहा कि जल निकायों का पुर्नरूद्धार झीलों के सृजन, भूजल रिचार्ज द्वारा ही पानी की कमी को कुछ हद कम किया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड का समर एक्शन प्लान , जल तकनीकी में अतुलनीय नवीनता लाने के लिए जिससे पानी संरक्षण में सहायता मिलेगी।

हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि पानी की आपूर्ति मांग से अधिक हो, हमें इस पर भी बात करनी होगी कि कहां से हम पानी लें, कैसे उसका उपयोग करें। बोर्ड ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति क लिए 4 नए भूमिगत जलाशयों का काम पूरा कर दिया हैं। यह जलाशय पश्चिम कमल विहार, सोनिया विहार, मुंडकातथा महिपालपूर में है। जिससे पश्चिमी तथा मध्य दिल्ली के इलाकों में पानी आपूर्ति में सुधार हुआ है। पानी के कमी वाले इलाकों में 254 अतिरिक्त टयूब बैल लगाए गए हैं, जिससे लगभग 4910 टयूब वैल हो गए है। उससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की जा सकेगी।

नई झीलों का सृजन

1. द्वारका जल उपचार संयंत्र
2. तिमारपुर आक्सीडेशन पांड
3. रोहिणी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
4. निलोठी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट
5. पप्पन कला ट्रीटमेंट प्लांट
6. सतपुला प्लांट

उत्तर प्रदेश सरकार

अपील

वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से उबरने के लिए पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर प्रदेश के सभी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं युवाओं की सुरक्षित घर वापसी के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है।

अभी तक, उत्तर प्रदेश के 13.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं अन्य लोगों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों द्वारा उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है।

प्रवासी एवं प्रदेश में रह रहे कामगारों एवं श्रमिक भाई-बहनों से मेरी विनम्र अपील है - ''घर वापसी के लिए पैदल न चलें। साइकिल, दोपहिया वाहनों/ट्रकों से भी यात्रा न करें। ज्यादा लम्बी दूरी चलने से शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है और आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

आप जहां हैं, धैर्यपूर्वक वहीं रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी की वापसी के लिए नि:शुल्क ट्रेनों की व्यवस्था की है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जिस राज्य में हैं, वहां के स्थानीय प्रशासन/नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें, ताकि इन ट्रेनों के माध्यम से आपकी सुरक्षित घर वापसी हो सके।''

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

किसी भी सहायता हेतु सम्बन्धित प्रदेश के लिए नामित नोडल अधिकारी से या इण्टीग्रेटेड राहत कन्ट्रोल नं. 1070 या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नं. 1076 पर सम्पर्क करें। प्रवासी नागरिक घर वापसी हेतु www.jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण करें।

मुख्यमंत्री ट्विटर हेल्पलाइन : @CMHelpline1076

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

कोरोना वॉरियर स्टाफ नर्स बोली

कोई बीमारी सेवा के जज्बे में नहीं बन सकती बाधा

कोरोना की जंग लड़कर लौटी स्टाफ नर्स पूनम सहराय से विशेष बातचीत

देश में नर्सों की कमी दूर करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की जरूरत

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

पूनम सहराय।

कोरोना से जंग जीतकर गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल की नर्सिंग सिस्टर (स्टाफ नर्स) अपने घर लौट चुकी हैं। कोरोना योद्धा के रूप में उनके जज्बे को सभी ने सेल्यूट और स्वागत किया। कोरोना बीमारी से जूझने के बाद अब नए जोश के साथ उन्होंने अपने आगे के सफर को, सेवा को शुरू करने की बात कही है।

स्टाफ नर्स पूनम सहराय ने कहा कि कोई बीमारी हमारे सेवा के जज्बे को कम नहीं कर सकती। हमारा मनोबल नहीं गिरा सकती। बेशक कुछ समय के लिए, कोरोना ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। वे अब और अधिक जोश और जज्बे के साथ मरीजों की सेवा करेंगी। उनका कहना है कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनको फॉलो करें। उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से कहा कि देश हेल्थ सेक्टर में बेहतरी के लिए स्टाफ नर्सों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए तीन बातों का हमेशा पालन करें। पहली मास्क लगाना, दूसरी सोशल डिस्टेंस और तीसरी अच्छे से हाथ धोना। यह काम नियमित तौर पर हमें करने हैं।

कोरोना वॉरियर्स पर हमलों पर जताई चिंता

उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्हें दुख है कि देश में कई जगह पर इन पर हमले किए गए। जो कि सही नहीं है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि ऐसा ना करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन भी इस बात को कह चुका है कि कोरोना इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लंबे समय तक और सकता है जीवनभर ही हमें कोरोना के साथ जीना पड़े। इसलिए हमें खुद में कुछ बदलाव लाने होंगे।

नर्सिंग में आकर पिता का सपना किया साकार

नर्सिंग क्षेत्र में अपने के पीछे की वजह पूनम सहराय अपने पिता चंद्र सिंह मलिक का सपना बताती हैं। 18 साल की उम्र में शादी हो गई, तो पिता और बेटी का सपना एक तरह से अधूरा ही रह गया। लेकिन जिसके दिल में सेवा की भावना हिलौरें ले रही हों तो उसके बंद हुए रास्ते किसी न किसी तरह खुल भी जाते हैं। पूनम बताती हैं कि उनके पति विनय कुमार ने खुद उनसे नर्सिंग कोर्स करने को कहा। उसी दिन से पूनम ने अपने पिता और पति दोनों के सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान से मेहनत करते हुए कामयाबी हासिल की। वर्ष 2006 में गुरुग्राम से नर्सिंग कोर्स किया और वर्ष 2008 में उन्हें हरियाणा में सरकारी जॉब मिली। रेवाड़ी में एक साल तक जॉब करने के बाद उनका तबादला गुरुग्राम में हो गया। तब से लेकर अब तक वे यहीं पर सेवाएं दे रही हैं।

ई-एजुकेशन ले रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों की ई-पीटीएम ले रहे अधिकारी

गुरुग्राम। हेलो, आपके बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ इस तरह से शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के अभिभावकों से ई-पीटीएम के माध्यम से रोजाना जानकारी ले रहा है। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उसके बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधे अभिभावकों से संपर्क करके फीडबैक लिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के कार्य पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ना केवल नजर रख रहे हैं, बल्कि शिक्षकों का इस दिशा में मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी इंदु बोकन का कहना है कि लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों के बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के तरीके को आजमाया गया है। यह तरीका पहली बार इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसके बारे में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से लगातार फीडबैक लेकर प्रणाली में सुधार करने के प्रयास रहते हैं। उन्होंने कहा कि फीडबैक में जहां कहीं भी कमी नजर आती है, उसे दूर करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स तथा अन्य शिक्षाविदों से मदद ली जाती है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा ई-पीटीएम का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। गुरुग्राम जिला में प्रदेश में सबसे पहले ई-पीटीएम करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

ट्रेन में रवानगी से पूर्व दृष्टिहीन बच्चों के साथ पुलिस ने काटा केक

गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर दृष्टिहीन बच्चों के साथ केक काटते पुलिस अधिकारी।

गुरुग्राम। स्थानीय रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन में सवार होकर जाने वाले दृष्टिहीन बच्चों के लिए आज का दिन खास रहा। एक तो वे अपने गांव जा रहे थे और दूसरी वजह यह रही कि जैसे ही वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो गुरुग्राम पुलिस ने उनके साथ मिलकर केक काटा।

गुरुग्राम पुलिस के उपायुक्त सुमेर सिंह के नेतृत्व में 8 दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटने और फिर उसका वितरण ट्रेन में सवार अन्य बच्चों में भी करने का भाव इन बच्चों के लिए अविस्मरणीय हो गया। गुरुग्राम पुलिस की यह भावना इन दिव्यांग बच्चों के लिए तो यादगार लम्हों के तौर पर याद रहेगी। शुक्रवार को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बिहार के दरभंगा के लिए स्पेशल ट्रेन भेजने का शेड्यूल था। इस स्पेशल ट्रेन में जाने वाले यात्रियों के लिए भी शुक्रवार का दिन स्पेशल रहा। एक ओर जहां हरियाणा सरकार की ओर से सभी यात्रियों के लिए मुफ्त टिकट, खाना, पानी की बोतलों आदि की व्यवस्था की गई थी, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के साथ जाने वाले बच्चों में बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट वितरित किए गए। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से आज लगातार तीसरे दिन प्रवासी नागरिकों को उनके पैतृक गांव सकुशल पहुचाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। यह ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 2:15 बजे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जिसकी 20 बोगियों में 1200 यात्री बिहार के दरभंगा तक पड़ने वाली जगहों पर अपने घरों को गए हैं। इस स्पेशल ट्रेन में बिठाने समय यात्रियों के साथ जा रहे बच्चों को मिठाई देते हुए सेक्टर-5 पुलिस थाने के एसएचओ वेद प्रकाश ने बताया कि प्रवासी नागरिकों के लिए जाने वाली ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रोजाना फूड पैकेट दिए जा रहे हैं।

शुक्रवार को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से 1200 यात्रियों को लेकर बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन

संक्षिप्त समाचार

आजाद भारत का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज : अनुराग

गुरुग्राम। वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिलाने के लिए भले ही दुनिया भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक किसी कारगर वैक्सीन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कोरोना से उत्पन्न आर्थिक मंदी की मार से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन ढूंढ निकाली है। गत 12 मई को मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10 फीसद है। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज। मोदी की इस घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व आइआरएस अनुराग बख्शी ने कहा कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से चुनौतियों भरे साहसिक गेम चेंजिंग फैसलों के लिए मशहूर हैं, जिनमें नोटबंदी, जीएसटी, जनधन योजना, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, किसानों-कामगारों को पेंशन, बालाकोट, धारा 370, तीन तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे फैसलों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया, अपितु देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी। अनुराग बख्शी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जान है तो जहान है और फिर जान-जहान से भी आगे बढ़ते हुए 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, सपने और जिम्मेदारी को पूरा करने का रोड मैप देश की जनता के सामने पेश किया।

कोरोना से बचाव के लिए डाक्टरों ने बांटी आयुर्वेदिक दवा

नूंह। जिले के फिरोजपुर के अंतर्गत गांव पाठखोरी में कोरोना से बचाव के लिए शुक्रवार को डाक्टरों द्वारा लोगों को आयुर्वेदिक दवा बांटी गई साथ में लोगों को घरों से बाहर न निकलने व सोशल डिस्टेंस के प्रति जागरूक किया गया। ताकि लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। पाठखोरी गांव में तैनात आयुर्वेदिक डाक्टर जीनत ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ आयुर्वेदिक दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक दवा के सेवन से कोरोना से बचा जा सकता है। वहीं डाक्टर जीनत ने ग्रामीणों को दवा बांटते समय मुंह पर मास्क लगाने, हाथों को साबुन से बार-बार धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी लोगों को जागरूक किया समाजसेवी साजिद हुसैन ने भी आयुर्वेदिक डाक्टरों का सहयोग किया।

नूंह जिले से अब तक 550 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया घर

नूंह। नूंह जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास जारी है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सरल पोर्टल पर अब तक लगभग 4 हजार प्रवासी श्रमिकों ने अपने घरों को जाने के लिए आवेदन किया हुआ है। जिनमें से 550 मजदूरों को उनके प्रदेश भेजा जा चुका है। उपायुक्त पंकज ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी को उनके गृह क्षेत्र में भेजने के समुचित इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न स्थानों से चलने वाली विशेष ट्रेनों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की गई है। उपमंडल अधिकारी नागरिक प्रदीप अहलावत ने बताया कि शुक्रवार को सुबह बस स्टैंड नूंह व तावडू के सरल पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर फरीदाबाद बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें सभी को मास्क, खाना आदि व उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद भिजवाया जा रहा है।

गुरुग्राम में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए

गुरुग्राम। शुक्रवार को जिला में कोरोना के 9 केस पॉजिटिव आए। इस तरह से यहां कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 179 हो गई है। जिसमें से 90 नेगेटिव यानी ठीक हो चुके हैं। पॉजिटिव केसों में 6 राजीव नगर क्षेत्र से हैं। इसके साथ ही राजीव नगर हाई रिस्क जोन में आ गया है। एक केस गांधी नगर से है और एक केस हरि नगर से है, जो कि खांडसा सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेता है। इनके अलावा एक केस बसई एन्क्लेव क्षेत्र से है।

मकान मालिक जबरन खाली करा रहा मकान, लूट का आरोप

सोहना। भोंडसी में मकान मालिक ने परिजन सहित 4, 5 पड़ोसियों के साथ मिलकर बेवजह किराएदार वृद्ध मां को पीटा। आरोप है कि आरोपी एक रुपये सहित लाखों रुपये के जेवरात ले गए। भोंडसी से गढ़ीबाजीदपुर को जाने वाले परमिट मार्ग पर भोंडसी निवासी कविता पत्नी देवेन्द्र ने अपना मकान पांच वर्ष के लिए किराए पर दिया था। किरायदार मुकेश चौधरी पत्नी प्रदीप चौधरी ने पुलिस को बताया कि उसने मकान पांच साल एग्रीमेंट के तहत किराए पर लिया था। जिसमें उसने 13 लाख रुपये खर्च करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र एवं संस्था शुरू की थी, लेकिन मकान मालिक के मन में बेइमानी आ गई और उसने कई बार घर में घुसकर लूटपाट भी की। जिसका उसने भोंडसी थाने में मामला दर्ज कराया था। मुकेश चौधरी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वह और उसका पति गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में मकान मालिक के खिलाफ शिकायत करने गए थे। उनके जाने के बाद कविता व उसका पति देवेन्द्र पड़ोसी इंद्रा देवी, बेटा निशान्त और 4, 5 अन्य लोगों को लेकर घर में ताले तोड़ घुस गया। उसकी वृद्ध मा से मारपीट की और घर से जरूरी कागजात, एक लाख 30 हजार रुपये और लाखों के जेवरात ले गए।

कोरोना काल में 8वीं कक्षा का छात्र ईशान बना सेवा की मिसाल

फंड जुटाकर वंचितों को राशन पहुंचाने में लगा है ईशान जैन

अब तक 500 परिवारों को दे चुका है राशन

प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

ईशान जैन।

गुरुग्राम। कोरोना के कारण लॉकडाउन में बेशक बच्चों ने मौज-मस्ती करके समय बिताया हो, लेकिन 8वीं कक्षा के छात्र ईशान जैन ने इस समय का एक तरह से जनसेवा करके सदुपयोग किया। अपने प्रयासों से उसने फंड एकत्रित किया और मजदूरों को राशन आवंटित करना शुरू किया। अब तक 500 लोगों तक वह सहायता पहुंचा चुका है।

गुरुग्राम के डीएलएफ मैग्नोलियाज सोसायटी के रहने वाले नितिन जैन के पुत्र ईशान जैन की उम्र मात्र 13 साल है और वह हेरिटेज एक्सपेरियंसल लर्निंग स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र है। लॉकडाउन के साथ ही उसने खुद को जनसेवा के लिए तैयार किया। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ा। इसमें दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। सभी से अपना आइडिया सांझा किया और फंड देने की रिक्वेस्ट की। कहते हैं अगर आप सही काम के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी कमी नहीं छोड़ता। इसलिए लोगों ने ईशान के इस प्रयास को सराहा भी और मदद भी की। ईशान ने उन लोगों तक राशन पहुंचाने का काम शुरू किया, जो कि रोजाना कमाते, रोजाना खाते थे। यानी उनके पास अब कोई साधन नहीं था। करीब 500 परिवारों तक ईशान ने राशन पहुंचाकर उनकी भूख को मिटाया है। राशन के साथ लोगों को बना हुआ खाना भी दिया जा रहा है। सीधे इन परिवारों को राशन, खाना उपलब्ध कराने के साथ ईशान ने सिविल डिफेंस के साथ भी मिलकर यह काम किया है। सिविल डिफेंस को उसे मास्क, किट आदि भेंट की है। ईशान जैन का कहना है कि राशन, खाने के अलावा अब वह लोगों को मास्क आदि देने का काम शुरू कर रहा है।

मेवात की मस्जिदों, मजारों, मदरसों में चल रही हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे

विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हरियाणा के मेवात क्षेत्र में हिन्दुओं की प्रताड़ना पिछले कई वर्षों से निरंतर की जा रही है।

गोहत्या, धर्मान्तरण, संतों का अपमान, महिलाओं का शील भंग एवं अपहरण, हिन्दुओं की जमीन पर कब्जे करने के अलावा अवैध मस्जिदों, मजारों व मदरसों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। जो कि चिंता का विषय है। यह बात उन्होंने यहां पत्रकार वार्ता करके कही। उन्होंने कहा कि मेवात के मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच की गई है। कमेटी में जनरल जीडी बख्शी, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और वरिष्ठ एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा को शामिल हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सम्पूर्ण मेवात में चल रहे हिन्दू विरोधी व राष्ट्र विरोधी षडयंत्र का खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि आज सम्पूर्ण मेवात में हिन्दू का रहना दुभर हो गया है। वह वहां से पलायन का विचार कर रहा है। पिछले 25 वर्षों में 50 गांव हिन्दू शून्य बन चुके हैं।

580700 क्विंटल गेहूं व 295820 क्विंटल हुई सरसों की खरीद

गुरुग्राम। जिला की अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर अब तक 5 लाख 80 हजार 700 क्विंटल गेहूं व 2 लाख 95 हजार 820 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। सभी मंडियों व खरीद केंद्र से नियमित उठान के निर्देश संबंधित खरीद एजेंसी को दिए गए हैं। उपायुक्त अमित खत्री के निर्देशानुसार कोविड-19 से बचाव के साथ ही लॉकडाउन का पालना प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक के मुताबिक गुरुवार शाम तक गुरुग्राम जिला की मंडियों में 6 हजार 970 क्विंटल गेहूं तथा 10 हजार 940 क्विंटल सरसों की खरीद हुई है।

श्रमिकों के वेतन के लिए पैकेज में कुछ नहीं

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने कही यह बात

एचपी यादव।

एफएमएसएमई सेक्टर की उम्मीदों के अनुसार सरकार ने अप्रैल और मई-2020 के महीने के लिए श्रमिकों के वेतन व मजदूरी के भुगतान के लिए इस पैकेज में कोई प्रावधान नहीं किया है। मंदी और लॉक डाउन की बंदी के कारण विषम परिस्थिति से जूझ रहे उद्योग और व्यापार प्रतिष्ठानों की प्रमुख मांगों में से यह एक था। वित्त मंत्री द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाना निराशाजनक है। यह बात एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष एचपी यादव ने वित्त मंत्री द्वारा कोरोना को लेकर जारी किए गए एमएसएमई सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज पर कही।

एचपी यादव का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर देश के 11 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है जिसे भारत सरकार भी स्वीकार करती है। लेकिन जिस राहत पैकेज की घोषणा की गई है उससे सीधे एमएसएमई सेक्टर को अपेक्षित मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि अगर 2 महीने के वेतन और मजदूरी के भुगतान की घोषणा सरकार ने की तो श्रमिकों को वापस काम पर बुलाना मुश्किल होगा। इससे बेरोजगार श्रमिकों का पलायन बंद नहीं होगा। नतीजा यह निकलेगा कि उद्योग धंधे बंद रहेंगे और निकट भविष्य में बेरोजगारी चरम पर होगी। उनका मानना है कि अधिकतर कम्पनियां दयनीय स्थिति में हैं और इसे पुनर्जिवित करने के लिए आर्थिक पैकेज में लॉक डाउन के दौरान के वेतन को भी समावेश करना जरूरी है। अन्यथा उद्योग और व्यापार के लिए श्रमिकों की कमी का सीधा असर रोजगार, रेवेन्यू, निर्यात और आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई को कोलैटरल फ्री ऋण के लिए पात्र बनाया है। यह सकारात्मक कदम है, लेकिन अगले चार वर्षों के लिए यह ब्याज मुक्त होना चाहिए। साथ ही बैंकों को भी बिना किसी देरी के ऋण जारी करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव बताता है कि ज्यादातर योजनाएं जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं हो रही हैं। सरकार की घोषणाओं के अनुरूप वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को सुविधा नहीं देती हैं और अपनी शर्तें थोपती है।

लॉकडाउन में खरीदारी से बच रहे लोग

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोग।

शुक्रवार को लॉकडाउन के बीते 53 दिनों के बाद सोहना में बाजार धीरे-धीरे खुलने लगा है, लेकिन बाजारों में लॉकडाउन काल होने के कारण ग्राहकों का टोटा बना हुआ है। दुकानदार सुबह दुकान खोलने के बाद ग्राहकों को पूरा दिन इंतजार करता रहा।

शुक्रवार को सोहना के बाजारों में स्थित सी श्रेणी में आने वाली गिफ्ट, टॉय शॉप, बैग और सूटकेस शॉप, आप्टीकल, रेडीमेट गारमेंट अथवा क्लोदिंग व बर्तन व कोकरी शॉप खुली। लॉकडाउन के 53 दिन बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों की साफ सफाई करके के बाद खोली और कामकाज को पहले की भांति संभाल लिया, लेकिन बाजारों में ग्राहकों की चहल कदमी कम देखी गई। दुकानदार अपनी आंखों से ग्राहकों का इंतजार करता नजर आया।

क्या कहना है दुकानदारों का

रेडीमेट कपड़ा बेचने वाले दुकानदार नरेश गुप्ता का कहना है कि अभी बाजारों में पहले की भांति रौनक आने में समय लगेगा। कोरोना काल के भय से ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने के लिए कम निकल रहा है। बर्तन दुकानदार प्रकाश का कहना है कि ग्राहक जब तक लॉकडाउन देश में रहेगा। तब तक घर से बाहर कम निकलेगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बीते 53 दिन घर में रहकर काटने मुश्किल हो गए थे। अब सप्ताह में दो बार ही सही। कम से कम घर से बाहर निकल अपनी रोजी रोटी को संभाल तो रहे हैं।

क्या कहते हैं ग्राहक

ग्राहक मनोज का कहना है कि बाजार से सामान भीड़ में जांच खरीदना जल्दबाजी होगी। क्योंकि अभी भी कोरोना से अपने आपको बचाने की आवश्यकता है। बिजली के पंखा, कूलर, कूलर की घास और एसी की मरम्मत करानी आवश्यक है। जो कॉल करके मैकेनिक को बुलाया लिया जाता है। ग्राहक ओमबीर का कहना है कि बाजार में जाकर रुपये का लेन-देन करना, दुकानदार के यहां पर जाकर सामान खरीदना यह सब से दूरी बनाने की आवश्यकता है।

कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहा मेवात

नूंह। प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला मेवात अन्य जिलों की अपेक्षा कोरोना से जंग जीतने में सफल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नूंह जिले में मरीजों की संख्या 61 हो गई थी। अब तक 3839 संदिग्ध लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3669 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 61 कोरोना संक्रमित में से 57 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उप सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी कोरोना डाक्टर अरविंद ने बताया कि 3 मरीजों को अभी इलाज चल रहा है तथा एक मरीज घर पर एडवांस में रखा गया है और 109 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकि है। उन्होंने बताया कि लोगों की जांच का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही है तथा संदिग्ध लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा डाक्टरों की टीम लोगों को घरों से बाहर ना निकलने, मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस के प्रति भी जागरूक कर रही हैं।

सोहना में धड़ल्ले से चल रहे निजी अस्पताल

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

सुन्दरी।

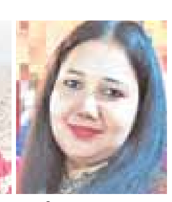
सीमा डागर।

राजकुमार।

हरीश।

शहर में दिन प्रति दिन निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय निवासी निजी अस्पतालों की मान्यता को लेकर जांच और मनमर्जी से वूसली जाने वाली उपचार के नाम पर फीस की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं।

साइबर सिटी गुरुग्राम, बादशाहपुर, पलवल, और फरीदाबाद की तर्ज पर सोहना में भी निजी अस्पतालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। उपचार के नाम पर निजी अस्पताल संचालक रोगियों से मनचाही फीस वसूल कर रहे हैं। जिससे उपचार के नाम पर आम लोगों की जेब पर निजी अस्पताल मालिक कैंची चला रहे हैं। निजी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम फीस तो ली जाती है। लेकिन उपचार के दौरान रोगी की मौत होने पर निजी अस्पताल के डॉक्टर से लेकर मालिक अपने आपको सुरक्षित बचा लेते है। जिसका कारण निजी अस्पताल मालिक व संचालक रोगी के परिजनों को उपचार न कराने के नाम पर भय दिखाते हुए मोटी रकम वसूली कर लेते है। जिसको लेकर निजी अस्पताल संचालकों पर अब स्थानीय लोग अंगुलियां उठा रहे हैं।

क्या कहना है लोगों का

महिला सुन्दरी का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को अचानक से होने वाली परेशानियों के दौरान परिजन अपने आस-पास के निजी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर निजी अस्पताल मालिक पीड़िता की परेशानी को कम तथा उसके उपचार से होने वाली कमाई पर अधिक ध्यान देते हैं। जो महिला रोगी के परिजनों को जल्द ही ठीक करने का आश्वासन देते हुए अपने अस्पताल से रेफर नहीं करते हैं। ऐसे में मामला खराब होने पर बच्चा और जच्चा की जान खतरे में पड़ जाती है। जिसमें पीड़िता की जान भी चली जाती है।

अधिवक्ता सीमा डागर का कहना है कि किसी भी सड़क हादसा में घायल होने वाले रोगी गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के कारण रेफर कर दिया जाता है। क्योंकि हड्डी रोग विशेषज्ञ से लेकर सर्जन डॉ. स्थानीय अस्पताल में नहीं है। घायल व्यक्ति के परिजन अधिक पूंजी न होने के कारण क्षेत्र में खुले निजी अस्पतालों में पीड़ित को उपचार के लिए लेकर जाते हैं। रोगी को दाखिल करने में निजी अस्पताल के कर्मचारी पूरी तत्परता दिखाते हैं। लेकिन रोगी के ठीक होने के बाद जो बिल रोगी के हाथ में दिया जाता है। वह उसकी और उसके परिजनों की क्षमता से अधिक होता है। ऐसी मनमर्जी की फीस वसूली की जांच होनी चाहिए।

राजकुमार का कहना है कि शहर में चल रहे निजी अस्पताल मालिकों को फीस वसूली का एक बोर्ड तैयार करके मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। ताकि रोगी व उसके साथ आने वाले परिजनों को उपचार पर खर्च होने वाली नकदी की जानकारी मिल सके।

उन्होंने बताया कि रोगी जब भी निजी अस्पताल से छुट्टी होने पर घर को जाता है। तब बिल की सूची में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी की विजिट के अलावा बैड फीस, एसी व नॉन एसी रुम के खर्चे जोड़कर दे दिया जाता है। जिसे देख उनके पैरों के नीचे की जमीन निकलने लगती है।

हरीश संदूजा का कहना है कि निजी अस्पतालों की वर्ष में कम से कम दो बार जांच हो। यदि साल के हर तीन माह में स्वास्थ्य विभाग की टीम या प्रदेश सरकार द्वारा जांच करानी चाहिए। जांच के दायरे में रोगी से ली जाने वाली फीस का रिकार्ड, निजी अस्पतालों में चल रहे मेडिकल स्टोरों की मान्यता प्राप्त की जांच हो। जो डॉक्टर निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे है। डॉक्टर के अलावा अन्य स्टाफ की कार्य के अनुसार योग्यता की पड़ताल होनी चाहिए।

दहशत के साथ राहत : एक मौत तीन पॉजिटिव के साथ 14 नेगेटिव

किशोरी का अंतिम संस्कार कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत करवाया

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

कोरोना से बृहस्पतिवार को देर रात हुई एक किशोरी की मौत से विभाग उभर भी नहीं पाया कि तीन पॉजिटिव मरीज और सामने आ गए। विभाग की तरफ से किशोरी का अंतिम संस्कार कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत करवाया। साथ ही विभाग को उस वक्त राहत मिली, जब 14 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

किशोरी की मौत

जिले में पिछले दिनों कोरोना से चार लोगों की मौत हुई थी। उन सभी की उम्र 55 साल से अधिक थी। लेकिन बीती रात हुई एक किशोरी की मौत की खबर से विभाग में हडकंप मच गया। बल्लभगढ़ की शिव शारदा कालोनी निवासी मृतक 17 वर्षीय किशोरी को पहले से ब्लड कैंसर था। बुधवार रात को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। युवती को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। जहां उसने बृहस्पतिवार की रात को दम तोड़ दिया।

तीन नए पॉजिटिव

शुक्रवार को तीन कोरोना पॉजिटिव आने आंकड़ा 140 पर पहुंच गया। इन पॉजिटिवों में सिही गांव सेक्टर-आठ से 39 वर्षीय पुरुष है। उसने गत 12 मई को ईएसआईसी में ही सैम्पल दिया था। सेक्टर-आठ स्थित इंद्र नगर से 28 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव पाया गया है। वह गुर्दे में सूजन के कारण ईएसआई में ऑपरेशन करवाने आया था। डाक्टर की सलाह पर उसने कोरोना जांच कराई तो पॉजिटिव पाया गया। मुजेसर स्थित तिलक नगर (ऑटो पिन झुग्गी) से एक 36 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। यह सेक्टर-23 निवासी सब्जी विक्रेता के सम्पर्क में आया था। तीनों को ईएसआईसी मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया गया है।

यह 14 हो गए ठीक

कोरोना पॉजिटिव 14 मरीजों की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को नेगेटिव आने पर सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें सेक्टर-28 निवासी दिल्ली के निजी अस्पताल के सीईओ की 44 वर्षीय पत्नी कमलजीत और 18 वर्षीय बेटा जिग्यांशु शर्मा शामिल है। इनके अलावा दिल्ली की एक फार्मेसी कंपनी के कर्मचारी अनखीर निवासी 24 वर्षीय विक्की की रिपोर्ट नेगेटिव है। आढ़ती गुलशन भाटिया के सम्पर्क में आए डबुआ कालोनी निवासी 43 वर्षीय इंद्रपाल, पलवली निवासी आढ़ती पिता के सम्पर्क में आई उसकी 19 वर्षीय बेटी मेघा, मुजेसर निवासी 24 वर्षीय, जवाहर निवासी 55 वर्षीय रामपुरन, उनकी 45 वर्षीय पत्नी और 25 वर्षीय बेटे अरूण कुमार, इनके साथ ही मृतक सुरक्षाकर्मी ओमप्रकाश के सम्पर्क में आने वाले सेक्टर-16 स्थित गांव दौलताबाद निवासी 29 वर्षीय विरेन्द्र, जवाहर कालोनी निवासी 39 वर्षीय नरेश कुमार, ठाकुरबाद़ा निवासी सब्जी विक्रेता के पास कार्यरत 26 वर्षीय महेन्द्र सैनी और संजय कालोनी निवासी 51 वर्षीय शशिकांत पाडे की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई।

यह है आंकड़े

डॉ. रमेश ने बताया कि अब तक 7224 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 1685 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 5534 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 7084 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 6323 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 5799 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 384 की रिपोर्ट आनी शेष है।

अब तक 140 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 55 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा पांच पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 75 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक पांच मरीजों की मौत हो चुकी है।

गुरुद्वारे को सैनिटाइजर मशीन भेंट की

फरीदाबाद। जिले के दयालपुर गांव स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के गुरु गद्दी दिवस के मौके पर माथा टेका व सरोवर पर अरदास की कि इस वैश्विक कोविड-19 महामारी से प्रदेश, देश के साथ-साथ पूरे विश्व को मुक्ति मिले। सभी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरु गद्दी दिवस दी लख-लख बधाइयां दी। इस अवसर पर आयोजकों ने गुरुद्वारे को सैनिटाइजर मशीन भेंट की। इस मौके पर कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया तथा आने वाले सभी सेवादारों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। इस अवसर पर प्रधान चमकौर सिंह, प्रमुख सेवादार दलजीत सिंह. गुरुप्रसाद सिंह, टेकचंद नंदराजोग (टोनी पहलवान) व कुलदीप सिंह साहनी ने गुरु की महिमा का बखान किया तथा सभी से उनके बताये सच्चाई व नेकी के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। वहीं सभी ने कहा कि इस महामारी के दौर में गरीब व जरूरतमंदों की सेवा से भी ईश्वर भक्ति के समान ही है क्योंकि इससे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं।

मृतका के सम्पर्क में आने पर पांच हेल्थ कर्मी क्वारेंटाइन

कविता। फरीदाबाद

मृतक किशोरी के सम्पर्क में आने वाले चिकित्सक समेत पांच स्टाफ को जिला स्वास्थ्य विभाग ने पांच दिनों के लिए घर में क्वारेंटाइ करने आदेश जारी कर दिए है। वहीं किशोरी को बीके अस्पताल में भेजे जाने की बात भी सामने आई है। जिससे दोनों अस्पतालों के कर्मचारियों और दहशत छाई हुई है।

कोरोना पॉजिटिव किशोरी की मौत की सूचना ने के सम्पर्क में आए इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी में डाल दिया। किशोरी ब्लड कैंसर के इलाज को सबसे पहले बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में लाया गया था। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद ड्रिप लगवाने भेज दिया था। दो स्टाफ नर्सों ने किशोरी को ड्रिप लगाई थी और दो स्वीपरों ने किशोरी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया था। ऐसे में इन स्वास्थ्य कर्मियों की आफत आ गई, किशोरी की मौत की खबर से उनके हाथ पांव फूल गए।

जिस पर आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने पांचों को पांच दिन अपने घरों में ही क्वारेंटाइ रहने की सलाह दी है। पांच दिन बाद फिर सैम्पल लिए जाएंगे। दो दिनों के बाद रिपोर्ट आने पर फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके सम्पर्क में आए सभी स्टाफ के सदस्यों के सैम्पल जांच को भेजे जाएंगे। ताकि कोरोना का चक्र न बढ़े। इस खबर के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल बन गया।

अधिकारी का कथन

बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. मान सिंह ने बताया कि किशोरी पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में आई थी। जिस पर इलाज करने वाले चिकित्सक, दो स्टाफ नर्सो, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक स्वीपर समेत पांच लोगों को पांच दिन के लिए क्वारेंटाइ किया है। किशोरी के सम्पर्क में आने वाले प्राइमरी कॉन्टेक्ट के 15 सैम्पल जांच के लिए भरे है। इसके अलावा सेक्टर-55 पुलिस चौकी से 27 पुलिस कर्मियों के सैम्पल लिये है। यह सभी पिछले दिनों सेक्टर-17 से सामने आए पुलिसकर्मी के सम्पर्क में आये थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कुल 57 सैम्पल लिये है।

टीचर ऑन कॉल प्रोजेक्ट से अब-तक 800 छात्र लाभांवित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले के सरकारी स्कूल के छात्रों को मिल रहे हैं फोन कॉल पर समाधान

सहज पाठ फाउंडेशन और फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल की ओर से 25 अप्रैल को जिले के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए टीचर ऑन कॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस टोलफ्री 18008906006 नंबर के जरिए अब तक 800 छात्र अपना पंजिकरण करवा चुके हैं और फोन पर टीचर्स से अपने सवालों का समाधान भी पा चुके हैं। देशभर में कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासिस चल रही हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों को कोई परेशानी न हो इसके लिए यह हेल्पलाइन शुरू की गई। कॉल सेंटर के टीचर्स का कहना है कि, स्कूल खुलने के बाद कॉल फ्लो ज्यादा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया, वह सभी पंजीकृत छात्रों को प्रतिदिन एसएमएस के माध्यम से बल्क मैसेज भेज रहे हैं। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के एडमिशन सेल इसके लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

एफईसी टीम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पंजीकृत छात्र से बात कर रही है और उन्हें कॉल करने के लिए प्रेरित कर रही है। वे छात्रों को छात्रों द्वारा की जा रही त्रुटियों को कम करने के लिए कॉलिंग प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं। प्रश्नों के लिए कॉल करने के लिए और फोन कॉल के माध्यम से पंजीकरण करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के साथ एक हिंदी पत्रक (उपयोगकर्ता गाइड) को डिज़ाइन किया गया है और कॉल त्रुटियों को और कम करने के लिए पंजीकृत छात्रों के बीच प्रसारित किया जा रहा है।

शिक्षकों ने 45 मिनट और 52 मिनट तक का समय एकल विशिष्ट कॉल पर भी समर्पित किया है।

दस कर्मचारियों वाले संस्थानों को काम करने छूट

फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने लॉकडाउन अवधि में 10 कर्मचारियों तक वाले उद्योगों, औद्योगिक संस्थानों एवं व्यावसायिक संस्थानों, जिन्हें सरल पोर्टल पर आटो मोड से काम करने की अनुमति मिली है, की चेकिंग के लिए क्षेत्रवार तीन कमेटियां गठित की है। ये कमेटियां अपनी इन यूनिटों की निगरानी करेंगी। कमेटी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव व उपायुक्त को भेजना सुनिश्चित करेंगी।

जिलाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा प्रतिदिन कोविड-19 की मानीटरिंग मीटिंग लेते हैं, जिसमें निर्णय लिया गया कि 10 कर्मचारियों तक की यूनिट से मेडिकल सुरक्षा के संबंध में स्व घोषित प्रमाण पत्र भी लिया जाए। जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए औद्योगिक संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है।

बिना राशन कार्ड के भी सरकार दे रही है राशन

फरीदाबाद। हरियाणा की मनोहर सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोगों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनको राशन के कूपन बंटवाये हैं। जिनके जरिये उनको मई-जून माह का राशन निशुल्क मिलेगा। इसी योजना के तहत आज नगर निगम के वार्ड-23 में पार्षद गीता रैक्सवाल व पूर्व पार्षद ओमप्रकाश रैक्सवाल ने वार्ड में कूपन बांटे।

इससे वार्ड के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश जरूर जीतेगा। मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण ही आज बाकी प्रदेशों से हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है, यहाँ ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोगों को राशन डिपुओं पर फ्री में राशन महीने में दो बार मिल रहा है। जरूरतमंद लोगों को रेडक्रास से भी राशन मिल रहा है व पका हुआ भोजन दोनों समय दिया जा रहा है।

इस मौके पर गीता रैक्सवाल व ओमप्रकाश रैक्सवाल ने कहा कि कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में हम सभी को एक जुटता दिखाते हुए जरूरतमंद व गरीब अप्रवासी लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, यही इंसानियत का भी तकाजा है। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत के समय में अगर इन गरीब व मजदूरों की मदद नहीं की गई तो आने वाले समय में हमें अपने उद्योग-धंधे चलाने को भी श्रमिक नहीं मिल पाएंगे। जिसका देश व समाज के विकास पर विपरित प्रभाव पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। इसलिए हम सभी को इन अप्रवासी मजदूरों की भरपूर मदद करनी चाहिए और उनके लिए यहीं रहने-खाने के उचित प्रबंध करने चाहिए ताकि जब कल को तालाबंदी खुले तो ये मजदूर यहीं उद्योगों में काम जीवन को सही पटरी पर ला सकें।

जेसी बोस ने विद्यार्थियों से मांगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस

फरीदाबाद। कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से लड़ने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को सहयोग देने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 20 से 23 मई, 2020 तक आत्मनिर्भर भारत- हैकथॉन प्रतियोगिता के आयोजन का निर्णय लिया है।

इस आशय का निर्णय कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल (आईआईसी) की बैठक में लिया गया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. एस. के. गर्ग, टीईक्यूआईपी परियोजना समन्वयक डॉ. विक्रम सिंह, समन्वयक डॉ. मुनीश वशिष्ठ, आईआईसी के अध्यक्ष डॉ. लखविंदर सिंह, निदेशक, एलुमनाई एवं कॉर्पोरेट अफेयर डॉ. संजीव गोयल और आईआईसी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन पुरस्कार राशि सीड मनी / इंक्यूबेशन प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी।

संक्षिप्त समाचार

शॉटपुट की खिलाड़ी घर पर कर रही प्रैक्टिस

फरीदाबाद। जिले और प्रदेश स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल लेबल के लिए शॉटपुट की उभरती हुई खिलाड़ी घर पर ही पसीना बहा रही है। शॉटपुट खिलाड़ी मोनिका बिरला पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में घर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। एनएच-पांच में 18 वर्षीय मोनिका बिरला अपने परिवार के साथ रहती हैं और उनके मम्मी-पापा सरकारी नौकरी में हैं। मोनिका 12वीं कक्षा की छात्रा है। वह बैडमिंटन की बेहतरीन खिलाड़ी थी, जिससे की वह स्टेट लेवल तक खेली, लेकिन एक साल पहले सत्यवीर धनखड़ के प्रोत्साहन करने पर उन्होंने एथलीट में जाना शुरू कर दिया। वह राजा नाहर सिंह एथलीट मैदान पर ट्रेनर शाकिर हुसैन और सत्यवीर धनखड़ के नेतृत्व में शॉटपुट, जैवलिंग और लंबी कूद में भाग लेती हैं, पर उन्होंने खास तौर पर शॉटपुट को अपनी पसंदीदा खेल बनाया है। उनकी एक साल की मेहनत रंग लाई। उन्होंने जिला व प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ के मुकाबलों में भाग लेते हुए पदक जीते। वह अब भी प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका मैदान में जाना बंद हो गया, लेकिन उन्होंने अपने घर को ही प्रैक्टिस का मैदान बना लिया। उनकी सोच है कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो वह इस साल तक नैशनल स्तर पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन कर हरियाणा का नाम रोशन करेंगी।

पास नोडल अधिकारी नियुक्त

फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने सरल पोर्टल पर पास जारी करने की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी सिस्टम एक्जिक्यूटिव ऑफिसर फरीदाबाद अमिताभ कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आदेशों में बताया कि ये अधिकारी गृह मंत्रालय व जिलाधीश द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मूवमेंट पास जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है, जिस कारण जिला से बाहर जाने के लिए इस कार्यालय द्वारा पास जारी किए जा रहे हैं।

आवेदन करने पर कूपन से तुरंत मिलेगा राशन : त्रिखा

फरीदाबाद। बडखल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा ने आज गोल्फ क्लब में डीआरओ सतीश यादव और उनके अधिकारियों के साथ जनसहायक ऐप को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए कि सरकार द्वारा चलाई गई जनसहायक ऐप द्वारा या किसी और अन्य माध्यम से भी अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने अपने लिए सूखा राशन का आवेदन किया है तो उसे तुरंत राशन मुहैया करा दिया जाए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राशन उपलब्ध कराने की यह व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश में युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत आज से कूपन वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और आने वाले 2 या 3 दिनों में जिन-जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था उनको सरकारी स्थान से कूपन बांटने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। सीमा त्रिखा ने कहा कि बडखल विधानसभा में 10 अलग-अलग सरकारी स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं और उन्हीं सभी सरकारी स्थानों से ही आने वाले 2 या 3 दिनों में कूपन वितरण का काम पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात कूपन प्राप्त होने के बाद उनको अपने अपने डिपो होल्डर से राशन प्राप्त हो जाएगा। विधायक ने कहा कि अभी जिन जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनके नाम आ चुके हैं, हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो और कुछ नए आवेदन भी हो रहे हों उन सभी आवेदकों का नाम जल्द से जल्द आ जाएगा और उनको राशन दे दिया जाएगा।

नारायणी माता परिवार कोरोना में दे रहा मदद

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

नारायणी माता गऊ संरक्षण सोसायटी के प्रधान महेश हिन्दु खुद की कमाई के पैसों से पिछले 49 दिनों से लोगों को भोजन और राशन बांट रहे है। उनकी सोसायटी में उनका परिवार के सदस्य ही शामिल है। महेश की माने तो वह अपने जेब खर्च से पिछले 49 दिनों से सुखा और बना हुआ भोजन 40 हजार परिवारों को बांट चुके है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन वह ढ़ाई सौ लोगों को खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद का ऐसा कोई कोना नही है, जहां वह जरूरतमंदों की मदद न कर रहे हो।

खुद करते हैं सहयोग

महेश हिन्दु ने बताया कि वह पहले तीन कम्पनियों के मालिक थे। ट्रेवल्स का कारोबार चलाते थे। लेकिन पिछले 12 सालों से वह गौवंशों के लिए नंगे पैर कार्य कर रहे है। उन्होंने बताया कि वह अपनी सोसायटी के लिए सरकार व निजी किसी संस्था से कोई पैसा नहीं ले रहे है। भगवान की कृपा से वह अपने पैसों से ही दान कर रहे है। उनकी इस सोसायटी में उनकी पत्नी के अलावा दो बेटे और दो भतीजे सहयोग करते है। वह घायल गौवंशों का इलाज कर रहे है।

जेआरसी और विधिक सेवा ने प्रवासी मजदूरों को किया जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनएच-तीन स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य रवीन्द्र कुमार मनचन्दा की अध्यक्षता में विद्यालय की जेआरसी व एसजेएबी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार एवं मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, रामवीर तंवर, ओम प्रकाश सैनी ने 75 प्रवासी मजदूरों को कोविड 19 महामारी के संक्रमण से बचने के उपाय बताए।

एनएच तीन फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में बने शेल्टर होम इंचार्ज और प्राचार्य रवीन्द्र कुमार मनचन्दा ने विद्यालय में ठहर रहे 75 से भी अधिक प्रवासी मजदूरों को बताया कि कोविड 19 महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए है उनके अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखें। हाथों को सैनेटाइजर से साफ रखें अथवा साबुन से अच्छी तरह धोएं। मुंह तथा नाक को भली भांति मास्क, रुमाल, साफी या गमछे से ढक कर रखें। सोशल डिस्टेंस के सम्पूर्ण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। मजदूरों को बताया कि बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर या वह परिसर जहां रह रहे है से बाहर जाए।

सुरक्षा में ही बचाव है तथा हम सभी को अपनी अपनी सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। फरीदाबाद जूनियर रेडक्रॉस काउंसलर रवीन्द्र कुमार मनचन्दा ने कहा कि डीएसएसओ मालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, रामवीर तंवर तथा ओम प्रकाश सैनी ने भी सोशल डिस्टेंस के लाभ बताए। प्राचार्य रवीन्द्र कुमार मनचन्दा ने सभी प्रवासी मजदूरों को शुभ एवं सुखद यात्रा के साथ स्वस्थ और तंदरुस्त रहने का संदेश दिया।

मजदूरों को सहायता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन

फरीदाबाद। विभिन्न मजदूर संगठनों ने संबंधित सीटू के आह्वान पर जिला फरीदाबाद में शहरी गरीब व प्रवासी मजदूरों को राशन व आर्थिक सहायता देने को लेकर प्रदर्शन किया गया। उचित दूरी रखते हुए मजदूर महिलाओं व पुरुषों ने मांग की कि हमें भूख से बचाने के लिए गुजारे लायक राशन व आर्थिक मदद दी जाए।

सीटू के जिला जिला प्रधान निरंतर पराशर, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल, ने कहा कि भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार मीडिया में हैडलाइन बनवा रही है। परन्तु धरातल पर मजदूरों व गरीब लोगों की हालात दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भुखमरी के चलते प्रवासी मजदूरों में भारी बैचेनी है। तथा वें हजारों की संख्या में भुखे-प्यासे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकडाउन को 52 दिन हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों तथा जिन गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं है या जिनके हरे राशन कार्ड हैं। उनको राशन नहीं मिलता है। वे भुखमरी के कगार पर है। इतने दिनों के बाद भी सरकार शहरों में रहने वाले निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, खुली दिहाड़ीदार, रेहड़ी-पटरी मजदूरों, रिक्शा-ऑटो रिक्शा चालकों, घरों में झाडू पोचा सफाई करने वाले मजदूरों, वर्करों, दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों आदि को राहत देने में नाकाम रही है।

सीटू नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कल घोषणा की गई कि प्रवासी मजदूरों व जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज व एक किलो चने की दाल महीने में दी जाएगी। मजदूरों व संगठनों के बहुत भारी दबाव के बाद केन्द्र ने यह छोटी सी राहत की घोषणा की है जिसे दिया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए। परन्तु क्या इतने भर से परिवार का महीने का गुजारा चल जाएगा? इसलिए 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज व महीने भर का रसोई का पूरा राशन मिलना चाहिए। सरकार पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा कर रही है। जबकि करोड़ों मजदूरों को भुखमरी से बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले मजदूरों को लोन देने की बात कह रही है, आर्थिक मदद देने की नहीं। प्रदर्शनों के माध्यम से मांग की गई कि रोजगार बहाली तक प्रत्येक परिवार को महीने भर का अनाज व जरूरी राशन दिया जाए। खाना बनाने के लिए ईंधन का प्रबन्ध किया जाए। सभी साधन हीन व आमदन हीन परिवारों को 7500 रुपए मासिक नगद राशि दी जाए। मकानों का किराया लेने पर राक हो। जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनको जाने की तुरंत निःशुल्क व्यवस्था की जाए। हरियाणा सरकार बिना किसी कंडीशन के मजदूरों के लिए घोषित 4500 रूपये प्रतिमाह तुरंत नगद उपलब्ध करवाए। प्रदर्शनकारियों को धर्मवीर वैष्णव, अनिल ने सेक्टर 12 में महेश द्विवेदी ने मुजेसर में सुधा पाल, संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में, केपी सिंह ने तिलपत, संतोष नगर, राजीव कॉलोनी, बड़खल पुल के नीचे मजदूर कॉलोनी में, जबकि मानिक और विजय झा ने ओल्ड फरीदाबाद में मजदूरों की सभा को संबोधित किया।

घर में घुस कर युवक से मारपीट

फरीदाबाद। सेक्टर तीन में रहने वाले एक युवक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में घुस कर युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना सेक्टर आठ में दर्ज मामले के मुताबिक सेक्टर तीन निवासी विपिन भाटी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह मूलरूप से कौराली गांव का निवासी है। वह पिछले काफी समय से परिवार के साथ सेक्टर तीन में रहता है। सीही गांव में रहने वाले टिंवकल से उसकी किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है। विपिन का आरोप है कि 12 मई की रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपने घर पर था, तभी उसके घर पर टिंवकल अपने साथ चार पांच युवकों को लेकर आ गया।

स्वदेशी पर जोर

जनता में विश्वास जरूरी

कोविड-19 ने हमें आत्मनिर्भर बनने तथा वैश्वीकरण पर कुछ निर्भरता छोड़ने का सबक दिया है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छी थी, पर वैश्विक महामारी के समय निष्प्रभावी दिखी है। टेस्टिंग किटों से लेकर दवाइयों तथा वेंटीलेटरों से लेकर अस्पतालों की क्षमता तक हम आयातों पर निर्भर थे। स्वास्थ्यरक्षा व शिक्षा के लिए बजट आबंटन पिछले वर्षों में बहुत कम रहा है जिस कारण हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमजोर है तथा शोध एवं विकास पीछे है। इसके बावजूद पिछले डेढ़ महीने में तेजी से खोज हुई तथा स्वदेशी टेस्ट किटें व वेंटीलेटर तैयार हुए और ऐसी वैक्सीन की खोज तेज हुई जो विश्वसनीय और सस्ती हो। इस प्रकार संकट ने हमें अपनी खोज और कौशल तलाशने का अवसर दिया है। यदि इन प्रयासों पर पहले से जोर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। उदाहरण के लिए, दवा उद्योग लगभग 70 प्रतिशत चीनी रसायनों पर निर्भर था। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'लोकल को वोकल' बनाने का आह्वान किया है। सेना कैंटीनों को एफएमसीजी समेत 'मेड इन इंडिया' उत्पाद रखने को कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में हम उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में 70 प्रतिशत वैश्विक ब्रांडों पर निर्भर हैं। इसका कारण आयातों का सस्ता होना भी है। ऐसे में 'स्वदेशी बनो व स्वदेशी खरीदो' महत्वपूर्ण बन जाता है। समय आ गया है कि हम 'मेक इन इंडिया' के बारे में जमीनी स्तर पर विचार करें। इसके साथ ही हमें संरक्षणवादी बनने के बजाय प्रतियोगी भी बनना होगा। ऐसा होने पर हमारे ब्रांड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे। भारत में पिछले लगभग 50 साल से सभी बडे बहुराष्ट्रीय

निगम-एमएनसी काम कर रहे हैं। वे यहां से कच्चा माल लेकर यहीं उत्पादन करते हैं। निसंदेह भारत को स्थानीय ब्रांडों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इनसे रोजगार सृजन होगा तथा इंजीनियरिंग व विनिर्माण कौशल विकसित होंगे। लेकिन इस 'आयात विस्थापन' के लिए विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपनी विशेषज्ञता व कौशल भारत लाएं।

आत्मनिर्भरता की गांधीवादी भावना ने अनेक बड़ी स्वदेशी कंपनियों को जन्म दिया था जिनमें से कुछ बची रहीं, पर अधिकांश हाशिए पर पहुंच गईं। जेएन टाटा ने 1886 में स्वदेशी मिल लगाई थी। गोदरेज का विश्वास था कि भारत विनिर्मित वस्तुओं के मामले में पश्चिम पर निर्भरता घटा कर ही स्वराज प्राप्त कर सकता है। अब भारत कोई उपनिवेश नहीं है। विडंबना है कि स्थानीयकरण से वैश्विक रूप से प्रतियोगी कंपनियां बड़ी संख्या में नहीं बन सकीं। बजाज आटो की असाधारण अंतरराष्ट्रीय सफलता का कारण यह है कि उसने भारतीय बाजार में बड़े विदेशी ब्रांडों से मुकाबला किया। भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों टाटा, महिन्द्रा व हीरो की सफलता का कारण यह है कि उन्होंने प्रतियोगिता झेली तथा सर्वश्रेष्ठ विदेशी साझीदारों से गठबंधन किया। वर्तमान समय में भारत वस्तुओं व सेवाओं के आयात में चीन पर निर्भर है जो उसके निर्यातों से 50 बिलियन डालर अधिक हैं। हमारे पास रेयर-अर्थ धातुओं की कमी है, इसलिए हम सोलर पावर उपकरण, हवा टरबाइनें, सेलफोन, लैपटाप व इलेक्ट्रानिक्स का विनिर्माण ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वैश्विक ब्रांडों का स्मार्टफोन व टेलीवीजन में 90 प्रतिशत कब्जा है। रेफ्रीजरेटरों, वाशिंग मशीनों व एसी के हमारे ब्रांड बहुत पहले ही चीनी, जापानी व दक्षिण कोरियाई आयातों के सामने ध्वस्त हो गए थे। हालांकि, स्वदेशी ब्रांड खादी भारत में बहुत लोकप्रिय है, पर इसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बहुत कम है। यदि देशी खुदरा कंपनियों, हाइपरमार्केट श्रृंखलाओं व फास्ट फूड ब्रांडों के मामले में भारत की सफलता कोई संकेत है तो स्पष्ट है कि हम इस क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडों का मुकाबला कर सकते हैं। छोटे अनुबंधो के मामले में भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना अच्छा कदम है। लेकिन अनेक उपलब्धियों व उम्मीदों के बावजूद हमें आत्मनिर्भरता व स्वदेशी पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और हम 1970 के दशक वाले दिनों में वापस नहीं लौटना चाहेंगे।

सरकार का संकट मोचन आर्थिक पैकेज

सरकार ने वर्तमान संकट से निपटने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। लेकिन कुछ विश्लेषकों की नजर में यह आर्थिक रूप से ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसमें मांग घटने की समस्या से निपटने के समुचित उपाय नहीं हैं।

जयवीर शेरगिल
लेखक सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं)

हाल ही में, 12 मई को प्रधानमंत्री ने अपनी खास शैली में 20 लाख करोड़ के 'वित्तीय पैकेज' की घोषणा की जिसके विस्तृत विवरणों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिचित करा रही हैं। पैकेज की घोषणा के पहले सभी क्षेत्रों का मानना था कि ऐसे पैकेज की आवश्यकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की बहाली के बारे में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की विषयवस्तु व आयामों पर संदेह था। वर्तमान संकट के कारण अनेक बिजनेस बंद हुए हैं, बचत घटी है, रोजगार गायब हुए हैं, बुरे कर्ज बढ़े हैं, ग्रामीण जनता में बदहाली है तथा कृषि क्षेत्र का संकट गहरा हुआ है। वित्तीय पैकेज की घोषणा के बाद सवाल उठे हैं कि क्या इससे पहले से सुस्त पड़ चुकी व सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को कोई प्रोत्साहन मिलेगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पैकेज का परीक्षण राजनीतिक विश्वसनीयता व आर्थिक प्रभावशीलता तथा क्रियान्वयन के आयामों पर करना होगा।

वर्तमान समय में जब सारा देश 'स्वास्थ्य व संपदा' के मामले में सबसे अंधेरे समय का सामना कर रहा है तब सरकार से उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार अपनी झोली खोल कर बिना किसी शर्त के लोगों की जेबों में अतिरिक्त आमदनी डालेगी। लेकिन 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की डेढ़ घंटे लंबी चली प्रेस कान्फ्रेंस के बाद संभवत: अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। लोगों को इससे पैसा मिलता नहीं दिखाई दिया। सभी लोगों को निराशा हुई कि समाज के संकटग्रस्त तबकों पर घोषणाओं में समुचित ध्यान नहीं दिया गया जिनमें प्रवासी श्रमिक, किसान, दूकानदार व वेतनभोगी तबके शामिल हैं। अनेक घोषणाओं से लगा कि जैसे वित्त मंत्रालय कोई 'बचाव योजना' पेश करने के बजाय 'लोन मार्केटिंग ब्रोचर' पेश कर रहा है। कहा जा सकता है कि 'स्टीमुलस पैकेज' के रूप में पेश वित्तीय पैकेज अपनी उम्मीदों व अनता की आवश्यकताओं पर अनेक कारणों से खरा नहीं उतरा।

'सबको कुछ न कुछ देने' के समावेशी फार्मूले के बजाय इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों व उनके 13.62 करोड़ परिवारों को छोड़ दिया गया जिनमें किसान, निम्न मध्यवर्गीय व वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि नोटबंदी की तरह समाज के सबसे संकटग्रस्त तबके को सरकार के गलत नियोजन, संवेदनहीनता व अतार्किक दृष्टिकोण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना कोई आर्थिक व्यवस्था किए केवल चार घंटे की सूचना पर 1.3 बिलियन लोगों को उनके घरों में बंद कर देना उचित नहीं कहा जा सकता है। लाकडाउन का 300-400 रुपये रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों पर भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत अनेक निगमों को भी वेतन कटौती तथा बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा करनी पड़ी है।

विडंबना है कि सरकार ने ईंधन पर टैक्स लगाने जैसा संवेदनहीन कदम उठा कर आर्थिक रूप से परेशान नागरिकों पर एक और बोझ डाल दिया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य 18 साल में सबसे कम स्तर पर हैं। इसके अलावा विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती की गई है जिससे 30 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी 44 करोड़ खाताधारकों के बचत खातों पर ब्याज दर 3.25 प्रतिशत से घटा कर 2.75 प्रतिशत कर दी है। इन कदमों के कारण गंभीर संकट के समय जमाकर्ताओं की आय घटी है। देश इस समय आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि राजग सरकार आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाएगी। उम्मीद थी कि वह प्रत्येक जनधन खाताधारक के खाते में कम से कम 7,500 रुपये डालेगी। यह भी आशा थी कि वह बेरोजगारों को राहत देने के लिए मासिक भत्ते की घोषणा करेगी। उसे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में वृद्धि की घोषणा भी करनी चाहिए थी तथा वेतनभोगी वर्ग को आय कर में व्यापक राहत देनी चाहिए थी। इसके बजाय लगता है कि सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के माध्यम से सबको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई थी। लेकिन इसके बाद कम से कम 55 प्रवासी मजदूरों की मौत तथा गांवों की ओर बड़ी संख्या में उनके पलायन की हृदयविदारक तस्वीरें सामने आई हैं। गरीब 'रोटी सब्जी' के लिए घंटों लाइनों में खड़े दिखते हैं। इससे स्पष्ट है कि शायद घोषणाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तनों की जरूरत है। इसके लिए उन हाथों में पैसा देने की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। इसके बिना आर्थिक पैकेज का कोई अर्थ नहीं होगा।

इसके साथ ही किसी स्टीमुलस पैकेज का अर्थ अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय सृजन कर मांग बढ़ाना होना चाहिए, कर्ज का बोझ बढ़ाना नहीं। हमारे नीति-निर्माताओं ने शायद इस बार भी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान नहीं दिया है। 45 लाख सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों-एमएसएमई को बंघन-मुक्त कर्ज देने के लिए 3 लाख करोड़ की कर्ज गारंटी योजना लाई गई है। लेकिन इसमें यह तथ्य अनदेखा किया गया है कि इस क्षेत्र के पास कर्ज के बजाय मांग में कमी की समस्या अधिक है। सवाल यह भी है कि इस योजना से उन 6.5 करोड़ एमएसएमई को छोड़ क्यों दिया गया जो जनसंख्या के 11.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं? यदि कर्ज पर ब्याज की माफी का निर्णय किया जाता तो इससे एमएसएमई के पास अतिरिक्त पैसा बचता और वह अर्थव्यवस्था का गतिरोध दूर करने में सहायक सिद्ध होते।

एक ओर सरकार उद्योगों से उम्मीद कर रही हैं कि वे अपने कर्मचारियों व कामगारों को बिना किसी आमदनी के वेतन देते रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर उनको 'ब्याज मुक्त' कर्ज के रूप में किसी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। इस प्रकार वित्तीय पैकेज का लक्ष्य मांग बढ़ाने के बजाय कर्ज बढ़ाना अधिक लगता है जिससे सभी लोग निराश व आश्चर्यचकित हैं। विडंबना है कि वित्त पैकेज ने प्रधानमंत्री के नारे-'लोकल को वोकल बनाने का समय आ गया है' को शायद कोई समर्थन नहीं दिया है। 'मेक इन इंडिया' हमें इस तथ्य की याद दिलाती है कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है। स्थानीय उद्योगों को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल व अन्य संगठनों की कैंटीनों से स्वदेशी उत्पादों की ज्यादा बिक्री हो। स्थानीय उद्योगों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए पैकेज में औद्योगिक वृद्धि दर तेज करने के प्रयास दिखने चाहिए थे। पैकेज में 'वेतन सुरक्षा पैकेज' को भी स्थान मिलना चाहिए था। इस प्रकार एक समग्र दृष्टिकोण के अभाव में 'लोकल को वोकल' बनाने का नारा भी ज्यादा प्रभावी नहीं होगा।

इस वित्तीय पैकेज के बारे में यह कहना गलत न होगा यह आर्थिक प्रभावशीलता तथा राजनीतिक विश्वसनीयता के मानकों पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि यह समावेशी नहीं है तथा इसमें आय सृजन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस पैकेज से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। ऐसे में आगे बढ़ने का रास्ता राजनीतिक विश्वसनीयता मजबूत करना है। हालांकि, अभी देश के 20 लाख करोड़ के पैकेज की केवल एक झलक देखने को मिली है, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं पैदा होती हैं। जनता का हित ध्यान में रखते हुए विपक्ष को उम्मीद है कि सरकार पहले किए गए अपने वादों पर भी ध्यान देगी जिसमें देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने, गंगा साफ करने, आतंकवाद समाप्त करने, काला धन समाप्त करने तथा हर साल दो करोड़ नौकरियों का सृजन शामिल हैं।

वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के पुन: जल्दी से पटरी पर आने की उम्मीदें कम लगती हैं।

अब और लाकडाउन की आवश्यकता नहीं!

"17 मई को लाकडाउन समाप्त होने के पश्चात सरकार को सुरक्षा एवं स्वच्छता के साथ जीवन को सहज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।"

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक आईटीआई परिषद के प्रबंधक हैं)

ताली बजाना, दीप, लैम्प आदि जलाना एवं फूल बरसाना, यह सबकुछ हो चुका। अब हमें वायरस द्वारा मचाई गई तबाही तथा महामारी के भय से परिपूर्ण वर्तमान अनिश्चिततापूर्ण परिस्थिति में अपनी आजीविकाओं की ओर लौटने जैसे धीमे एवं निराशायुक्त काम की ओर पुन: लौटना है। यह मेरा चौथा स्तम्भ लेख है उस मुद्दे पर कि किस तरह मेक इन इंडिया की ओर वापस लौटना है और वर्ष 2020 के शेष कालखंड में जीना है।

मैं पिछले दो महीनों के दौरान हुए जीवन के वास्तविक अनुभवों की ओर ध्यान दिलाता हूं और फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। मेरा मित्र एक डॉक्टर है, जो दयालुता के साथ सांसारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए टैक्स अदा करता है। उसके परिवार में, 80 वर्ष से अधिक आयु की मां, एक किशोरावस्था में एक बेटी तथा डॉक्टर पत्नी है। उसके क्लीनिक में तीन लोग नौकरी करते हैं जो पिछले दो महीनों से बंद है। उसे हर महीने वेतन, टैक्स और बहुत से खर्चों में धन व्यय करना पड़ता है। सरकार के आदेशों के अनुसार, कोई भी एकल स्वास्थ्यरक्षा इकाई खोलने की अनुमति तो प्रदान की गई है लेकिन उसके पास शुरुआत में निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। अब उसने कुछ खरीदे हैं लेकिन प्रत्येक पीपीई सूट की कीमत 2,000 रुपए होती है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर देना होता है और यह खर्च उसे रोज वहन करना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या एक निजी स्वास्थ्यरक्षाकर्मी प्रतिदिन इतना खर्च वहन कर सकता है?

दूसरा उदाहरण दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित खाद्य वितरण पहल से संबंधित है। लाकडाउन के प्रथम चरण के दौरान एवं उसके समवर्ती राज्य की प्रतिक्रिया के चलते, लोग दिन में बार भोजन के लिए लाइनों में लगते थे, लेकिन जल्द ही उनका धैर्य चुकने लगा। एक बार मुझे एक भीड़ ने घेर लिया जिसमें शामिल लोगों ने हाथ जोड़कर मुझसे किसी तरह उन्हें दूरस्थ गांवों में स्थिति उनके घरों को वापस भिजवाने का निवेदन किया। ये सभी लाकडाउन में फंसे आम जनों के व्यक्तिगत तथा यथार्थपूर्ण अनुभव हैं। हम सदैव इस बहस में उलझे रहते हैं कि कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं और कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, और ये बातें हमारी राजनीतिक, धार्मिक अस्मिताओं एवं वैचारिकताओं पर आधारित होती हैं। लेकिन आज हमें उठ खड़े होने एवं भारत को इन दुर्दशाओं व जनता के जमावड़ों से मुक्त करना है। यहां सुशासन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं।

केंद्र सरकार लगभग दो महीनों से आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के बल पर राज्य सरकारों पर आच्छादित होकर काम कर रही है। यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से केंद्र का शासन जो अधिकतर अपने राज्य मुख्य सचिवों का समर्थन करते हैं तथा केंद्र सरकार के आकाओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। यहां पर प्रमुख चुनौती है नौकरशाही का इस लोक सेवा को स्वीकार करना जो लाभ के लिए नहीं है जो एक कारपोरेट नौकरी का प्रतिरूप है। सहमत हूं कि कई जिला मजिस्ट्रेट आगे जाकर सचिव बनने वाले हैं मगर क्या वे दूरदृष्टिपूर्ण ढंग से नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी बनते हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नौकरशाहों को लक्ष्य दर्शाने का दायित्व देकर शक्ति प्रदान करने का श्रेष्ठ काम किया है। मगर क्या वो इसे जिला स्तर तक पहुंचा पाए हैं? आत्मनिर्भर भारत केवल तभी हो पाएगा यदि प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को मुख्य कार्यकारी बना दिया जाए। उसे कोविड-19 से पहले और बाद की दो स्थितियों को जिलें में जीडीपी पर निर्मित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें पर्याप्त नियंत्रणों के साथ शक्ति प्रदान करनी चाहिए, उनके अपने जिले की अर्थव्यवस्था का सापेक्षत: अल्प समयांतराल में पुनरुत्थान करने के लिए। हो सकता है आपदा प्रबंधन कानून का इस्तेमाल आर्थिक सशक्तीकरण के लिए किया जा सके।

दूसरे, सरकार को नीति घोषणाओं में नौकरशाही भाषा को खत्म करने के लिए अधिक विशालहृदयता का परिचय देना होगा। उदाहरण के लिए, "दबाव के शिकार एमएसमई के लिए 20,000 करोड़ के अधीनस्थ ऋण" जैसे बयान को कोई नहीं समझता। क्या हम बैंकों में प्रविष्टि स्तरीय कर्मचारियों से कर्ज मांग रहे स्थानीय दर्जी का सामना करने, व्याख्या करने एवं नीति के पहलू समझाने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम सरकार से उन लोगों के समक्ष सरल भाषा में यह बताने की उम्मीद कर सकते हैं जो योजना के लाभार्थी हैं या जो नहीं हैं?

क्या शासन जनता के लिए अपनी भाषा को सरल बना सकता है? भूमि, तरलता एवं कानून केवल तभी बदल सकते हैं जब उनको लागू करने वाले प्राधिकारी, ऐसी भाषा बोलना प्रारम्भ करें जो नागरिकों को समझ में आती हो। क्या यह समय सरलीकृत संप्रेषण प्रशासन का है?

क्या शासन को एकबद्ध किया जा सकता है? यह पूछने में अतिशयोक्तिपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि क्या स्थानीय, जिला, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को एक समुत्थानपरक एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए संयोजित किया जा सकता है? क्या वैश्विक आपूर्ति श्रंखलाओं का बड़ा हिस्सा पाना एवं उन्हें तोड़ना संभव है? क्या हम एक देश के तौर पर, चीन निर्मित दीवाली लैंपों, बिजली स्विचों एवं कपड़ों के साथ-साथ 5,000 फोनों के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम मानते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रानिक वस्तुएं एवं उनके पुर्जे व हिस्से एक वैश्विक आपूर्ति श्रंखला की रेखा हैं जिसका निर्माण मूल रूप से चीन में होता है?

अंत में, और पुन: भाषा से संबंधित, लाकडाउन की शब्दावली एक लाल रेखा को निर्धारित करती है जिसके चले जाने की आवश्यकता है। हां, यह महामारी जल्दी जाने वाली नहीं है और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के साथ लोगों तथा वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध कुछ समय तक लागू रहने वाले हैं। हालांकि, भाषा में बदलाव कम से कम स्थानीय पुलिस को उन पर रौब जमाने से रोक सकते हैं जो बहस नहीं कर पाते। 17 मई को लाकडाउन-4 समाप्त होने के पश्चात सरकार को सुरक्षा एवं स्वच्छता के साथ जीवन को सहज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

आप की बात

सही कहा राष्ट्रपति जी ने

इस महामारी के माहौल को देखते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की कही यह बात बिल्कुल सटीक है कि भारत जैसे बड़े और घने आबादी वाले देश को विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर ठोस कदम उठाने होंगे अन्यथा हमारे देश में ऐसी आपदाओं के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पिछले कई वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाई जाती रही है लेकिन सत्ता के मोह तथा वोट के लालच के चलते ठोस नीति व कानून का अभाव पिछले कई सालों से बना हुआ है महामारी के चलते देश के कोने-कोने में गरीबी भुखमरी व लाचारी की तस्वीर देखने को मिलती है जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है इस महामारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है सिर्फ शारीरिक दूरी ही अभी तक एक कारगर उपाय है लेकिन भारी जनसंख्या की वजह से हमारे देश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने से यह उपाय नाकाफी साबित हो रहा है इसलिए हम देखते हैं कि जब इस लॉकडाउन में बाजार खुलते है तो भारी भीड़ के चलते शारीरिक दूरी के सभी नियम टूट जाते हैं और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा जनसंख्या की वजह से आज हमारे प्राकृतिक संसाधन भी कम पड़ते जा रहे हैं।

– **महेंद्र सिंह लोधी**, अलीगढ़

बढ़ती मजदूरों की मुश्किलें

वो समाजवाद, जम्हूरियत या राजशाही हो;मज़दूरों का हमेशा एक सा इतिहास होता है। समस्या महामारी की थी और उपाय भी लॉकडाउन ही था। लिहाज़ा अपनाया भी गया। हालांकि कई मामलों में असफल भी रहा। लेकिन इस लॉकडाउन नें आज़ादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही आधिकारिक रूप से अपनाए गए शहर केंद्रित विकास या यूं कहें कि नेहरू-महालनोबिस मॉडल की कलई ही खोल के रख दी है। यह व्यवस्था ऊपर से कितनी भी आकर्षक क्यों न रही हो पर यह अंदर से बेहद ही लचर व खोखली थी। जिसकी न नींव मज़बूत थी और न ही ऊपर और अंदर की संरचना ही सक्षम थी। जो मज़दूरों को भी अपनेपन का अहसास दिला सके। लिहाज़ा यह नियोजन भी बहुत ही अनियोजित ही था, जो आज अब हम सबके ही सामने है। हमनें कभी सोचा ही नहीं कि जिन मज़दूरों के श्रम से महलों में लगातार कृपा बरसती रही है, वह इन मेहनतकशों के लिए कितनी मात्रा में अपना है। देश की अर्थव्यवस्था को अपने श्रम के पसीने से सतत गतिमान रखने वाले इन मज़दूरों को जीवन निर्वाह भर का भी हिस्सा नहीं दिया गया। 90 के दशक से तो एलपीजी के नाम पर श्रम कानूनों पर प्रत्येक सरकारों के द्वारा लगातार कैंची ही चलाई जाती रही।

– **वीरेंद्र बहादुर पांडेय,** गोंडा

न्यायाधीश की पीड़ा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने रिटायर होने के बाद अपनी व्यथा कथा, पीड़ा को संबोधन के जरिए न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की कानून व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। अमीर व रसूखदार सलाखों के पीछे होता है तो कानून तेजी से काम करता है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को खुद ही अपना ईमान बचाना चाहिए। यह कड़वा लेकिन पूर्ण सच है । पिछले कुछ समय से न्यायालय फैसलों पर उंगली उठना व कुछ प्रकरणों में तेजी से सुनवाई करना और कुछ प्रकरणों को जानबूझकर लटकाए रखना इस बात का प्रमाण है। जब न्याय व्यवस्था अमीरों और रसूखदारों के इशारों पर काम करेगी तो ईमान व न्याय का गला घुटना स्वाभाविक ही है। उनका इशारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की तरफ भी है। दिल्ली के दंगों के समय सख्ती से लिए गए संज्ञान पर रातों-रात जस्टिस महोदय मुरलीधर को हरियाणा कोर्ट के लिए रिलीव कर देना इस बात का प्रमाण है। यह समय न्यायपालिका के ईमान को बचाने का है।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

हमें कोरोना के साथ जीने की कला समझनी होगी क्योंकि यह प्राकृतिक वायरस नहीं कृत्रिम वायरस है।
– **नितिन गडकरी**
केंद्रीय मंत्री

यह बात सामने रखना महत्वपूर्ण है। यह हमारे समुदायों में एक और तंत्रस्थ विषाणु बन सकता है। हो सकता है यह कभी न जाए।
– **माइक रेयान**
डब्लूएचओ पदाधिकारी

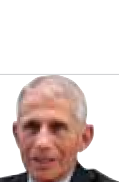

अमेरिका में घर में सीमित रहने के नियमों में इतनी जल्दी राहत दे देने से हमारे देश में परेशानियां एवं मौतों की संख्या और बढ़ेगी।
– **एंथोनी फॉसी**
एनआईएआईडी निदेशक

आर्थिक पैकेज से जुड़ी कार्य योजना तुरंत तैयार करें

रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन पर विशेष फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के मद्देनजर राज्य के विभागों को कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न सेक्टरों हेतु किए गए प्राविधानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ यहां की जनता के लिए सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन पर विशेष फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों की कार्य योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र सरकार के पैकेज के दृष्टिगत औद्योगिक विकास, कृषि, वित्त, राजस्व, नगर विकास, एमएसएमई, खाद्य एवं रसद, ऊर्जा, आवास, श्रम, वन, पंचायतीराज और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने सम्बन्धित विभाग पैकेज के प्राविधानों का अध्ययन करते हुए भारत सरकार से समन्वय बनाते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब या शिथिलता न बरती जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से शिल्पकारो, व्यवसायियों और कामगारों को लाभकारी रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसानों की आय को बढ़ान, फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य और पशुपालन, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत योजनाएं बनाकर लागू की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था और समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति सजग है। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न सेक्टरों के लिए की गई घोषणाओं द्वारा लाभार्थियों के राहत और कल्याण का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड से सभी शेष किसानों को आच्छादित करने का कार्य किया जाए। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों, स्ट्रीट वेण्डरों, प्रवासी शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों और आवास सेक्टर के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में विशेष आर्थिक पैकेज से मदद मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से कमजोर वर्गों की आवास समस्या का समाधान होगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा, ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ,एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष की जनता से अपील गरीब-मजदूरों की करें मदद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने देश और प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के चलते पीड़ित गरीब परिवारों की मदद करें। उन्होंने कहा कि हम भारतवासी हैंए हमारी संस्कृति और परम्परा परोपकार की रही है। कहा जाता है कि गरीबों में ईश्वर का वास होता हैए इसीलिए दरिद्रनारायण की चर्चा की गई है। हिन्दू धर्म मे अन्न दान को महादान बताया गया है, इस्लाम में गरीबों की मदद हेतु ज़कात की व्यवस्था है, सिख धर्म मे लंगर खिलाना पुण्यकर्म माना गया है और ईसाई धर्म गरीबों की सेवा और इलाज को सर्वोच्च स्थान मिला है। ऐसे में हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम इन हालात में अधिक से अधिक लोगों की मदद करें। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि मेरी जनसामान्य से भावपूर्ण अपील है कि सरकारी निर्देशों एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाकर राहगीरों के लिए केवट और शबरी बन जाइये।

प्रवासी मजदूरों का रखा जाय पूरा ख्याल

जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से उपमुख्यमंत्री ने की वार्ता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री व जनपद मैनपुरी के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से वेबिनार के जरिए वार्ता करते हुए कोरोना वायरस के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कोविड-19के संकट में दिए जा रहे उनके योगदान के बाबत जानकारी हासिल की तथा कहा कि सभी लोग कोराना वायरस संक्रमण के नियंत्रण में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन समन्वय बनाकर काम करें।

उन्होंने आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव सहित विधायकों व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अभी तक उठाए गए कदमों की जानकारी हासिल की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका भी रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। जो बाहर से आए है उनकी सूची तत्परता पूर्वक बना ली जाए। राशन वितरण में लापरवाही व घटतौली किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। कहा कि मनरेगा में जरूरतमंदों को काम हर हाल में दिया जाए और काम के बदले भुगतान समय से मिले। उपमुख्यमंत्री ने मैनपुरी में किसान सम्मान निधि भी पूरी तरह से पात्रों को ही लाभ देने के निर्देश दिए। साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि जो पैदल प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिये पैदल यात्री सेवा केंद्र बनाकर उनके भोजन पानी आदि का प्रबंध सुनिश्चित कराएं। उपमुख्यमंत्री ने सांसद रीता बहुगुणा जोशी सहित अन्य लोगों से भी जिले की स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल की। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनकी सही ढंग से ट्रैकिंग होनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग प्रयागराज से होकर अन्य जिलों को जा रहे हैं उनका सही मार्गदर्शन करेंए सांत्वना दें और यथासंभव उनकी मदद करें।

ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से हो साफ-सफाई: भूपेंद्र सिंह चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु ग्रामों की नियमित साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सफाई कर्मचारियों को सफाई किट व मास्कए ग्लब्सए सेनिटाइजरए साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। ग्रामों में साफ-सफाई हेतु ग्राम वासियों को निरन्तर जागरूक किया जाये। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 52781 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर सफाई का कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था सही रहे इसके लिए ग्रामों में हैण्डपम्प यदि कहीं खराब या मरम्मत योग्य है तो उन्हें शीघ्र ही ठीक कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से अब तक 83773 रिबोर एवं 159759 खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य कराया गया है। पंचायतीराज के राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य कराये गये हैं उनका विवरण ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर अंकित कराया जाये।

प्रवासी मजदूरों को लेकर कारगर कदम उठाए जाएं: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की हालत पर दुख व्यक्त जताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें उनके लिए कारगर कदम उठाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट के माध्यम से लिखा कि देश की सड़कों पर घर वापसी करते लुटे लाचार लाखों प्रवासी मजदूर व उनके बिलखते परिवारों की भूख, बदहाली व रास्ते में हो रही मौतों के टीवी दृश्य हृदयविदारक व अति दुखद। ऐसे में केन्द-राज्य सरकारों द्वारा आज की उनकी जिंदगी-मौत की लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल लागू हो।

प्रदेश में अब तक आ चुके हैं 13.50 लाख कामगार : अवनीश अवस्थी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 13.50 लाख कामगार व श्रमिक आ चुके हैं। प्रदेश में पहली मार्च से 30 अप्रैल तक 6.50 लाख लोग प्रदेश में आए हैं। प्रदेश में अब तक 380 ट्रेन के माध्यम से लगभग 4.69 लाख प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आए है।

बसों के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से लगभग 70 हजार लोग आए हैं जबकि लगभग 1.50 लोग निजी वाहनों से प्रदेश में आए हैं । प्रदेश में आ रहे कामगार एवं श्रमिकों को मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरान्त खाद्यान्न देकर होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में 57 ट्रेन से 62680, लखनऊ में 34 ट्रेन से 39905 , प्रयागराज में 25 ट्रेन से 31431, जौनपुर में 25 ट्रेन से 32419, बलिया में 14 ट्रेन से 17568, वाराणसी में 18 ट्रेन से 22357, आगरा में 5 ट्रेन से 6433, कानपुर में 8 ट्रेन से 10133 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 48 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आवागमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 250 और ट्रेन की अनुमति दी गई है । उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गुजरात से रिकार्ड 201 ट्रेन आ चुकी हैं जबकि महाराष्ट्र से 72, कर्नाटक से 13, पंजाब से 67, केरल से 5, तेलंगाना से 5, आन्ध्र प्रदेश से 2, राजस्थान से 7 तमिलनाडु से 3, मध्य प्रदेश से 2 तथा गोवा से 1 ट्रेन के माध्यम से प्रवासी कामगार एवं श्रमिक को लाया गया है। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों व श्रमिकों एवं अन्य लोगों को बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजते हुए चिकित्सकीय जाच के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें होम क्वारेंटाइन कराया जा रहा है।

मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाए सरकार: रालोद

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में असहाय मजदूरों पर हो रहे हादसों पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि विगत सप्ताह में 16 मजदूरों की रेल हादसे में हुई दर्दनाक मृत्यु ने आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया था और अब सड़क हादसों में भी 16 से अधिक लोग अकाल मृत्यु के गाल में समा गए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर रोडवेज की बस द्वारा पैदल चलने वाले मजदूरों को कुचलना तथा मध्य प्रदेश के गुना में बस और ट्रक की भिड़न्त के फलस्वरूप हुई मौतों को मानवीय लापरवाही ही कहा जायेगा। त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक व्यक्ति के लिए दो लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है जो नाकाफी है। रालोद प्रदेश प्रवक्ता ने माँग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकारों द्वारा मृतकों को पाँच लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की मुआवजा धनराशि की घोषणा होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी स्थानीय उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराकर दोषियों को दण्डित करना चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही पर लगाम लग सके।

सरकार के फैसलों से अमीर-गरीब के बीच बढ़ेगा फासला: अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अब किसी को इसमें रत्तीभर भ्रम नहीं रह गया है कि भाजपा सरकार अमीरों के लिए, अमीरों के हितों के पोषण के लिए और गरीब, किसान तथा मजदूर के खिलाफ है। हाल के भाजपा सरकार के निर्णयों से साफ हो गया है कि उसकी नीतियों के फलस्वरूप देश में अमीर-गरीब की खाई ज्यादा चौड़ी होगी तथा देश अराजकता की दिशा में चलता दिखाई देगा। अखिलेश ने कहा कि यह कौन सा किसानों के हित की घोषणा है कि किसानों को कर्ज लेने के लिए कहा जा रहा है। बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हुई, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, गन्ना किसान बदहाल है, बैंक और साहूकार ब्याज पर ब्याज वसूलते जा रहे ह, खेती के काम आने वाले उपकरण और अन्य सामग्री सब मंहगी है, ऐसे में क्या वह और कर्ज लेकर फांसी के फंदे से बच पायेंगे। अखिलेश ने कहा कि घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जो सड़कों पर भूखें प्यासे मरने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार अब भेदभाव और विद्वेष के चलते गरीबोंए मजदूरों को राशन पानी भोजन की मदद देने वाले समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमें दर्ज कर रही है और उन्हें राहत कार्य करने से रोक रही है। मेरठए बुलंदशहर और कई अन्य जनपदों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं।

लगातार पेट्रोलिंग कर श्रमिकों की मदद के साथ साथ आपराधिक घटनाओं पर लगाएं अंकुश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में यूपी 112 और स्थानीय पुलिस के वाहन लगातार प्रभावित पेट्रोलिंग करें। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों की हर संभव मदद करने के साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगाएं।

डीजीपी अवस्थी शुक्रवार को यूपी 112 मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर अपर पुलिस महानिदेशक ए कानून व्यवस्था ए अपर पुलिस महानिदेशक ए रेलवे ए अपर पुलिस महानिदेशक ए 112 ए पुलिस महानिरीक्षक ए कानून व्यवस्था सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जोनल एडीजी रेंज के आईजी डीआईजी व जिलों के पुलिस कप्तानों को लॉकडाउन के दृष्टिगत जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा किविभिन्न प्रदेशों से पैदल व साइकिल से आने वाले प्रवासी कामगार आऔर श्रमिकों को रोककर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उन्हें ऐसे निर्धारित स्थानों पर पहुंचाएं जहां से उन्हें बसों द्वारा उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जाना है। इन श्रमिकों के साथ अत्यंत शालीनता एवं समानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं जिससे श्रमिकों के साथ सड़क पर कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। ट्रेनों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन के आसपास जीआरपी ए स्थानीय पुलिस ए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के आपसी समन्वय से सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैंकों में लोगों के बढ़ रहे आवागमन के दृष्टिगत बैंको के आसपास सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध करते हुए सघन पेट्रोलिंग करायी जाए तथा अपराधिक एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी करायी जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस बल को संक्रमण से बचाते हुये निर्गत निर्देशों एवं एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करें।

राहत पैकेज के उपयोग के लिये रोजगार सृजित करें: मुख्यसचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये लाकडाउन से प्रभावित लोगों एवं उद्योगों के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि योजना में 30 से 35 प्रतिशत अधिक भूमि चिन्हित की जाये, ताकि आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश शुक्रवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कैम्पा अभिचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिये। बैठक में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं सीएएफ रूल्स-2018 के प्राविधानों के अनुसार कैम्पा की वर्ष 2020-21 की धनराशि 27500 लाख की वार्षिक प्रचालन योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर केन्द्र सरकार भेजने के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंटए मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्यए वृक्षारोपण एवं जंगल की सुरक्षाए जंगल की आग की रोकथाम तथा नियंत्रण ऑपरेशन, वन्य जीवों के आवास में सुधारए जैव विविधता संरक्षणए नर्सरी के उच्चीरकण इत्यादि सम्बन्धी कार्य शामिल हैं। श्री तिवारी ने कहा कि ई.सर्विलांस के माध्यम से जंगल के अन्दर की गतिविधियों की निगरानी की व्यवस्था की जाये। जंगल से निकले वाले रास्ते पर वन्य जीवों को बचाने के लिये सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किये जायें। टाइगर रिजर्व पार्क में क्षमता से अधिक टाइगर होने पर नियमानुसार उन्हें रिलोकेट किये जाने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने जंगलों को सूखने से पूर्व उनकी मानीटरिंग के लिये नवीनतम टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बल दियाए ताकि सूखने से पूर्व समय रहते उन्हें बचाने के प्रयास किये जा सकें। बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाने के वादे से क्यों मुकर रही है सरकार: लल्लू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उप्र के एक एक प्रवासी श्रमिक को उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, ऐसी घोषणा और वादा करने वाली उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से पैदल व निजी वाहनों से यात्रा कर रहे परेशान हाल उप्र के प्रवासी श्रमिकों की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकारों ने संवेदनशीलता पूरी तरह से खो दी है। इस भीषण गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर अपने बच्चों एवं सामान के साथ हजारों श्रमिक सड़कों पर पदयात्रा करने को मजबूर हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उप्र से लगने वाली सभी राज्य की सीमाओं पर राज्य परिवहन निगम की बसें लगायी जाएं और सीमा में प्रवेश करने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों एवं उनके परिजनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए।

रोडवेज की बसें किस दिन के लिए हैं: प्रियंका

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों की पैदल घर वापसी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को किए गए ट्वीट में अटैची पर अपने बेटे को लटकाकर खींच रही महिला का वीडियो लगाकर कहा है कि थके हुए कदमों से ये किसका भविष्य खींचा जा रहा है, यूपी रोडवेज की बीसियों हजार बसें किस दिन के लिए हैं, यदि हम विपदा के मारे इन हिंदुस्तानियों को घर भी नहीं ले जा सकते। प्रियंका ने कहा है कि आपके भाषणों से, पैकेजों से इनका भरोसा टूट चुका है। ये कदम अब अपने गांव पहुंचकर ही रुकेंगे। इन्हें घर पहुंचाइए।

सड़क हादसों में सात की मौत, दर्जनों घायल

● प्रवासी मजदूर लगातार बन रहे हैं दुर्घटनाओं का शिकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना वायरस के संकट के बीच बड़ा संकट उन मजदूरों पर मंडरा रहा है जो घर वापसी के दौरान लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रदेश के जालौन, बहराइच, जौनपुर, बाराबंकी में हुए सड़क हादसों में सात मजदूरों की मौत हो गई जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए। जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रयागराज से गिट्टी लेकर बस्ती जा रही ट्रक जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के गोबरहा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। ट्रक पर सवार सात प्रवासी मजदूर गिट्टी के नीचे दब गए। उनमें एक की मौत हो गई। छह अन्य मजदूरों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। सीएचसी खुटहन पर प्रारम्भिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दो मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे में चालक भी घायल हुआ है, जबकि खलासी घटना के बाद से लापता है। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर बड़ेल स्थित भाजपा कार्यालय के सामने वाहन के इंतजार में खड़े 7 श्रमिकों को लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दो भाइयों की मौके से मौत हो गई जबकि 5 घायल हुए। वहीं घायलों में से एक की मौत जिला अस्पताल में हुई। जबकि अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। मृतक व घायल ग्राम हुसैनपुर, मोहम्मदपुर थाना रिसिया, जिला बहराइच के रहने वाले हैं। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसा शुक्रवार की भोर करीब 3 बजे हुआ। घायलों ने पुलिस को बताया कि वह ट्रक से यहां तक आए थे। इसके बाद पहले ट्रक वाले ने उन्हें यहां छोड़ दिया। घर जाने के लिए दूसरे ट्रक का इंतजार कर रहे थे।

जालौन के एट थाना क्षेत्र के एनएच 27 स्थित ग्राम गिरथान के करीब प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 14 मजदूर घायल हो गए। डीसीएम में 46 प्रवासी मजदूर सवार थे। बहराइच लखनऊ हाईवे पर मदनकोठी के पास हुई दुर्घटना में 30 मजदूर घायल हो गए। इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी लोग भी महाराष्ट्र से लौट रहे थे।

प्रवासी मजदूरों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, किया मदद का ऐलान

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन के बाद भी प्रवासी कामगार का पैदल तथा अन्य साधनों से अपने घरों की ओर जाने के कारण दुर्घटना में मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर के बाद जालौन तथा बहराइच में सड़क दुर्घटनाओं में प्रवासी श्रमिकों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद दुखी हैं। दोनों दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक दिये जाने के सीएम योगी ने निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन के एट थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में प्रवासी कामगारों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बहराइच में एक सड़क दुर्घटना में एक प्रवासी कामगार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने तथा सभी घायलों का समुचित उपचार कराने का निर्देश दिया है।

सेतु निगम में तबादले पर भड़का परिषद

लखनऊ। राज्य सरकार के फैसले के विपरीत सेतु निगम में हुये तबादलों का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि कोरोना के कारण लाकडाउन चलते स्थानन्तरण सत्र 2020-21 में आग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गई थी लेकिन इसके विपरीत शासन के आदेशों को धता बताते हुए सेतु निगम प्रबंधन द्वारा रामबाबू दिवाकर सहायक अभियंता को अपनी योगदान आख्या देने हेतु गोरखपुर भेजने का कार्यमुक्ति दिया। मुख्य सचिव के आदेश अवहेलना होने की जानकारी होने पर सेतु निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन तथा उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने इसका प्रबल विरोध करते हुए उक्त कार्यमुक्ति आदेश वापस लेने की मांग की गई। इस मामले में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लिखित रूप से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि आपके शासनादेश के उपरान्त रामबाबू दिवाकर सहायक अभियंता को कार्यमुकत किया गया।

ऑनलाइन शिक्षण कार्य से जुड़े 376 महाविद्यालय: मोनिका गर्ग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में लाकडाउन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की पढ़ाई को निर्बाध गति से जारी रखने के लिये निरन्तर प्रयास कर रहा है। प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं ने इस दिशा में आगे बढ़कर आनलाइन शिक्षा की चुनौती को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। वर्तमान में लगभग 376 महाविद्यालयों द्वारा आनलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 112 महाविद्यालयों, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली के 62 महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के 54महाविद्यालय आनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बतायाा कि शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा 1,55,185 ई.कन्टेन्ट्स तैयार कर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसका लाभ 9,06,126 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के 14,884 शिक्षकों द्वारा आनलाइन क्लास टाइमटेबल प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा चुका है। इसके अंतर्गत कुल 3,51,805 आनलाइन कक्षायें संचालित की गयीं। इन कक्षाओं में औसतन प्रतिदिन 274887 विद्यार्थियों ने कक्षाओं में प्रतिभाग किया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि लाकडाउन के दौरान 6,939 शिक्षकों ने अपने ज्ञान में अभिवृद्धि के लिये आनलाइन कोर्स किये तथा 5791 शोधपत्र, पुस्तकें तथा लेख आदि लिखे हैं। यह आनलाइन शिक्षा के प्रति शिक्षकों के अभिरूचि को दर्शाता है। आनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये तथा गुणवत्तापरक ई-कन्टेन्ट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा महाविद्यालय के प्रचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा 3615 बैठकें आयोजित की गयीं तथा इसी क्रम में विश्वविद्यालयां एवं महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की 3577 आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। आनलाइन टीचिंग के ई-कन्टेन्ट्स का लगभग 80 विषयवस्तु हिन्दी में अपलोड किया है। यही कारण है कि 906126 विद्यार्थियों द्वारा ई-कन्टेन्ट्स का प्रयोग किया गया है। आने वाले समय में शिक्षक अपने ई-कन्टेन्ट्स को अधिक से अधिक संख्या में हिन्दी में अपलोड करने के लिये तैयारी कर रहे हैं। नि:संदेह यह अभिनव प्रयास विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

राज्यपाल से खफा टीएमसी, कहा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए

● राज्यपाल द्वारा केन्द्र के आर्थिक पैकेज की तारीफ करना राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को नागवार गुजरा

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा केन्द्र के आर्थिक पैकेज की तारीफ करना राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को नागवार गुजरा है। पार्टी ने शुक्रवार को धनखड़ से कहा कि उन्हें राज्य की विधानसभा के अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यपाल ने देशभर में किसानों की परेशानियों को दूर करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से केन्द्र की पीएम-किसान योजना में शामिल होने का आग्रह किया था। किसानों, प्रवासियों और रेहड़ी-पटरी वालों की दिक्कतों को दूर करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रशंसनीय प्रयास। पीएम-किसान लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से दो लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज मिलेगा। इसके अलावा रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।

राज्य सरकार पर राजभवन के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रखने का आरोप लगाते रहने वाले धनखड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को दूरदर्शी और कायापलट करने वाला करार दिया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा सांसद कल्याण बनर्जी ने धनखड़ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके ट्वीट से पता चलता है कि राज्यपाल भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हें अगले साल भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आपके ट्वीट से पता चलता है कि आप पूरी तरह केन्द्र सरकार के कर्मचारी बन गए हैं और भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कल जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया उसमें कुछ नहीं है और इसमें बंगाल की जनता के साथ धोखा किया गया है।

विदेश में फंसे के लोगों की वापसी के लिए बंगाल तैयार : राज्य सचिव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने केन्द्र सरकार को बहुत पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि उसने खाड़ी समेत दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इंतजाम कर लिए हैं। विदेशों से किसी भी विशेष विमान के पश्चिम बंगाल नहीं आने को लेकर केन्द्र द्वारा लगाए गए आरोपों के एक दिन बाद यह बयान आया है। राज्य के गृह विभाग ने ट्वीट किया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विभिन्न देशों में फंसे हमारे लोगों को वापस लाने को इच्छुक है और काफी समय पहले भारत सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके साथ वापस आने वाले लोगों को पृथक रखने के इंतजाम की भी जानकारी दी थी। पत्र संलग्न है। बंगाल विमानों का इंतजार कर रहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बृहस्पतिवार रात कहा था कि केन्द्र ने विदेशों से आ रहे विमानों के बंटवारे को लेकर भेदभाव किया है।

रांची में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई।

कोविड-19 के नए मामले

सावंत गोवा में ट्रेनों के रुकने के खिलाफ

पणजी। गोवा में एक महीने के अंतराल पर कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों को मडगांव स्टेशन पर नहीं रोकने का सुझाव दिया है।उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रेलगाड़ियों या विमानों में राज्य आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा भले ही वे गोवा के निवासी क्यों न हों। सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे को सुझाव दिया है कि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए 15 मई को चलने वाली विशेष ट्रेन जो कि 16 मई को मडगांव पहुंचेगी, उसे गोवा के स्टेशन पर नहीं रोका जाए। उन्होंने कहा, 720 लोगों ने ट्रेन में टिकट बुक की है जो मडगांव स्टेशन पर उतरेंगे। हमें पता चला है कि उनमें से शायद कोई भी गोवा का नहीं है। सावंत ने कहा, हमें इस बात की चिंता है कि उनके यहां उतरने पर क्या होगा। हमें उनका परीक्षण करना पड़ेगा। हम उन्हें घर में पृथक-वास में रहने को कहेंगे लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। इसलिए हमने सुझाव दिया कि है ट्रेन इस स्टेशन पर रुके ही नहीं।

असम ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने केंद्र को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होना है। यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि सभी राज्यों को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर शुक्रवार तक अपनी प्रतिक्रिया देनी थी और असम सरकार पहले ही अपने पक्ष से केंद्र को अवगत करा चुकी है। सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने बंद के चौथे चरण में उन रियायतों पर भी अपने विचार रख दिए हैं जो वह राज्य के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार को इस पर विचार करने दिया जाए। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता।

राजनाथ ने किया गश्ती पोत, दो नौकाओं का जलावतरण

भाषा। पणजी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच नई दिल्ली में वीडियो-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के (आईसीजी) एक पोत और दो अवरोधक (इंटरसेप्टर) नौकाओं का शुक्रवार को जलावतरण किया। सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के देश में निर्मित सचेत पोत और सी-450 एवं सी-451 अवरोधक नौकाओं का वीडियो लिंक के माध्यम से गोवा में जलावतरण किया। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने में इन पोत एवं नौकाओं का जलावतरण एक मील का पत्थर है।

सिंह ने कहा कि इनका जलावतरण भारतीय पोत निर्माण क्षमताओं की बढ़ती ताकत को दर्शाता हैं। उन्होंने भारतीय तटों की सुरक्षा में आईसीजी के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षित तट देश को आर्थिक विकास के अवसर देते हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। आईसीजी के प्रवक्ता ने बताया कि पांच अपतटीय गश्ती नौकाओं की श्रृंखला के तहत पहले पोत सचेत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने देश में डिजाइन किया और बनाया है। यह अत्याधुनिक नौवहन एवं सम्प्रेषण उपकरणों, सेंसर एवं मशीनरी से लैस है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुद्री इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब डिजिटल माध्यम से तटरक्षक नौका का जलावतरण किया गया है। ऐसा कोविड-19 वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में सामाजिक दूरी के कड़े प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए किया गया।

इस अवसर पर सिंह के अलावा, रक्षा सचिव अजय कुमार, आईसीजी के महानिदेशक डी जी कृष्णास्वामी नटराजन भी मौजूद थे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के वास्को परिसर में मौजूद थे। 105 मीटर लंबे इस पोत का वजन करीब 2,350 टन है और इसमें 9,100 किलोवॉट के दो इंजन लगे हुए हैं। यह 26 नॉट की अधिकतम गति से चल सकता है। यह पोत तलाश एवं बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर, उच्च गति की चार नौकाओं और एक हवा भरी जाने वाली नौका ले जाने में सक्षम है। यह समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित उपकरण ले जाने में भी सक्षम है।

आईसीजीएस सचेत की कमान उप महानिरीक्षक राजेश मित्तल के पास है और इसमें 11 अधिकारी एवं 110 अन्य लोग तैनात हैं। प्रवक्ता ने बताया कि देश में निर्मित सी-450 और सी-451 अवरोधक नौकाओं को गुजरात के हजीरा में एल एंड टी शिपयार्ड ने डिजाइन किया एवं बनाया है और इसमें अत्याधुनिक नौवहन एवं सम्प्रेषण उपकरण लगे हैं। 30-30 मीटर लंबी ए नौकाएं 45 नॉट की गति से चलने में सक्षम हैं। इन्हें उच्च गति से अवरोधन, तट के निकट गश्त एवं कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इन नौकाओं की कमान सहायक कमांडेंट गौरव कुमार गोला और सहायक कमांडेंट अकिन जुत्शी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पौत एवं नौकाओं को ईईजेड (विशिष्ट आर्थिक जोन) में सर्तकता, तटीय सुरक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए मुख्य तौर से तैनात किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि अब भारतीय तट रक्षक बल के पास 150 पोत एवं नौकाएं और 62 विमान हो गए हैं। इसके अलावा 50 अन्य पोतों का निर्माण जारी है।

घुसपैठ की आशंका के बीच गुजरात में मछुआरों को किया गया अलर्ट

पोरबंदर। घुसपैठ की आशंका के बारे में भारतीय तटरक्षक बल से मिली खुफिया सूचना के बाद गुजरात में मछुआरों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या नौका देखने पर उनके बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है। बृहस्पतिवार को मछुआरों के संघों को लिखे पत्र में, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक के पोरबंदर स्थित कार्यालय ने कहा कि तटरक्षक बल ने एक खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि मई में राष्ट्र-विरोधी तत्त्व तट के पास हमला करने या घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सूचनाओं के मद्देनजर, विभाग ने मछुआरों को सतर्क रहने और तट के पास किसी भी लैंडिंग स्थान के पास कोई संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या नाव दिखने पर स्थानीय समुद्री पुलिस या तटरक्षक बल को सूचित करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि मछुआरे समुद्री पुलिस और तटरक्षक बल के टोल-फ्री नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।

मास्क नियम को लेकर बहस के बाद हमले में तीन पुलिसकर्मी जख्मी

मुंबई। मध्य मुंबई के एंटप हिल इलाके में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनने के बारे में टोकने के बाद 15 लोगों के समूह ने धारदार हथियारों से एक पुलिस उपनिरीक्षक और दो कांस्टेबल पर कथित तौर से हमला कर दिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि घटना बृहस्पतिवार दोपहर को कोखरी अगर गरीब नवाज नगर इलाके में हुई जहां पुलिस की एक टीम ने मास्क नहीं पहनने के लिए इन लोगों को रोका। उन्होंने कहा, उन लोगों ने इस मुद्दे पर पुलिस दल के साथ बहस की और उन पर हमला कर दिया। 15 से अधिक लोगों ने धारदार हथियारों से एक उपनिरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों पर हमला किया। अधिकारी ने बताया कि घटना में तीन पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

देहरादून में बजुर्ग महिला की कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल लेते स्वास्थ्य कर्मी।

कोविड-19 स्थिति पर उद्धव और शरद पवार ने की गहन मंत्रणा

मुम्बई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में शुक्रवार को बैठक की। राकांपा ने बताया कि ठाकरे और पवार ने केन्द्र द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज, कानून एवं व्यवस्था, प्रवासी श्रमिकों, रोजगार और उद्योगों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रिमंडल के कुछ अन्य मंत्री भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार का राकांपा प्रमुख हिस्सा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यवापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने से दो दिन पहले यह बैठक हुई। देश में कोविड-19 के सबसे अधिक 27,500 मामले महाराष्ट्र में ही हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। राज्य में कारोना वायरस के सबसे अधिक मामले यहीं हैं। राकांपा ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री, सांसद शरद पवार और कुछ अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में कोविड-19 की स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन किया गया। पार्टी ने कहा कि सांसद शरद पवार ने केन्द्र द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज,प्रवासी मजदूरों की समस्या, बेरोजगारी और औद्योगिक मामलों की समीक्षा की और (राज्यों की) नीति दिशा तय करने के लिए (बैठक में) चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और पवार के बीच यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। गृह मंत्री अनिल देशमुख, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सहित कई मंत्री बैठक में मौजूद थे।

सामाजिक न्याय मंत्री मेघवाल को उपचार के लिए गुडगांव भेजा गया

जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को आगे उपचार के लिए विशेष विमान से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल ले जाया गया है। यहां जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिजनों की इच्छा के अनुरूप उन्हें आगे उपचार के लिए अब गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। शुक्रवार सुबह उन्हें विशेष विमान से गुड़गांव के अस्पताल के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मेघवाल को बुधवार रात पक्षाघात का दौरा पड़ने के बाद जयपुर के सवाई मान सिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉ वीरेंद्र सिंह व मेघवाल के परिजनों ने उन्हें आगे उपचार के लिए गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भेजने की इच्छा जताई।

छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों का सीएसआर का पैसा राज्य को वापस करे केंद्रः बघेल

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उनके प्रदेश के उद्योगपतियों द्वारा पीएम केयर्स कोष में दिए गए सीएसआर के पैसे को वापस लौटाए। उन्होंने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में यह भी कहा कि देश को पीएम केयर्स कोष में आए पैसे के बारे में जानने का अधिकार है। बघेल ने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में आई सहयोग राशि का लेखा-जोखा सार्वजनिक किया था। उनके मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि पीएम केयर्स कोष में छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत पैसे दिए हैं।

केंद्र 17 मई के बाद कई चीजों में ढील की घोषणा कर सकता है : एदियुरप्पा

भाषा। बेंगलुरू

कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है, और ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा ने शुकवार को विश्वास जताया कि 17 मई के बाद केंद्र कई चीजों में ढील देने की घोषणा कर सकता है। एदियुरप्पा ने यहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, केंद्र सरकार 17 मई के बाद बहुत सी चीजों में ढील देने जा रही है। हमें इसका इंतजार करना चाहिए।

उन्होंने कहा, मेरे मुताबिक वे (केंद्र) हर चीज में ढील देंगे...पांच सितारा होटल जैसी चीजों या अन्य के लिए कुछ समय तक वह भले ही अनुमति नहीं दें, लेकिन अन्य चीजों के लिए वे अनुमति देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए और देखिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन शुरूआत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू किया गया था। इसके बाद इसे तीन मई तक बढा दिया गया और एक बार फिर इसे 17 मई तक के लिए बढाया गया।

कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी टी रवि ने बुधवार को संकेत दिया था कि राज्य सरकार जिम, फिटनेस सेंटर एवं गोल्फ कोर्स खोलने की अनुमति देने जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद स्थानीय पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से कुछ निश्चित होटलों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मुजराई विभाग (मंदिरों के प्रशासन के प्रभारी) भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की योजना के तहत, जनता के लिए मंदिरों को खोलने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए मंदिर खोलना गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन आता है।

महाराष्ट्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए दो समन्वय समितियों का गठन किया

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्य और जिला स्तर पर दो समितियों का गठन किया है। सरकार के अनुसार भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के प्रतिनिधियों और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता के बीच एक बैठक के बाद गुरुवार को समन्वय पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया। 14 मई को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि समितियां महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और चिकित्सा दिशा-निर्देश संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध कराए जाने संबंधी सरकार के सभी फैसलों को क्रियान्वित करने का काम करेंगी। पैनल यह भी जांच करेंगे कि निजी अस्पतालों में चिकित्साकर्मियों को पीपीई किट, दस्ताने और मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं या नहीं।

कोरोनाः भोपाल के कब्रिस्तान में हर वक्त तैयार रखी जा रही है दस कब्रें

भोपाल। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ने के मद्देनजर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एक प्रमुख कब्रिस्तान में कम से कम दस कब्रें हर वक्त उपयोग के लिए तैयार रखी जा रही हैं। भोपाल में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण को 900 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल शहर में कोविड-19 से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले जहांगीराबाद में झाड़ा कब्रिस्तान में यह व्यवस्था की गई है। इस कब्रिस्तान की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रेहान गोल्डन ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा से कहा, हम झाड़ा कब्रिस्तान में कम से कम दस कब्रें हर वक्त इस्तेमाल के लिए तैयार रखते हैं, क्योंकि अस्पतालों से शव कभी भी यहां आ रहे हैं। हमें नहीं पता मरने वाले लोग कोविड-19 संक्रमित हैं या नहीं।

कब्रों को उपयोग के लिए तैयार रखने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, एक कब्र खोदने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। इन परिस्थितियों में हम शवों को दफनाने के लिए लोगों को पांच घंटे तक इंतजार नहीं करा सकते। वह भी तब, जब प्रशासन अस्पताल में मरने वाले लोगों के शवों को घर ले जाने की अनुमति भी नहीं दे रहा।

रेहान ने बताया कि झाड़ा कब्रिस्तान में छह अप्रैल से अब तक शहर के विभिन्न अस्पतालों से 38 शव आ चुके हैं। उन्होंने कहा, हम कब्रों को तैयार रखते हैं और शरीयत के अनुसार शव को दफनाने की रस्मों में लगभग आधा घंटा लगता है। उन्होंने बताया कि पांच मई को कब्रिस्तान में एक ही दिन में अलग-अलग अस्पतालों से छह शव आए थे। रेहान ने कहा, हम सभी मामलों में पूरी सावधानी बरतते हैं क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि अस्पताल से आने वाला शव कोविड-19 संक्रमित है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार बृहस्पतिवार शाम तक भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 900 पर पहुंच गई। इनमें से 35 लोगों की मौत हो गई है।

गुवाहाटी में फैंसी बाजार में आवश्यक सामान ले जा रहे डिलीवरी मैन को चेक करती पुलिस।

‘आत्मनिर्भर भारत स्वत: ही अधिक वैश्विक बन जाएगा’

● आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भारत कभी भी एकाकी व्यवस्था पर जोर नहीं देता : विदेश सचिव

भाषा। नई दिल्ली,

विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत स्वत: ही अधिक वैश्विक बन जाएगा क्योंकि देश आत्म केंद्रित या एकाकी व्यवस्था की बात कभी नहीं करता है।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत की वकालत की थी और इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया था। नेशनल डिफेंस कालेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा सभी संकटों का भू-राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और कोविड-19 के बाद भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जिसमें शक्तियों का पुन: संतुलन , नई बहुस्तरीय संवाद व्यवस्था और शक्तियों की ताकत में बदलाव शामिल है। विदेश सचिव ने कहा, जब हम वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं, ऐसे में हमें संकट से उबरने के लिए आत्म निर्भर बनने की जरूरत है जिसकी बात प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में की थी। उन्होंने कहा, हालांकि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तब आत्म केंद्रित या एकाकी व्यवस्था की बात नहीं करते। एक आत्मनिर्भर भारत स्वत: ही अधिक वैश्विक भारत बन सकेगा। विदेश सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस ने औषधि की दुनिया में भारत की भूमिका की पुन: पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत ने 133 देशों को चिकित्सा आपूर्ति भेजी जिसमें 44.6 करोड़ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन टैबलेट और 1.54 पैरासिटामोल टैबलेट शामिल हैं। विश्व के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्रृंगला ने कहा कि आतंकवाद बढ़ रहा है और ऐसा कैंसर बन गया है जो देशों को अस्थिर और कमजोर करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत के प्रयासों से आतंकवाद और इसके प्रायोजक अलग थलग पड़े हैं लेकिन देश को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रूख रखे। उन्होंने कहा कट्टरवादी विचारधारा हिंसा और असुरक्षा उत्पन्न कर रही है। सीमापार से जारी आतंकवाद से पीड़ित देश के रूप में हम आतंकवाद को समर्थन, वित्त पोषण और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कार्वाई की मांग करते हैं।

देशभर में लाकडाउन के बीच हैदराबाद में लोगों को गंतव्य पर रवाना करने से पहले जानकारी एकत्र करता पुलिस अधिकारी।

क्विक न्यूज

रालोसपा ने छोटी परियोजनाओं को बढ़ावा देकर प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया

पटना। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) ने बिहार वापस लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के मद्देनजर नीतीश कुमार सरकार से लाल फीताशाही दूर कर छोटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की अपील की है। रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र की उस नई नीति का लाभ उठाना चाहिए, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए की खरीद के लिए कोई वैश्विक संविदा आमंत्रित नही करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली छोटी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित कंपनियों को ही जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नामांकन के जरिए निविदाएं दी जानी चाहिए। आनंद ने कहा कि एक परियोजना की निविदा जारी होने से लेकर कई चरण होने के कारण इसकी शुरुआत करने में लंबा समय लग जाता है, ऐसे में इस ओर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक अनमुान के मुताबिक, लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले 10 लाख से अधिक बिहार के प्रवासी विभिन्न राज्यों से वापस आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार एक साथ कई महीनों तक लाखों लोगों का खर्च वहन नही कर सकती, इसलिए रोजगार के अवसर पैदा करके बिहार सरकार इस संकट के समय को लोगों के लिए यही रहने के अवसर में तब्दील कर सकती है।

नायडू ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि उत्पादो की अंतर-राज्ईय बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। उप राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक उन्होंने, यह हर्ष का विषय है कि सरकार ने कृषि उत्पादो की अंतर-राज्ईय बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। इस हेतु एक केंद्रीय कानून लाने का निर्णय समयानुकूल है, जिसमें किसानों को बिक्री के अधिक विकल्प दिए जाएंगे ताकि किसान अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। नायडू ने कहा, अनाज, आलू, प्याज,तिलहनो और खाद्य तेलो की बिक्री का विनियमन और, मत्स्य पालन, पशु पालन, कृषि ढांचे व सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदम देश में कृषि के विकास को गति देंगे। उप राष्ट्रपति के अनुसार इन निर्णयों से कृषि उत्पादकों व उपभोक्ता दोनो को लाभ पहुंचेगा।

मणिपुरी युवती से नस्ली दुव्यवहार, पिटाई को लेकर हरियाणा सरकार व पुलिस को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुड़गांव में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा एक मणिपुरी युवती से कथित तौर पर नस्ली दुर्व्यवहार और उसकी पिटाई किए जाने की खबरों को लेकर हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है। आयोग ने खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि 20 वर्षीय युवती से पहले एक उम्रदराज महिला ने दुर्व्यवहार किया और उनके बीच कहा-सुनी शुरू होने पर भीड़ ने युवती को कोरोना कह कर पुकारा। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में आई इन खबरों पर स्वत:संज्ञान लिया है कि रविवार दोपहर मणिपुर की रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ गुड़गांव के कुछ स्थानीय लोगो ने नस्ली दुर्व्यवहार किया और उस पर नृशंस हमला किया। इसमें कहा गया है, यह बहुत ही घिनौना है कि अपने ही देश के पूर्वोत्तर हिस्से की रहने वाली एक युवती से एनसीआर में एक स्थानीय परिवार ने नस्ली भेदभाव किया और उसकी पिटाई की। बयान में कहा गया है कि इस घटना को लेकर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुड़गांव के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजे गए हैं। उनसे चार हफ्तों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद पुलिस की जांच की स्थिति तथा पीड़िता को प्राधिकारों द्वारा मुहैया की राहत के बारे में भी बताने को कहा गया है।

सकारात्मक परिणाम देती हैं कठिन स्थितियां: प्रो. चंदन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली/ ईटानगर

हिंदी विभाग, राजीव गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के दूसरे दिन प्रो. चन्दन कुमार का वक्तव्य हुआ। ‘कोविड-19 का उत्तरकाल: शिक्षा, साहित्य और समाज’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा पूर्वोत्तर से लगाव पुराना है। इस समय समर्थ और ताकतवर देशों का भ्रम टूट रहा है। ताकत और सुविधा संपन्नता के जो मापदंड हमने तय किये थे वे देखते ही देखते बिखर चुके हैं। प्रो. चन्दन ने कहा कि तुलनात्मक यथार्थ सुख और दुख दोनों को समझने का एक विवेक देता है।

निराला के ‘कुगी भाट’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समाज का महामारियों से सामना नया नहीं है। वह पहले ऐसी समस्याओं से निजात पा चुका है इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए। 1918 में आये स्पेनिश फ्लू का वर्णन उन्होंने तथ्यों को सामने रखकर किया। उन्होंने कहा कि कई बार कठिन स्थितियां सकारात्मक परिणाम देती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोरोना का उत्तरवर्ती काल शिक्षा, साहित्य और समाज के लिए नए आयाम विकसित करेगा।अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि कोविड-19 का संकट हमारी शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालयों को बदलेगा।

वेबिनार में भाग लेते प्रो.चंदन कुमार।

आगामी समय में कक्षाएं तकनीक की जद में चलेंगी। तकनीक आप पर तीसरी आंख के रूप में शासन करेगी। शिक्षा में तकनीकी के प्रवेश से अध्यापकों को संयमित, पारदर्शी और जवाबदेह रहना होगा। उन्होंने इस बात की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि इस महामारी के पश्चात सूचनाओं की महामारी आएगी। जो लोग तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को गाली देते हैं वो गाली भी तकनीकी के माध्यम से ही देते हैं इसलिए तकनीकी का विरोध हास्यास्पद है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि शिक्षा के मानकीकरण में तकनीकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण वक्ताओं में हात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के निदेशक प्रो. नंद किशोर पाण्डेय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ,रायपुर के कुलपति प्रो. केसरी लाल शर्मा और यूजीसी, दिल्ली के सदस्य प्रो. किरण हजारिका ने भी अपने वक्तव्य दिए।

प्रो. संजीव कुमार शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना ने हमारी तीव्र आधुनिक गति को विराम दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद हमारे कथ्य एवं शिल्प दोनों में एक संतुलित परिवर्तन ही समाज को सही दिशा दे सकेगा। प्रो. पाण्डेय ने कहा कि कोरोना ने हमें सिखाया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रो. केसरी लाल वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम भारतीय जीवन पद्धति से ही इस संकट से निजात पा सकेंगे। प्रो. किरण हजारिका ने भी इस विषय पर अपने सुचिंचित वक्तव्य से श्रोताओं को लाभान्वित किया। आज के कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य राजीव गाँधी विवि, ईटानगर के कुलपति प्रो. साकेत कुशवाहा ने दिया। संचालन प्रो. हरीश कुमार शर्मा ने किया। संयोजन डॉ. सत्यप्रकाश पाल और डॉ. राजीव रंजन प्रसाद ने किया।

श्रमिकों, अन्य व्यक्तियों के परिवहन में होने वाले व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से हो: बघेल

भाषा। रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों के अंतरराज्जीय तथा राज्य के भीतर परिवहन में होने वाले व्यय के भुगतान का प्रावधान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में होना चाहिए।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों के अंतरराज्जीय परिवहन तथा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले परिवहन व्यय के भुगतान के लिए एसडीआरएफ में समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य के 1.50 लाख से अधिक श्रमिक तथा अन्य व्यक्ति अन्य राज्यों में अवरूद्ध हैं तथा लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वह अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ की वापसी के लिए उत्सुक हैं। इसमें कहा गया है, अन्य राज्यों से श्रमिकों की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

लगभग 27 हजार से अधिक श्रमिक स्वयं के साधनों तथा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बस सुविधा से गृह राज्य लौट चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख 32 हजार श्रमिकों को रेल तथा बसों के माध्यम से लाने की प्रक्रिया 11 मई से प्रारंभ हो चुकी है।

श्रमिकों के लिए रेल तथा बस परिवहन में हुए व्यय का भुगतान एसडीआरएफ से किए जाने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। बघेल ने पत्र में लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।

रांची में कोविड-19 से लड़ रहे रिम्स के स्वास्थ्यकर्मियों की हौसलाआफजाई के लिए स्वयंसेवकों ने आयोजित किया स्वागत कार्यक्रम।

बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट

भाषा। देहरादून

उच्च हिमालई क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट छह माह के शीतकालीन अवकाश के बाद शुक्रवार तड़के साढ़े चार बजे खोल दिए गए। मंदिर के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में धनिष्ठा नक्षत्र में खोले गए,लेकिन हर वर्ष कपाट खुलने के दौरान श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला मंदिर का प्रांगण इस बार कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण खाली रहा और मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी समेत चुनिंदा 11 व्यक्ति ही मौजूद रहे।

इस दौरान सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसी सभी जरूरी एहतियाती कदम भी उठाए गए। इस बार सेना के बैंड की सुमधुर ध्वनि और भजन मंडलियों की स्वर लहरियां भी नहीं सुनाई दीं। भगवान विष्णु को समर्पित इस धाम के खुलने के बाद मानवमात्र के रोग-शोक की निवृत्ति, आरोग्यता एवं विश्व कल्याण की कामना की गई।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से भगवान बद्रविशाल की प्रथम पूजा मानवता के कल्याण हेतु संपन्न की गई। मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया था जो बिजली की रोशनी से जगमग होकर अनूठी आभा बिखेर रहा था। कपाट खुलने के बाद वेद मंत्रों की ध्वनियों से पूरी बद्रीशपुरी गुंजायमान हो गई। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कहर का प्रभाव उत्तराखंड के चार धामों पर भी पड़ा है। बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन आश्रम, दुकानें, छोटे-बड़े होटल, रेस्तरां और ढाबे बंद है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तिथि भी इस बार कोरोना वायरस के कारण 15 दिन आगे खिसका दी गई थी। पहले कपाट 30 अप्रैल को खोले जाने थे।

उत्तराखंड के अन्य तीन धाम पहले ही खोले जा चुके हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले गए थे, वहीं रूद्रप्रयाग जिले में भोले बाबा के धाम केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले गए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष चार धाम यात्रा से अभी श्रद्धालुओं को दूर रखा गया है और केवल कपाट खोले गए हैं।

पेज एक का शेष

देश में...

था, में भी शुक्रवार को सात नए मामले आए हैं। गोवा में कुल मामलों की संख्या अब 14 हो गई है। इसी तरह, मणिपुर में 26 दिनों के बाद एक नया मामला सामने आया है। इस पूर्वोत्तर राज्य में कुल मिलाकर तीन केस हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोनो वायरस संक्रमण के मामलों की दोगुने होने की दर घटकर 13.9 दिन रह गई है।आईसीएमआर के एक अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या शुक्रवार को बीस लाख से ज्यादा हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में अनुसंधान प्रबंधन, नीति योजना और संचार विभाग के प्रमुख डॉ. रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुवार सुबह 9 बजे से 92,911 टेस्ट किए गए हैं। देशभर में शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कुल 20,39,952 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, कोविड-19 के टेस्ट में पिछले दो महीनों में काफी वृद्धि हुई है और इनकी क्षमता प्रति दिन लगभग एक लाख तक बढ़ गई है। श्रीवास्तव ने कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और घरेलू निर्माताओं को अपने कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट को वैध बनाने के लिए आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रयोगशालाओं की संख्या पांच से बढ़ाकर 14 कर दी गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए कोई भी टीका कम से कम 2021 तक ही तैयार हो पाएगा। क्योंकि लाखों लोगों पर इस्तेमाल से पहले इसका व्यापक रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर अब तक 45,27,811 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इस महामारी से 3,03,418 है।

आर्थिक पैकेज...

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू करेगी। इनमें से 11 हजार करोड़ रुपये खारे (समुद्री क्षेत्र) व भूक्षेत्र (मीठे जल) में मत्स्यपालन के लिये होंगे। शेष नौ हजार करोड़ रुपये फिशिंग हार्बर, शीत भंडारण व बाजार जैसी बुनियादी संरचनाओं के लिये होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के असवर मिलेंगे तथा निर्यात भी दो गुना होकर एक लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जायेगा। उन्होंने कहा कि मुंह पका- खुर पका बीमारियों और ब्रूसीलोसिस को लेकर चल रहे राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों का 100 प्रतिशत टीकाकरण किया जायेगा। इस पर 13,343 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अलावा डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मवेशी चारा क्षेत्र में निजी निवेश को समर्थन के लिये 15 हजार करोड़ रुपये का पशुपालन संरचना विकास कोष स्थापित किया जाएगा। औषधीय पौधों और दूसरी जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन के लिये भी 4,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा की गयी। इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों की खेती के तहत लाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों के लिये पांच हजार करोड़ रुपये के आय के सृजन में मददगार होगी। गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में औषधीय गुणों वाले पौधों के लिये एक गलियारा बनाया जायेगा। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मधुमक्खी पालकों के लिये बुनियादी ढांचा विकास को 500 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की गयी। इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि अब हरित अभियान का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू से आगे सभी फलों और सब्जियों तक किया जायेगा। इसके लिये 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष दिया जायेगा। इस राशि का इस्तेमाल इन जिंसों को आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में परिवहन और शीत भंडारण जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी देने में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसान अब अपने उत्पाद औने-पौने दाम पर बेचने के लिये मजबूर नहीं होंगे।

लॉकडाउन फोर...

ने भी इस महामारी को रोकने में काफी अच्छा काम किया है। उसने भी लंबे समय से बंद रेस्टोरेंट, होटल और जिम तथा सार्वजनिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। पीएमओ को भेजे गए प्रस्ताव में तमिलनाडु ने संक्रमण मुक्त जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की है। लेकिन उसके इस अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा क्योंकि यहां पर पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रदेश की राजधानी चेन्नई की एक सब्जी मार्केट से फैले संक्रमण की चपेट में 2600 से ज्यादा लोग आए हैं। बहरहाल यहां सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने कहा कि उसने संक्रमित क्षेत्रों की पहचान कर ली है और 4,623 लोगों क्वारेंटाइन कर दिया है। सोमवार से यहां पर राहत देन के संबंध में कई ऐलान किए गए है जिसमें दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के काम का समय बढ़ाए जाने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। गुजरात में अभी तक 9,591 मामले आ चुके हैं और 586 मौतें हो चुकी है। प्रदेश अब सभी बड़े शहरी इलाकों आर्थिक गतिविधियों को चालू करना चाहता है। जबकि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे तीन बड़े शहरों में राज्य के 80 फीसदी मामले हैं। अकेले अहमदाबाद में 70 फीसदी मामले हैं। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र अपनी आर्थिक गतिविधियों को किसी हद तक खोलने के लिए अडिग है। यहां पर करीब 30,000 मामले आ चुके हैं और 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने मुंबई और अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है. में 16000 केस हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने सरकार ने उद्योगों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। उधर, बिहार, ओडिशा और झारखंड ने दूसरा रास्ता अपनाया है। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी तथा देश भर से प्रवासी मजदूरों की वापसी के मद्देनजर इसमें और इजाफा होने की आशंका के चलते तीनों राज्यों ने सख्त लॉकडाउन की हिमायत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश भी केंद्र के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है। यहां पर अब तक 3,902 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 88 मौत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.3 लाख लोगों को क्वेरंटाइन या आइसोलेशन में भेज चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कहा था ‘हमें सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। मैं कर्फ्यू लगाउंगा। असम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी संकेत दिया कि इस मामले में केंद्र फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार को विचार करने दीजिए क्योंकि यह कोई अकेला कदम नहीं होगा, बल्कि कई कदमों पर विचार करना होगा।

मजदूरों की...

की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया। पीठ ने सवाल किया, ‘‘हम इसे कैसे रोक सकते है?’’ पीठ ने कहा कि राज्यों को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस आवेदन पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। साथ ही उसने टिप्पणी की कि अदालतों के लिये सड़कों पर चल रहे व्यक्तियों की निगरानी करना असंभव है। श्रीवास्तव ने प्रवासी कामगारों की कठिनाईयों से संबंधित निस्तारित की जा चुकी जनहित याचिका में औरंगाबाद के निकट रेलवे लाइन पर 16 श्रमिकों के एक मालगाड़ी से कुचले जाने की घटना के तुरंत बाद यह आवेदन दायर किया था।

रेलवे, दिल्ली...

अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। कई शहरों से झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच दिगी हाई कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अखबारों, टीवी पर विज्ञापन निकालें जाएं ताकि मजदूरों को पता चल सके। अदालत में रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब भी दिल्ली सरकार उनसे ट्रेन उपलब्ध कराने को कहेगी, हम करवा देंगे। दिगी हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल घर जाने का मुद्दा उठाया गया था।

लिपुलेख रोड...

वास्तविक नियंत्रण रेखा तक बनाई गई नई सड़क को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि नेपाल ने किसी और के इशारे पर यह मुद्दा उठाया है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 15,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर लिपुलेख-धारचूला सड़क के खुलने के तुरंत बाद नेपाल ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए भारत से आग्रह किया था कि नेपाल के क्षेत्र के अंदर किसी भी गतिविधि को अंजाम न दिया जाए। नेपाल में इस नई सड़क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। पिछले हफ्ते शनिवार को नेपाल ने भी कहा कि सड़क निर्माण का एकतरफा काम दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों को सुलझाने पर आपसी समझ के खिलाफहै। नेपाल सरकार ने इस संबंध में काठमांडू में भारतीय राजदूत को एक राजनयिक नोट भी दिया। पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया से हैरान सैन्य प्रमुख नरवाने ने कहा कि काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है। उसे लेकर कोई विवाद नहीं है। हमने जो सड़क बनाई है, वह वास्तव में नदी के पश्चिम में है। इसलिए, मैं नहीं जानता कि वे किस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में भी इस पर कोई विवाद नहीं था। नरवाणे ने कहा कि इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल ने किसी और के इशारे पर इस मुद्दे को उठाया है। पिथौरागढ़ में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित यह सड़क चीन की ओर जाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से घटियाबगड़ से लिपुलेख तक सिर्फ पांच किलोमीटर की दूरी पर है। इस सड़क का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह कैलाश मानसरोवर यात्रा को 10 से 12 दिनों तक कम कर देगी।

मानसून एक्सप्रेस...

पांच प्रतिशत की त्रुटि के साथ सामान्य मानसून रहेगा। उस पूर्वानुमान में कहा गया था कि जून के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी जबकि जुलाई का महीना ज्यादातर सूखा बीतेगा लेकिन अगस्त और सितंबर के दौरान जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद है। यह पैटर्न पिछले साल जैसा ही है। हालांकि, मौसम विभाग इस महीने के अंतिम या जून के पहले सप्ताह में मानसूनी वर्षा के माहवार पूर्वानुमान जारी करेगा। इस साल मानसून की स्थिति और अंडमान के समुद्र में इसके आगे बढ़ने की स्थिति पर मौसम विभाग ने कहा कि वर्तमान में कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास बन रहा है। यह अगले 12 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में केंद्रित रहेगा और इसकी वजह से 16 मई तक बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में चक्रवाती तूफान अम्फन आ सकता है।

पायनियर
नई दिल्ली , शनिवार, 16 मई, 2020

रग्बी को झटका, जुलाई में होने वाले टेस्ट कोविड–19 के कारण स्थगित

पेरिस। जुलाई में होने वाले सभी रग्बी टेस्ट मैचो को कोरेना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। विश्व रग्बी ने शुक्रवार को यह घोषणा की। विश्व रग्बी ने कहा कि कोविड-19 के कारण चल रहे पृथक्वास और यात्रा संबंधित पांबंदियो के कारण इन्हे आयोजित करना असंभव था। यह फैसला फिर से रग्बी के लिए झटका है जिससे क्लबो को राजस्व मे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि इस महामारी से पूरी दुनिया मे पेशेवर खेल ठप्प है। विश्व रग्बी ने बयान मे कहा, कई देशो मे यात्रा और पृथक्वास संबंधित पांबंदियों को बढ़ाने से खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए उचित समय मिलने की चिंताएं है जिसका मतलब है कि जुलाई मे किसी भी सीमा के बाहर अंतरराष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता की मेजबानी नही की जा सकती।

पूर्व बेसबॉल स्टार बॉब वाटसन का निधन

ह्यूस्टन। मेजर लीग बेसबॉल (एमएलबी) में अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी रहे बॉब वाटसन का निधन हो गया है। वह 74 साल के थे। वाटसन ने ह्यूस्टन एस्ट्रोज के साथ 14 सत्र तक मेजर लीग खेली थी। इस क्लब ने गुरुवार की रात को उनके निधन की घोषणा की। वाटसन बाद मे विश्व सीरीज जीतने वाले पहले अश्वेत महाप्रबंधक बने थे। उन्होंने 1996 मे न्यूयार्क यांकीज के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्हे दो बार ऑल स्टार टीम मे भी चुना गया था।

अभ्यास में अपनी अलग अलग गेंदों का इस्तेमाल करेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर

लंदन। इंग्लैड के क्रिकेटर वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व निर्धारित टेस्ट श्रृंखला से पहले जब अगले सप्ताह अभ्यास पर लौटेंगे तो उनमें से प्रत्एक को खुद के उपयोग के लिए गेदो का एक बॉक्स सौपा जाएगा जिन पर वे लार नही लगा सक्ते है। इंग्लैड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी सभी गतिविधियां जुलाई तक निलंबित कर रखी है। उन्होंने कहा कि इन गर्मियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए 30 क्रिकेटरो को तैयार रखा जाएगा।

श्रीलंका ने बीसीसीआई से जुलाई में दौरे की संभावना तलाशने को कहा

कोलंबो। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे पर बरकरार अनिश्चितता के बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एससीएल) ने बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) से अनुरोध किया है कि वे जुलाई में इस निर्धारित श्रृंखला के लिए दौरा करने पर गंभीरता से विचार करें। भारतीय टीम के आगामी कार्यक्रम में जून-जुलाई मे श्रीलंका का दौरा शामिल है जहां टीम को तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हालांकि इस दौरे पर संशय बरकरार है।

टल सकता है टी-20 विश्व कप

● 28 को विचार कर सक्ते है आईसीसी बोर्ड के सदस्य

भाषा। नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप को 2022 तक टालने पर विचार कर सकता है। आईसीसी के बोर्ड सदस्यों की 28 मई को बैठक होने वाली है और बोर्ड के एक सदस्य ने शुक्रवार को पीटीआई–भाषा से कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट को टालने पर विचार कर सकता है। बोर्ड के इस सदस्य के मुताबिक कोविड–19 महामारी के कारण टी20 विश्व कप पर संशय बरकरार है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है। आईसीसी के इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रस्तावित है। आईसीसी बोर्ड की बैठक से पहले क्रिकेट समिति की बैठक है जिसमें गेंद पर पसीना और लार लगाने सहित कई परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि क्रिस टेटली की अध्यक्षता वाली आईसीसी की प्रतियोगिता समिति कई विकल्प पेश करेगी। बोर्ड के सदस्य ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई–भाषा से कहा, हम आईसीसी की प्रतियोगिता समिति से तीन विकल्पों की उम्मीद कर रहे हैं। पहला विकल्प 14 दिन के पृथकवास के साथ विश्व टी 20 विश्व कप का आयोजन हो जिसमें दर्शकों की अनुमति है। इसमें दूसरा विकल्प है कि मैच खाली स्टेडियम में हो। तीसरा विकल्प है कि टूर्नामेंट को 2022 के लिए स्थगित कर दिया जाए। बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष शशांक मनोहर के लिए दो महीने के विस्तार पर भी चर्चा होगी लेकिन मुख्य रूप से ध्यान टी 20 विश्व कप पर फैसला करने पर होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनके मौजूदा और पूर्व शीर्ष खिलाड़ी भारत के साथ टेस्ट श्रृंखला करने पर जोर दे रहे है जिसे नवंबर दिसंबर में खेला जाना है। यह श्रृंखला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर टी20 विश्व कप को 2022 तक टाला जाता है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत दुखी नहीं होगा। आईसीसी सदस्यों से बना है। यदि सदस्य यह तय करते हैं कि द्विपक्षीय श्रृंखला अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप इसे खारिज नहीं

भारत के खिलाफ शानदार पदार्पण की बदौलत जैमीसन न्यूजीलैंड के अनुबंधित खिलाड़ियों में

वेलिंगटन। तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने साल के शुरू में भारत के खिलाफ अपने शानदार टेस्ट पदार्पण की बदौलत न्यूजीलैंड के 2020-21 सत्र के लिए अनुबंधित खिलाड़ियों में जगह हासिल की। पच्चीस साल के जैमीसन को भारत के खिलाफ वनडे पदार्पण मे मैन आफ द मैच पुरस्कार हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने हेगले ओवल में दूसरे टेस्ट में पांच विकेट हासिल कर प्लेयर आफ द मैच पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने विराट कोहली की टीम के खिलाफ दो टेस्ट में नौ विकेट चटकाए थे। चयन मैनेजर गाविन लार्सन ने मीडिया को दिए बयान मे कहा, काइल ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और 25 साल की उम्र मे वह निश्चित रूप से हमारा भविष्य है। बांए हाथ के स्पिनर एजाज पटेल और दक्षिण अफ्रीका मे जन्मे डेवोन कॉनवे को भी अनुबंध दिया गया है। कॉनवे को तीन साल देश में बिताने के अनिवार्य नियम से पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर दिया है क्योंकि मुख्य कोच गेविन लार्सन को लगता है कि उनकी शानदार फार्म को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह 28 वर्षीय बल्लेबाज हालांकि अगस्त तक टीम मे चयन की पात्रता हासिल नही कर पाएगा लेकिन वह न्यूजीलैंड के 20 अनुबंधित क्रिकेटरो मे शामिल तीन नए खिलाड़ियों मे से एक है। जैमीसन और पटेल को भी एलीट वर्ग मे रखा गया है। कोलिन मुनरो और जीत रावल को सूची से बाहर कर दिया गया है जबकि टॉड एस्टल ने जनवरी मे संन्यास ले लिया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे 2017 मे न्यूजीलैंड मे बस गए थे और तब से उन्होने तीनो प्रारूपो मे बेहतरीन प्रदर्शन किया और बल्लेबाजी सूची मे शीर्ष पर रहे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी पर जब वह टीम मे चयन की पात्रता हासिल करेंगे तो फिर टेस्ट सलामी बल्लेबाज रावल और सीमित ओवरो के बल्लेबाज मुनरो के लिए जगह नही बचेगी।

पांच-छह टीमों के साथ आईपीएल महिला क्रिकेट के लिए शानदार होगा: मंधाना

नई दिल्ली। भारत की विस्फोटक सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को लगता है कि एक पूर्ण महिला इंडियन प्रीमियर लीग प्रतिभाओ को तलाशने में काफी अंतर पैदा कर सकती है जिससे राष्ट्रीय टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। तेईस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने माना कि बीसीसीआई इसे साकार करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। उन्होंने बीबीसी पोडकास्ट पर द दूसरा में कहा, बीसीसीआई ने काफी प्रयास किए है, पहले हमारे लिए दो साल पहले प्रदर्शनी मैच की तरह का महिला आईपीएल आयोजित किया, फिर इसके बाद तीन टीमों का बहुत सफल आईपीएल रहा। इस साल इसे चार टीमों के बीच होना था। मुझे पूरा भरोसा है कि एक या दो साल के लिए आईपीएल की तरह के कई मैच आयोजित होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए पांच या छह टीम का आईपीएल शानदार होगा, विशेषकर विश्व कप को देखते हुए। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि देश में महिला क्रिकेट में अभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मे जो अंतर है, वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। भारत मे महिला क्रिकेट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विशेषकर घरेलू सर्किट मे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्किट के टूर्नामेंट मे काफी अंतर है और मुझे लगता है कि यह भी दो-तीन साल में खत्म हो जाएगा।

महिलाओं के घरेलू मैचों को कम नहीं करें: हीली

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने कहा कि वित्तीय परेशानी का सामना कर रहे उनके बोर्ड को महिलाओ के घरेलू मैचो की संख्या को कम नही करना चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण लाखों डॉलर का घाटा झेल रहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सत्र को छोटा करने का विचार कर रहा है। घरेलू महिला प्रतियोगिता मार्श शेफील्ड शील्ड और महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के मुकाबले पुरूष क्रिकेट की तरह आकर्षक नही होते है। हीली ने हालांकि कहा कि महिलाओ के मैचो को कम करना प्राथमिकता नही होनी चाहिए।हीली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट संघ (एसीए) की बोर्ड निदेशक भी है। उन्होंने द अनप्लेएबल पोडकास्ट से कहा, जाहिर है यह अच्छा नही होगा। हम नही चाहते की मैच कम हो। खास तौर पर डब्ल्यूबीबीएल (महिला बिग बैश लीग) के मुकाबलो को कम नही किया जाना चाहिए। यह शानदार टूर्नामेंट है और हम अपना ज्यादातर क्रिकेट इसी मे खेलते है। हमे घरेलू प्रतियोगिताओं मे 50 ओवर के मैचो को खेलने का ज्यादा मौका नही मिलता। हम नही चाहते कि मैचो की संख्या घटे। मुझे नही लगता कि हमारे घरेलू क्रिकेटरो को ज्यादा खेलने का मौका मिलता है।

हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान स्वदेश लौटे

नई दिल्ली। भारत की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक दीवान ने गुरुवार की सुबह स्वदेश लौटने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य मे लगातार सुधार हो रहा है और वह अपने देश पहुंचने पर अच्छा महसूस कर रहे है। विश्व कप 1975 की चैंपियन टीम के गोलकीपर दीवान कोविड-19 के चलते यात्रा पाबंदियो के कारण अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैक्रामेंटो मे फंस गए थे जहां से उन्हें 20 अप्रैल को वापस लौटना था। इस 65 वर्षीय खिलाड़ी ने तबीयत खराब होने के बाद खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से मदद मांगी थी। वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। दीवान ने स्वदेश लौटे पर आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को भेजे गए पत्र मे उनका आभार व्यक्त किया। मै आज सुबह स्वदेश लौट गया हूं और भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार 14 दिन के पृथक्वास पर चला गया हूं। मै स्वदेश लौटने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस मुश्किल दौर मे सीनियर खिलाड़ियों, साथियो, हाकी प्रेमियो, मित्रो और परिजनो ने मेरा हौसला बनाए रखा। मेरे स्वास्थ्य मे सुधार हो रहा है। मै इस मुश्किल समय मे सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने खेल मंत्री किरेन रीजीजू और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिका मे भारतीय राजदूत तरणजीत संधू का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। दीवान 1976 के मांट्रियल ओलंपिक मे भी भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्हें हॉकी मे योगदान के लिए 2002 मे ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था।

गांगुली के पास आईसीसी का नेतृत्व करने की राजनीतिक क्षमता: गॉवर

नई दिल्ली। इंग्लैड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर का मानना है कि सौरव गांगुली के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का नेतृत्व करने के लिए जरूरी राजनीतिक कौशल है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में खुद को पहले ही साबित कर दिया है जो बहुत कठिन काम है। गॉवर दुनिया के सबसे कलात्मक वामहस्त बल्लेबाजों में एक माने जाने वाले गांगुली के नेतृत्व क्षमता से प्रभावित है। उनका मानना है कि उनके पास भविष्य में वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने के लिए जरूरी समझ है। गॉवर ने ग्लोफैंस के चैट कार्यक्रम क्यू20 से पहले कहा, मैने इतने वर्षो मे जो कुछ सीखा है, वह यह है कि बीसीसीआई का संचालन करने के लिए अपके पास कई तरह का कौशल और समझ होने चाहिए। उनकी (गांगुली) जैसी प्रतिष्ठा होना (बोर्ड के लिए) बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आपको एक बहुत ही विनम्र राजनीतिज्ञ होने की जरूरत है। लाखों चीजों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। गॉवर ने कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद विश्व क्रिकेट में सबसे मुश्किल कामो में से एक है। जाहिर है आपको काफी जिम्मेदार होना होगा, भारत मे इस खेल के एक अरब से ज्यादा प्रशंसक है। गॉवर ने कहा कि प्रशासनिक कार्यो के लिए राजनीतिक समझ जरूरी है और उन्हें लगता है कि गांगुली इसके लिए सही है। वह शानदार इंसान है और उनके के पास राजनीतिक क्षमता है। उनका रवैया सही है और चीजो को साथ रख सक्ते है।

साइ ने केंद्रों के लिए एसओपी तैयार की

● लेकिन गृह मंत्रालय मंजूरी के बाद ही शुरू होगी ट्रेनिंग

भाषा। नई दिल्ली

अगर इस महीने के अंत में खिलाडि़यों की ट्रेनिंग शुरू होती है तो भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने कोविड–19 महामारी से बचने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें कम वेंटीलेशन वाले चेंजिंग रूम हटाए जाने, ट्रेनिंग उपकरणों को इस्तेमाल के बाद हर बार संक्रमण रहित करना, शिफ्ट में जिम के इस्तेमाल के अलावा स्पारिंग पर प्रतिबंध शामिल है। साइ ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विस्तृत मसौदा तैयार किया है जिनका इस महीने के अंत में अपने ट्रेनिंग केंद्रों को फिर से खोलने से पहले पालन किया जाएगा जैसा कि खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने सुझाव दिया था लेकिन यह स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही होगा। सचिव रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली छह सदस्ईय समिति ने 33 पन्ने का दस्तावेज बनाया है, जिसे अभी खेल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिया जाना बाकी है। इस दस्तावेज में प्रस्तावों के अनुसार इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए आरोग्य सेतु एप सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, ट्रेनिंग स्थलों पर कड़ाई से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा, ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों को पीपीई किट का इस्तेमाल करना होगा, स्वच्छता संबंधित उपायों को बढ़ाना होगा और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखना शामिल है। साइ के एक सूत्र ने पीटीआई–भाषा से कहा, समिति ने एक व्यापक एसओपी की रूपरेखा तैयार की है लेकिन इसमें बदलाव किया जा सकता है। यह पहला मसौदा है जिसे अभी खेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलनी बाकी है। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि एसओपी को ऐसे ही पारित कर दिया जाए। साइ ने इस दस्तावेज को राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के पास भेज दिया कि वे सिफारिशों में अपना पक्ष दे सकें। अंत में ट्रेनिंग फिर से शुरू होना गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा। अगर एमएचए तीसरे लॉकडाउन के बाद अपने आगामी दिशानिर्देशों में खेल गतिविधियों पर रोक बरकरार रखता है जैसा कि पिछले दिशानिर्देशों में था तो खेल मंत्रालय ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सकता।

अर्जुन पुरस्कार की अनदेखी से खफा पंघाल ने रीजीजू से चयन प्रक्रिया बदलने का आग्रह किया

नई दिल्ली। एशियाई खेलो के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल ने शुक्रवार को खेल मंत्री कीरेन रीजीजू से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारो के लिए चयन प्रक्रिया बदलने का अनुरोध किया और मौजूदा तरीके को भेदभावपूर्ण करार दिया। वर्ष 2012 में अनजाने में हुए डोप अपराध के लिए लगातार अर्जुन पुरस्कार के लिए उनकी अनदेखी होती रही है। मंत्री को लिखे पत्र मे पंघाल ने कहा कि खिलाड़ियो को खुद का नामांकन कर आवेदन नही करना चाहिए। पिछले साल विश्व चैम्पियनशिप का रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरूष मुक्केबाज बने पंघाल ने पत्र में कहा, मौजूदा प्रक्रिया मे एक खिलाड़ी को आवेदन भेजना होता है और फिर खेल समिति इन आवेदनो के आधार पर चयन करती है। पुरस्कार चयन में खेल समिति के सदस्यो द्वारा भेदभावपूर्ण फैसले होते हैं जिनकी कोई जवाबदेही नही है। पंघाल दो बार अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए जा चुके है लेकिन पूर्व के डोप उल्लंघन के कारण उनके नाम पर विचार नही किया गया। उन्होंने 2012 मे चेचक के उपचार के लिए दवाई ली थी।

अगले साल सिंथेटिक शटल के इस्तेमाल के फैसले को टाल सकता है बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली। विश्व बैडमिंटन संघ (बीडब्ल्यूएफ) कोविड–19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अगले साल सिंथेटिक शटल के इस्तेमाल की अपनी योजना से पीछे हट सकता है। इस साल जनवरी में इस वैश्विक संस्था ने 2021 से सभी स्तरों के मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सिंथेटिक पंख वाली शटल के उपयोग को मंजूरी दी थी। वर्तमान में उपयोग में आने वाली शटल आमतौर पर हंस या बत्तख के पंख से बनी होती हैं। योनेक्स सनराइज (भारत) के प्रमुख विक्रम धर का हालांकि मानना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसे लागू करने में एक और साल लग सकता है। कोविड–19 महामारी के कारण लगभग सभी बैडमिंटन टूर्नामेंटों को स्थगित कर दिया है, जिससे उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। धर से जब सिंथेटिक शटल के 2021 में उपयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पीटीआई से कहा, इसमें समय लगेगा, इसमें एक और साल लग सकता है। योनेक्स के तकनीकी सहयोग से विकसित सिंथेटिक शटल का बीडब्ल्यूएफ ने अनुमोदन किया था। इसे पक्षियों के पंखों के बजाय प्लास्टिक से बनाया गया है।

ओलंपिक जाने वाले हॉकी खिलाड़ियों को मैदान पर अभ्यास शुरू करना चाहिए : सरदार सिंह

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और स्टार प्लेमेकर रहे सरदार सिंह का मानना है कि ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियो को छोटे समूहो मे मैदान पर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए क्योकि करीब दो महीने से मैदान से दूर रहे शरीर को लय पकड़ने मे समय लगेगा। भारतीय हॉकी के सबसे फिट खिलाड़ियो मे से एक रहे सरदार ने अपने गांव संतनगर से भाषा को दिए इंटरव्यू मे कहा , ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास शुरू करना चाहिए लेकिन अभ्यास केंद्र पर स्वास्थ्य सुविधा का खास ख्याल रखा जाए। खिलाड़ियो को कोचो को पूरी ईमानदारी से हर बात बतानी होगी मसलन किसी को कोई शारीरिक परेशानी है तो मैदान पर नही आए। कोरोना वायरस महामारी के बाद खेल बिल्कुल बदल जाने वाले है और ऐसे मे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अभ्यास शुरू करना होगा। कोरोना महामारी के बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमे 24 मार्च से ही भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरू केंद्र मे है। खिलाड़ियो ने गुरुवार को खेलमंत्री किरेन रीजीजू से आनलाइन बैठक मे अभ्यास बहाल कराने का अनुरोध किया।

प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मिलेगी राहत: उद्योग जगत

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की बृहस्पतिवार को घोषित दूसरी किस्त का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित समाज के सबसे कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, आवास क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन (बंद) के कारण पस्त हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए के दूसरे चरण के आर्थिक पैकेज का बृस्पतिवार को ऐलान किया। इसमे प्रवासी मजदूरो को दो महीने तक मुफ्त अनाज, किसानो को 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज और रेहड़ी पटरी वालो को जरूरी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। उद्योग संगठन फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा, आज की घोषणाएं प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को आगे बढ़ाती है और इसमे कई नए आयाम जोड़ती है। हमे उम्मीद है कि सरकार ने इन योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारो के साथ मिलकर योजना बनाई है, जिनकी इसमे प्रमुख भूमिका होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त ने प्रवासी मजदूरो, किसानो, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओ और जनजातीय समुदायो के लोगो समेत कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित वर्ग को राहत पहुंचाने पर सही तरीके से केंद्रित है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.235 अरब डॉलर बढ़कर 485.31 अरब डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार आठ मई को समाप्त सप्ताह में 4.235 अरब डॉलर बढ़कर 485.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विदेशीमुद्रा परिसंपत्तियां बढ़ने से यह वृद्धि हासिल हुई है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 1.622 अरब डालर बढ़कर 481.078 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। देश का विदेशीमुद्रा भंडार इससे पहले छह मार्च को 5.69 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 487.23 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशीमुद्रा भंडार करीब 62 अरब डॉलर बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ो के अनुसार आठ मई, 2020 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (जो विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है) 4.233 अरब डॉलर बढ़कर 447.548 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार भी 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 32.291 अरब डॉलर हो गया। मार्च 2020 की समाप्ति पर रिजर्व बैंक के पास 653.01 टन सोने का भंडार था। इसमें से 360.71 टन विदेशो मे रखा गया है। वही, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का विशेष आहरण अधिकार 30 लाख डॉलर घटकर 1.423 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ मे देश की आरक्षित भंडार की स्थिति भी 80 लाख डॉलर घटकर 4.051 अरब डॉलर रह गई।

ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर बातचीत से इनकार किया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर बातचीत करने से इनकार कर दिया है और साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बीजिंग के तरीके पर निराशा व्यक्त की है। कोरोना वायरस से दुनिया भर मे तीन लाख से अधिक लोगो की मौत हो चुकी है, जिसमें से 80,000 सिर्फ अमेरिका से है। अमेरिका और चीन ने इस साल की शुरुआत मे व्यापार समझौते के पहले चरण पर दस्तखत किए थे, जिसके साथ माना गया कि दो साल से चल रहे व्यापार युद्ध का अंत हो गया। ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को बताया, चीन ने कही कहा है कि वे (व्यापार) समझौते पर फिर बातचीत करना चाहते है। हम फिर से बातचीत नही करेंगे। देखिए, मै फिलहाल उस बारे में (चीन) कुछ भी करने का इच्छुक नही हूं। मैंने जो भी कहा वह सही निकाला।

देश में लगातार चौथे वर्ष रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद

● 29 करोड़ 56 लाख टन उत्पादन का अनुमान

भाषा। नई दिल्ली

देश में कृषि उत्पादन लगातार चौथे वर्ष नए रिकार्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। मानसून की अच्छी वर्षा से फसल वर्ष 2019–20 में 29 करोड़ 56 लाख 70 हजार टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय के शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, इस साल खाद्यान्न की अनुमानित पैदावार, पिछले साल के मुकाबले 3.67 प्रतिशत अधिक होगा। वर्ष के दौरान खाद्याान्न उत्पादन वर्ष 2019–20 के बुवाई मौसम से पहले लगाए गए उत्पादन अनुमान 29 करोड़ 11 लाख टन को भी लांघ जाएगा ऐसा अनुमान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ (गर्मी) और रबी (सर्दियों) दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली फसलें शामिल हैं। कोविड–19 वायरस के जारी संकट के बीच रबी फसलों की कटाई का काम अपने अंतिम चरण में है। फसलवर्ष 2016–17 (जुलाई–जून) के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का यह लगातार चौथा वर्ष है। पिछला रिकॉर्ड फसल वर्ष 2018–19 के दौरान 28 करोड़ 52 लाख टन का था। देश में मानसून सत्र (जून से सितंबर 2019) के दौरान कुल वर्षा दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि वर्ष 2019–20 में अधिकांश फसलों का उत्पादन, उनके सामान्य उत्पादन से कहीं अधिक होने का अनुमान है। सभी फसलों में मुख्य रबी फसल – गेहूं का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 10 करोड़ 72 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 10 करोड़ 36 लाख टन था। गेहूं की फसल की कटाई पूरी होने के अंतिम चरण में है। इसी तरह, मुख्य खरीफ फसल, चावल का उत्पादन इस साल 11 करोड़ 79 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 11 करोड़ 65 लाख टन के उत्पादन से अधिक है। मोटे अनाजों का रिकॉर्ड उत्पादन यानी चार करोड़ 75 लाख टन होने का अनुमान है, जो उत्पादन पिछले साल चार करोड़ 30 लाख टन का हुआ था।

प्रोत्साहन पैकेज से राजकोषीय घाटे पर 1.29 लाख करोड़ रुपए का पड़ेगा प्रभाव: एसबीआई रिपोर्ट

भाषा। नई दिल्ली

सरकार की कोविड–19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए बृस्पतिवार तक की गई प्रोत्साहन पैकेज की घोषणाओं से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे पर 0.6 प्रतिशत यानी 1.29 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। समाज के कमजोर तबकों को ध्यान में रखकर बृस्पतिवार को की गई घोषणा के साथ सरकार अब तक कुल 16.45 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उसमें से अब करीब 3.54 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रमों की और घोषणा की जानी है। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार, बृस्पतिवार को 3.16 लाख करोड़ रुपए की घोषणा में से सरकार का कुल नकद व्यय 14,500 से 14,750 करोड़ रुपए होगा। बृस्पतिवार के पैकेज का राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जीडीपी का मामूली 0.07 प्रतिशत होगा। इसमें कहा गया है कि हाल के संकट ने भारत जैसे बड़े देश के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित किया है। इससे केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तरीके से व्यवस्थाा काम करती है।

शेयर बाजारों में मामूली गिरावट, प्रोत्साहन पैकेज के वित्तीय प्रभाव को लेकर निवेशक चिंतित

भाषा। मुंबई

उतार–चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों की सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के वित्तीय प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ने से शेयर बाजार नीचे आया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों को इस बात की चिंता है कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से प्रत्यक्ष और तत्काल मांग में वृद्धि की संभावना संभवत: नहीं है, उन्हें इसको लेकर निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने को लेकर भी शंका है। कारोबार के दौरान 350 से अधिक अंक टूटने के बाद 30

शेयरों वाला सेंसेक्स बाद में नुकसान से काफी हद तक उबरा और अंत में यह 25.16 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 31,097.73 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, एनएसई निफ्टी 5.90 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9,136.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में महिंद्रा एंड महिंद्रा रही। इसमें 4.70 प्रतिशत की गिरावट आई।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकता है 8,800 अरब डॉलर का नुकसान: एडीबी

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है। इसमे दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक असर होगा। एडीबी ने एक रिपोर्ट मे कहा, कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है, वैश्विक जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के बराबर है। एडीबी ने कोविड-19 के संभावित आर्थिक असर के नए मूल्यांकन मे कहा कि दक्षिण एशिया की जीडीपी में 3.9 प्रतिशत से छह प्रतिशत तक कमी आएगी।

प्रवासी मजदूरों को वितरण के लिए राज्य गोदामों में पर्याप्त अनाज भंडार: पासवान

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यो मे स्थिति गोदामो मे पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। राज्य आठ करोड़ प्रवासी मजदूरो के बीच मुफ्त वितरण के लिए शुक्रवार से इसे उठा सक्ते है। मुफ्त अनाज उन प्रवासी मजदूरो को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नही है। पासवान ने प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो चना दाल मुफ्त दिए जाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए दूसरे चरण मे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए प्रवासी मजदूरो को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का एलान किया। पासवान ने इस घोषणा के बाद पीटीआई-भाषा से कहा, राज्य स्थित गोदामो मे पर्याप्त अनाज का भंडार पड़ा है।

डब्ल्यूटीओ प्रमुख एजेवेदो अपना पद छोड़ेंगे

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके प्रमुख राबर्ट ऐजेवेदो 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। वह व्यक्तिगत कारणो से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले छोड़ रहे है। भारत जिनेवा स्थित विश्व व्यापर निकाय के संस्थापक सदस्यो मे से एक है। डब्ल्यूटीओ को वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

सीमा गुप्ता पावर ग्रिड की वित्त निदेशक

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा कि उसकी निदेशक (परिचालन) सीमा गुप्ता ने कंपनी के वित्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने एक बयान मे कहा, बिजली मंत्रालय ने 14 मई को एक आदेश मे पावरग्रिड की निदेशक (परिचालन) सीमा गुप्ता को निदेशक वित्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी छह मई से तीन महीने या नियमित नियुक्ति होने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए सौपी है।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हैं सबसे अधिक रेहड़ी पटरी वाले

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मे सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले है, जो देश की कुल संख्या के मुकाबले एक चौथाई है।

कम चर्चित कंपनियों ने ओएनजीसी के 49 तेल, गैस फील्ड हासिल किए

नई दिल्ली। दुगान्ता ऑयल एंड गैस और ओडिशा स्टीवेडोर्स लि. जैसी कम चर्चित कंपनियों ने ओएनजीसी के 49 छोटे एवं सीमांत तेल एवं गैस फील्डो को हासिल किया है। सरकार के निर्देश पर ओएनजीसी ने इन तेल एवं गैस कुओं के लिए बोलियां मंगाई थी।

वुहान स्थित एक फैक्ट्री के कर्मचारियों की कोविड 19 की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी

अमेरिकी सांसद ने चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजना पेश की

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनाने वाले उसके कथित झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है इसके अलावा अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। सीनेटर थोम टिलिस ने बृहस्पतिवार को अपनी 18 सूत्री योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा, चीन सरकार ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और ऐसी वैश्विक महामारी फैलाई जो हजारों अमेरिकियों के लिए विपत्ति लेकर आई।

यह वही शासन है जो अपने ही नागरिकों को श्रम शिविरों में बंद करके रखता है, अमेरिका की प्रौद्योगिकी एवं नौकरियां चुराता है और हमारे सहयोगियों की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा, यह अमेरिका और समूचे स्वतंत्र विश्व के लिए बड़ी चेतावनी है। मेरी कार्ययोजना चीनी सरकार को कोविड-19 के बारे में झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जन स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखते हुए चीनी सरकार को प्रतिबंधित करेगी। इस कार्य योजना में प्रशांत प्रतिरोध पहल शुरू करने और वित्तपोषण के लिए 20 अरब डॉलर के सैन्य अनुरोध को तत्काल स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई गई है। इसमें क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने और भारत, ताइवान एवं वियतनाम को उपकरणों की बिक्री

● इस कार्य योजना में प्रशांत प्रतिरोध पहल शुरू करने और वित्तपोषण के लिए 20 अरब डॉलर के सैन्य अनुरोध को तत्काल स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई गई है

बढ़ाने की भी अपील की गई है। इसमें कहा गया कि जापान को अपनी सेना का फिर से निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा जापान एवं दक्षिण कोरिया को आक्रामक सैन्य उपकरणों की पेशकश की जाए। योजना में कहा गया, चीन से सारी उत्पादन इकाइयां वापस अमेरिका लाई जाएं और धीरे-धीरे आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चीन पर निर्भरता समाप्त की जाए। चीन को हमारी प्रौद्योगिकी चुराने से रोका जाए तथा हमारे प्रौद्योगिकीय फायदे फिर से प्राप्त करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए। चीन की हैकिंग एवं गड़बड़ियों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा मजबूत की जाए। इसमें कहा गया, अमेरिकी करदाताओं के पैसे का चीनी सरकार द्वारा अपना कर्ज चुकाने में प्रयोग किया जाना रोका जाए। हुआवे (चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी) पर अमेरिकी प्रतिबंध को लागू किया जाए और इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ समन्वय करें। इसके अलावा इस योजना में चीनी सरकार से मुआवजा मांगने तथा वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन को उसके अत्याचारी मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।चीन ने कोरोना वायरस प्रकोप की भयावहता को छिपाने संबंधी अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है। उसने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह वुहान की विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला में वायरस की उत्पत्ति का दावा कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने पिछले महीने कहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को कोविड-19 की जानकारी देने वाला पहला देश चीन था और इसका यह मतलब नहीं है कि वायरस वुहान से पनपा है। कभी कोई जानकारी नहीं छिपाई गई और न ही कोई जानकारी छिपाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एक झलक में समझ जाएगा कि मकसद भ्रम पैदा करना, लोगों का ध्यान भटकाना और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सांसद टिलिस की योजना में ट्रंप प्रशासन से, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से औपचारिक तौर पर अनुरोध कर बीजिंग से 2020 शीतकालीन ओलंपिक वापस लेने की अपील भी की गई है।

अमेरिका ने बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को रिहा करने की चीन से की अपील

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका ने चीन से अपील की है कि वह तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु 11वें पंचेन लामा को रिहा करे। पंचेन लामा जब छह साल के थे, तभी चीनी प्राधिकारियों ने उन्हें कैद कर लिया था। तिब्बत के गेझुन चोएक्ई न्ईमा को 1995 में 11वां पंचेन लामा घोषित किया गया था। तिब्बत में दलाई लामा के बाद पंचेन लामा बौद्ध धर्म से जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक पद है। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही न्ईमा लापता हो गए थे और वह दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी बन गए थे। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के विशेष दूत सैम ब्रॉउनबैक ने बृहस्पतिवार को एक सम्मलेन के दौरान संवाददाताओं से कहा, वह कहां हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और हम पंचेन लामा को रिहा करने का दबाव चीनी प्राधिकारियों पर डालते रहेंगे। दुनिया को बताया जाए कि वह कहां हैं। ब्राउनबैक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन अगला दलाई लामा नियुक्त करने के अधिकार में बारे में लगातार बात करता रहता है, जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसी बीच, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाले अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने विदेश मंत्रालय से पुन: मांग की है कि वह तिब्बती मामले के विशेष समन्वयक के पद पर भर्ती करे।

न्यूयॉर्क बच्चों में कोविड संबंधित सूजन की दुर्लभ बीमारी के 110 मामलों की जांच कर रहा : गवर्नर

भाषा। न्यूयॉर्क

अमेरिका में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के केंद्र रहे न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारी बच्चों में कोविड-19 से संबंधित सूजन की दुर्लभ बीमारी के 110 मामलों की जांच कर रहे हैं। शहर के गवर्नर ने स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि इससे तीन बच्चों की जान चली गई है।बच्चों में गंभीर बीमारी और बच्चों की मौत, सूजन की गंभीर बीमारी से संबंधित है जिसे कोविड-19 से जुड़ा पीडियाट्रिक मल्टी-सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है।

अब तक, पांच और सात साल के दो लड़कों और 18 साल की किशोरी की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस पर नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि न्यूयॉर्क स्वास्थ्य विभाग अब बच्चों में कोविड-19 संबंधी बीमारी के 110 मामलों को देख रहा है जो कवासाकी बीमारी या टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम जैसा है और उन्होंने स्थिति को गंभीर एवं चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क राज्य एवं स्वास्थ्य विभाग इस दुर्लभ बीमारी की जांच करने में अमेरिका में सबसे आगे है। न्यूयॉर्क के अलावा, 16 अन्य राज्य भी इसी तरह के मामलों को देख रहे हैं। क्यूमो ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों-हफ्तों में मामले बढ़ सकते हैं और कहा है कि परिजनों को सतर्क रहना चाहिए तथा बच्चे को पांच दिन से ज्यादा बुखार रहने, शिशुओं को स्तनपान या कोई भी पेय पीने में दिक्कत होने, पेट में बहुत दर्द होने, दस्त या उलटी, त्वचा के रंग में बदलाव, सांस लेने में तकलीफ, आलसपन, चिड़चिड़ापन या भ्रम होने की स्थिति में तत्काल चिकित्सीय मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह बीमारी उन बच्चों में हो रही है जो कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं और अब उनके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी (प्रतिरक्षी) हैं या वे अब भी वायरस से संक्रमित हैं। यह बीमारी एक साल से कम के शिशु से लेकर 21 साल तक के किशोरों को प्रभावित कर रही है।क्यूमो ने कहा, जब आपको 100 से अधिक मामले देखने को मिलते हैं, जो कि इसका प्रसार बताते हैं, तो यह निश्चित तौर पर डराने वाली बात है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डे ब्लासियो ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी दुर्लभ बीमारी का बच्चों में पाया जाना, बेहद चिंतित करने वाला है क्योंकि अब तक कोरोना वायरस से बच्चे बहुत कम प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भले ही यह अब भी दुर्लभ स्थिति है लेकिन शहर के अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और बेहद सतर्क हो गए हैं।उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में 100 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55 में या तो कोविड-19 की पुष्टि हुई है या वे एंटीबॉडीज की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बाल रोग चिकित्सकों द्वारा जल्द इस बीमारी का पता लगाना और बच्चों को विशेषज्ञों के पास भेजना आवश्यक है। न्यूयॉर्क में पांच साल के बच्चे की कोविड-19 संबंधी दिक्कतों के कारण मौत हो गई जबकि न्यूयॉर्क में सात साल के एक बच्चे ने मारिया फरेरी बाल अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस सिंड्रोम ने हाल के हफ्तों में सबका ध्यान खींचा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित यूरोपीय देशों में ऐसे मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैज्ञानिक, डॉ मारिया वान केरखोवे ने कहा, कुछ यूरोपीय देशों में हाल में बच्चों में इस दुर्लभ बीमारी के वाकए सामने आए हैं जो कवासाकी सिंड्रोम से मिलती-जुलती है लेकिन यह बहुत दुर्लभ प्रतीत हो रहे हैं।

कोविड-19: पाकिस्तान शनिवार से शुरू कर देगा घरेलू उड़ानें

भाषा। इस्लामाबाद

देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में कुछ ढील देने के बाद पाकिस्तान शनिवार से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों का संचालन फिर से शुरू करेगा। कोरोना वायरस संक्रमण से पाकिस्तान में अब तक 800 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

पाकिस्तान सरकार ने पिछले सप्ताह कहा था कि अर्थव्यवस्था और कामकाज पर लॉकडाउन के प्रभाव के चलते इसे (लॉकडाउन को) चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान नागर विमानन प्राधिकरण (पीसीएए) ने शनिवार से घरेलू उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने की घोषणा की।पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और सेरेने एयर सुबह और दोपहर में उड़ान संचालित करेंगी। बयान में कहा गया कि 68 उड़ान कराची में जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, 32 लाहौर में अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, 32 इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, आठ क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से और चार पेशावर में बाचा खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार, 1,430 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 37,218 तक पहुंच गई। वायरस से अब तक कुल 10,155 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 33 और मौतें होने से कुल मौतों की संख्या भी 803 तक पहुंच गई। पंजाब प्रांत में 13,914 मामले, सिंध में 14,099, खैबर-पख्तूनख्वा में 5,423, बलूचिस्तान में 2,310, इस्लामाबाद में 866, गिलगित-बाल्तिस्तान में 501 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 105 मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर 3,44,450 जांच की गई हैं।

लाहौर में पाकिस्तानी शिया मुस्लिम पैगंबर मुहम्मद के दामाद और चचेरे भाई और मुस्लिम शियाओं के पहले इमाम अली की पुण्यतिथि मनाने के दौरान जुलूस निकालते हुए लोग

चीन में फिर जागा कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले

बीजिंग। चीन में कोविड-19 के 15 नए मामले सामने आए हैं जिनमें से 11 लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इन नए मामलों के साथ चीन में संक्रमितों की संख्या 82,933 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) के अनुसार, बृहस्पतिवार को जिलिन प्रांत से कोरोना वायरस के स्थानीय प्रसार के चार नए पुष्ट मामले सामने आए। नए मामलों में 11 में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, जिसके साथ ही बिना लक्षण वाले मामलों की संख्या 619 हो गई है। इसमें वुहान के 492 मामले भी शामिल हैं। चीन का वुहान शहर दुनिया में कोरोना वायरस का पहला केंद्र है। चीन ने पहले से ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिलिन शहर में सख्त नियंत्रण उपाय किए हैं।स्थानीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक वुहान में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस सप्ताह की शुरुआत में वुहान में छह नए पुष्ट मामले सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने 1.1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस शहर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया। वुहान में महामारी की एक दूसरी लहर आने का खतरा है क्योंकि यहां बिना लक्षण वाले 492 मामले सामने आ चुके हैं। एनएचसी ने कहा कि बिना लक्षण वाले 619 मरीजों में से 35 ऐसे है, जो विदेशों से आए है, जिनको चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। बिना लक्षण वाले मामलों में व्यक्ति में बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन वे फिर भी वायरस से संक्रमित होते हैं। ऐसे मरीजों से बीमारी के दूसरों तक फैलने का खतरा रहता है। कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बाद चीन ने देश को पूरी तरह से खोल दिया है।दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के व्यवसाय और कारखाने पूरी तरह से खुल गए हैं और उनमें काम चालू हो गया है। बहरहाल, चीन में कोविड-19 से 4,633 लोगों की मौत हुई है और देश में अब तक संक्रमण के 82,933 मामले सामने आए हैं, जिनमें 91 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है।

कोविड-19 की वजह से दुनिया में 2.8 करोड़ सर्जरी हो सकती हैं रद: अध्ययन

भाषा। लंदन

दुनिया भर में विभिन्न बीमारियों की वजह से 2.8 करोड़ लोगों की सर्जरी रद्द हो सकती है और मरीजों को अपनी समस्या के समाधान के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह आकलन हालिया अध्ययन में पेश किया गया है।

कोविडसर्ज कैलबैरैटिव नाम से 120 देशों पर किए एक गए शोध में कोविड-19 से पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया गया। इसके मुताबिक कोविड-19 की वजह से अस्पतालों में सबसे अधिक उथलपुथल होने से दुनियाभर में 2020 में दो करोड़ 84 लाख सर्जरी या तो रद्द की जा सकती है या उन्हें टाला जा सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी में प्रकाशित शोधपत्र के मुताबिक कोविड-19 की वजह से प्रत्एक एक हफ्ते अस्पतालों में उथलपुथल होने पर 24 लाख सर्जरी रद्द हो सकती हैं। शोधदल का नेतृत्व ब्रिटेन स्थित बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया और अध्ययन के मुताबिक दुनिया के 71 देशों के 359 अस्पतालो में सर्जरी से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई है और इन चुनिंदा सर्जरी को रद्द करने की योजना का विश्लेषण किया गया। इस आंकड़ों के आधार पर दुनिया के 190 देशों का आकलन किया गया। शोधकर्ताओं का आकलन है कि कोविड-19 के चरम पर होने पर दुनियाभर में पूर्व निर्धारित करीब 72.3 प्रतिशत सर्जरी रद्द की जा सकती हैं। इनमें अधिकतर गैर कैंसर सर्जरी होंगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक करीब 12 हफ्तों में सबसे अधिक 63 लाख हड्डी से जुड़ी सर्जरी टाली गई है। अध्ययन का आकलन है कि दुनियाभर में 23 लाख कैंसर से जुड़ी सर्जरी भी या तो रद्द कर दी गई या उसे स्थगित कर दिया गया। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अनिल भांगू ने कहा, कोरोना वायरस की महामारी के दौरान अधिकतर चुनिंदा सर्जरी को इसलिए टाला गया ताकि मरीजों को कोविड-19 के खतरे से बचाया जा सके और अस्पताल और अधिक क्षमता से वायरस संक्रमितों का इलाज कर सकें। उदाहरण के लिए ऑपरेशन थिएटर को गहन चिकित्सा कक्ष में बदला गया है। भांगू ने कहा, हालांकि, अवश्यक सर्जरी को टालने से मरीज और समाज पर भारी बोझ पड़ेगा। सर्जरी की तारीख को पुन: निर्धारित करने से मरीजों की हालत और खराब हो सकती है।उनके जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। कुछ मामलों में उदाहरण के लिए कैंसर में लोगों की सर्जरी में देरी की वजह से अनावश्यक मौत तक हो सकती है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के ही दमित्रि नेपोगोदिव ने कहा इसलिए यह अस्पतालों के लिए आवश्यक है कि वे नियमति रूप से स्थिति का आकलन करें ताकि चुनिंदा सर्जरी की प्रक्रिया को यथा शीघ्र बहाल किया जा सके।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके के परीक्षण का बंदरों पर अच्छा असर दिखा

भाषा। लंदन

ब्रिटेन की सबसे बड़े कोविड-19 टीका योजना के तहत बंदरों पर किए गए एक छोटे से अध्ययन में सकारात्मक परिणाम नजर आए हैं। इस टीके का परीक्षण फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है।

सीएचएडीऑक्स। एनसीओवी-19 परीक्षणों में लगे अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि टीके से रीसस मैकेक्यू प्रजाति के बंदरों के प्रतिरोधी तंत्र द्वारा घातक वायरस के असर को रोके जाने के संकेत मिले हैं और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं दिखा है। अध्ययन के मुताबिक, टीके की एक खुराक फेफड़ों और उन अंगों को होने वाले नुकसान से बचा सकती है जिन पर वायरस गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अध्ययन के लेखकों ने कहा सीएचएडीऑक्स। एनसीओवी-19 के साथ दिए गए एक टीके ने रीसस मैकेक्यू में प्रतिरोधी तंत्र ने द्रव एवं कोशिका संबंधी प्रतिक्रिया दर्शाई है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कोरोना वायरस के अत्यधिक स्तर से संपर्क कराने के बाद भी टीका लेने वाले छह में से किसी भी बंदर को वायरल निमोनिया नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसे भी कोई संकेत नहीं मिले कि टीके ने जानवरों को कमजोर बना दिया हो। इस उपलब्धि को उस टीके के लिए सकारात्मक संकेत माना गया है जिसका फिलहाल मानवों पर परीक्षण किया जा रहा है लेकिन विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यह देखना होगा कि यह मनुष्यों में भी इतना ही प्रभावी है या नहीं।किंग्स कॉलेज लंदन के फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की विजिटिंग प्रोफेसर डॉ पेनी वार्डा ने कहा, ए परिणाम मनुष्यों पर जारी टीके के परीक्षण को समर्थन देते हैं, जिनके परिणामों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अनुसंधान की अगुवाई कर रहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीका विज्ञान की प्राध्यापिका साराह गिलबर्ट ने पूर्व में कहा था कि उन्हें इस टीके की सफलता में अत्यधिक विश्वास है।

स्लोवेनिया ने खुद को कोविड-19 मुक्त किया घोषित

एपी। जुब्लजाना (स्लोवेनिया)

स्लोवेनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है।यूरोपीय संघ के सदस्य स्लोवेनिया की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है, विशिष्ट स्वास्थ्य उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।सरकार ने कहा कि यूरोपीय संघ के निवासी पूर्वनिर्धारित चौकियों पर ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी से स्लोवेनिया जाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन जो यूरोपीय संघ के निवासी नहीं हैं उन्हें 14 दिन तक पृथक रहना अनिवार्य है। स्लोवेनिया में कोविड-19 का पहला मामला चार मार्च को सामने आया था। संक्रमित व्यक्ति इटली से लौटा था। इसे 12 मार्च को राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित किया गया था। स्लोवेनिया में 13 मई तक 1,467 पुष्ट मामले थे और 103 लोगों की

बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविर में कोरोना का पहला मामला

एजेंसी। ढाका

दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बने भीड़-भाड़ वाले शिविरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इन शिविरों में 10 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं।देश के शरणार्थी मामलों के आयुक्त महबूब आलम तालुकदार ने बृहस्पतिवार को कहा कि रोहिंग्या समुदाय का एक व्यक्ति और कॉक्स बाजार जिले में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है जिसके बाद उन्हें पृथकवास में भेज दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता लुईस डोनोवन ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पृथक करने का प्रयास जारी है।सहायता कार्यकर्ता शिविरों में संक्रमण फैलने की आशंकाओं के बारे में संभावित चेतावनी दे रहे थे।इन शिविरों में प्लास्टिक शीट वाले तंबुओं में लगभग 40,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर (103,600 प्रति वर्ग मील) के जनसंख्या घनत्व के साथ रहते हैं। यह बांग्लादेश के औसत घनत्व से 40 गुना अधिक है जिससे शरणार्थियों में संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक झोंपड़ी बमुश्किल 10 वर्ग मीटर (107 वर्ग फुट) की है और कई में 12-12 लोग एक साथ रहते हैं।

‘लव आज कल’ में मेरा प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ’

अभिनेता कार्तिक आर्यन का कहना है कि एक ही फिल्म में यदि दो चरित्र निभाना पड़े तो ये किसी भी अभिनेता के लिए दुस्वप्न हो सकता है लेकिन फिल्म ‘लव आजकल’ में यदि सफलतापूर्वक ऐसा संभव हो सका है तो इसका पूरा श्रेय निर्देशक इम्तियाज़ अली को जाना चाहिये। आर्यन का कहना है कि अपनी बनाई फिल्मों में इम्तियाज़ सभी कलाकारों से अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने की विशेषता है।

कार्तिक ने ये बात अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से साझा की। इसमें उन्होंने फिल्म ‘लव आजकल’ से लिया गया एक फोटो भी संलग्न किया। साथ ही उन्होंने निर्देशक इम्तियाज़ अली के साथ भी अपना एक फोटो संलग्न किया।

अपनी फोटो के साथ ही उन्होंने लिखा, जब आप फिल्मों में आने का सपना देखते हैं और दर्पण के समक्ष अभिनय करते हैं तो आपको लगता है कि आप अच्छे अभिनेता हैं और आपको फिल्मों की दुनिया कुछ कुछ जादुई लगने लगती है। फिर आपको फिल्म में रोल मिलता है और आप कैमरा देखकर घबरा जाते हैं। तब आपको ये अत्यंत कठिन लगने लगता है। शूटिंग स्थल पर तेज चमकती लाइटें आपके खराब प्रदर्शन पर आपको डांटती प्रतीत होती हैं कि क्यों तुम सभी का समय व्यर्थ कर रहे हो।

आगे बताते हुए उन्होंने लिखा, ‘पहले कुछ साल तो नर्वस न दिखने के प्रयास करने में ही निकल जाते हैं। इसके बाद आपको इम्तियाज़ अली जैसा व्यक्ति मिलता है। वो जैसे ही अपनी कहानी सुनाते हैं आप एक सपने की दुनिया में चले जाते से लगते हैं।

मुझे स्मरण नहीं कि मैंने उनके सेट पर कभी कैमरा भी देखा हो। वो सदैव वहां खड़े मिलते थे जहां सीन के कट होने के बाद मैं देखता था। वो कभी मॉनिटर पर नहीं दिखते थे वो सदा मेरे साथ ही रहे। आपको इम्तियाज़ अली के सेट पर लाइटें टेप के निशान ढूंढने में सहायक होती हैं।’

जब आप फिल्मों में आने का सपना देखते हैं और दर्पण के समक्ष अभिनय करते हैं तो आपको लगता है कि आप अच्छे अभिनेता हैं और आपको फिल्मों की दुनिया कुछ कुछ जादुई लगने लगती है। फिर आपको फिल्म में रोल मिलता है और आप कैमरा देखकर घबरा जाते हैं। तब आपको ये अत्यंत कठिन लगने लगता है। शूटिंग स्थल पर तेज चमकती लाइटें आपके खराब प्रदर्शन पर आपको डांटती प्रतीत होती हैं कि क्यों तुम सभी का समय व्यर्थ कर रहे हो।

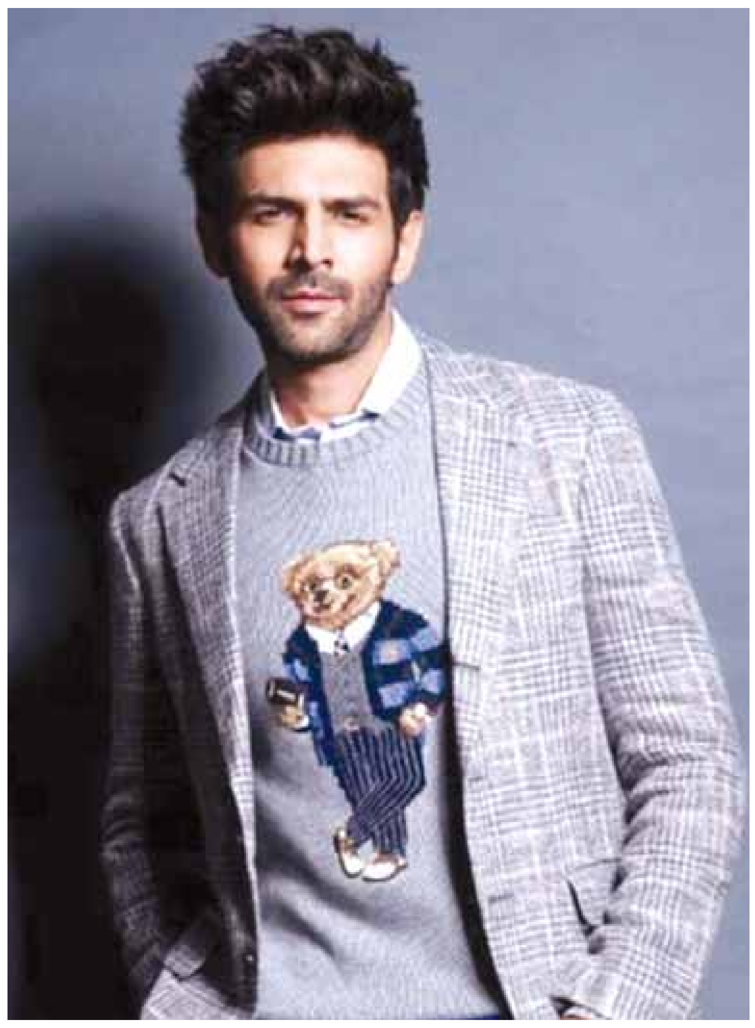

कार्तिक का कहना है कि लव आज कल में प्रदर्शन के बाद लोगों का जितना प्यार मिला, उतना प्यार उन्हें आजतक नहीं मिला।

उन्होंने बताया, ‘और वो भी उन फिल्म निर्माताओं और लोगों से, जिन्हें मैं इंडस्ट्री में सर्वाधिक सम्मानित मानता हूं। कितनी बड़ी विडंबना है कि फिल्म इतनी सरलता से बन गई कि इसके बनने का पता ही नहीं चला। एक ही फिल्म में दो चरित्र करना मेरे लिए एक डरावने सपने से कम नहीं था। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब वीर बना और कब रघु। ये सब निर्देशक इम्तियाज़ अली का ही चमत्कार था।’

आगे उन्होंने बताया, ‘किसी भी अभिनेता के लिए दर्पण से अच्छा कोई दूसरा वातावरण नहीं हो सकता। इम्तियाज़ आपको वैसा ही अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि देश के कुछ महान अभिनेताओं का सर्वश्रेष्ठ अभिनय इम्तियाज़ अली की फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं।’

आर्यन ने इसके बाद इम्तियाज़ की प्रशंसा करते हुए उन्हें जादूगर बताया।

‘इम्तियाज़ अली निर्देशक नहीं हैं वो तो जादूगर हैं! मुझे मेरे अभी तक के कॅरियर में सबसे अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए आपका धन्यवाद,’ आर्यन ने कहा।

लव आज कल में उनके साथ सारा अली खान थी और ये फिल्म इसी साल वैलेंटाइन दिवस पर रिलीज़ हुई थी। इसमें दो युगों की लव स्टोरीज़ दिखाई गई थीं। इनमें से पहली तो 80 के दशक के अंतिम समय की थी जिसमें रघु और लीना को दिखाया गया। इसके बाद वर्तमान में प्यार में पड़े वीर और ज़ो की कहानी प्रस्तुत की गई थी।

फिल्म वास्तव में अली की ही 2009 की फिल्म की अलग प्रस्तुतीकरण था जिसमें दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान लीड भूमिकाओं में थे। ये हिट साबित हुई थी। लेकिन 2020 की लव आज कल को दर्शकों का आशानुरूप समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। समीक्षकों ने भी फिल्म की आलोचना की थी।

आशा जी ने बनाया अपना यूट्यूब चैनल

दिग्गज गायिका आशा भोंसले का कहना है कि नाती पोतों से मिली प्रेरणा के चलते ही उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है।

भोंसले का कहना है, ‘आजकल की परिस्थिति के कारण सभी लोगों की ही भांति मैं भी घर तक ही सीमित हो गई हूं। मैं घर में रहकर अपने नाती पोतों के साथ इंटरनेट पर उनके कौशल से परिचित हुई हूं। मेरे लिए तो ये एक नई दुनिया का द्वार खुलने जैसा अनुभव था।’

भोंसले ने हाल ही में अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है।

वास्तविक दुनिया से दूर हो रहे हैं युवा

अभिनेत्री ईशा गुप्ता का कहना है कि ‘आजकल युवाओं को वास्तविक विश्व की अपेक्षा फर्स्ट-वर्ल्ड से जुड़ी समस्याएं अधिक हैं। उनकी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं- मुझे सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स और दूसरे लोगों जैसी लाइक्स और लोकप्रियता क्यों नहीं मिल रहीं? या फिर ‘उसकी कार मेरी कार से अधिक बड़ी क्यों है?’ वे सदैव दूसरों से और उनकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करते मिलेंगे। ‘वे सदैव दिखावे में व्यस्त रहते हैं और वास्तविक दुनिया से उनका सरोकार अधिक नहीं रहता।’

सोना मोहपात्रा ने आयोजित की वेबिनार

सिंगर और संगीतकार सोना मोहपात्रा ने हाल ही में 17000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया था।

इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारे स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सकं तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी हमारे वास्तविक नायक और योद्धा हैं। उन्हें हमारे स्नेह और समर्थन की आवश्यकता है। उनका काम अत्यंत जोखिमपूर्ण है क्योंकि वे वायरस के सीधे संपर्क में रहते हैं वे जीवन और मृत्यु के बीच लगातार जोखिम का सामना करते हैं। इस स्थिति के लिए आप किसी भी तरह से संपूर्ण तैयारी नहीं कर सकते। मैं उन्हें अनवरत मनोरंजन, उनका उत्साहवर्धन तथा समर्थन करना चाहती हूं। ऐसा करके मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम उनके कितने कृतज्ञ हैं।

स्कारलेट जोहांसन फिल्म की रिलीज में देरी से विचलित

हॉलिवुड स्टार स्कारलेट जोहांसन अनुभव करती हैं कि उन्हें फिल्म ‘ब्लैक विडो’ में सुपर हीरो का चरित्र करके अत्यंत आनंदित अनुभव किया था। उनका कहना है कि उसमें उनका चरित्र बीते 10 सालों में और भी बड़ा हो गया है। जोहांसन ने इस फिल्म को मार्वेल सिनेमेटिक यूनिवर्स में शूट किया था। अब वो इसकी रिलीज़ की प्रतीक्षा कर रही हैं। कोरोना वायरस से प्रसारित महामारी के कारण कई फिल्मों की रिलीज़ विलंबित हो चुकी हैं।

‘मेरा मानना है कि मेरा चरित्र बीते 10 सालों में बहुत बड़ा हो गया है। बल्कि अब वो अपने समूह का नेतृत्व करता है। मेरे अनुसार ये बहुत स्वाभाविक परिणति थी। वो प्रगतिशील, लचीली और दुनिया में फैले अंधकार और बुराइयों के प्रति सचेत थी,’ जोहांसन ने बताया।

लॉकडाउन स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बेहतर समय : एवलिन

अभिनेत्री एवलिन शर्मा विश्वव्यापी लॉकडाउन में अपने परिवार व अपने मंगेतर तुशान भिंडी संग ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनका कहना है कि क्वारंटाइन की यह अवधि स्क्रिप्ट लिखने की दिशा में हाथ आजमाने का एक बेहतर समय है।

एवलिन ने आईएएनएस से कहा, हालात काफी मुश्किल भरे रहे हैं। सीमाओं के बंद होने से पहले ही समय से मैं भी ऑस्ट्रेलिया आ गई। अपने परिवार व मंगेतर तुशान के पास वापस आकर मैं बहुत खुश हूं। घर से काम कर मैं खुद को व्यस्त रख रही हूं। अभिनेत्री का मानना है कि यह विभिन्न गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखने का एक उपयुक्त वक्त है।

वह कहती हैं, मैंने महसूस किया कि यह अपनी पसंदीदा गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखने का एक बेहतर समय है। मैं आजकल बागवानी कर रही हूं और अपने लिए सब्जियां उगा रही हूं। मैंने यह भी पाया कि यह स्वयं को स्क्रिप्ट राइटिंग में समर्पित करने के लिए एक सही समय है। एवलिन का यह भी मानना है कि यह अपने करीबियों संग वक्त बिताने का भी एक बेहतर पल है। उन्होंने आईएएनएस को बताया, एक एक्टर होने के नाते मुझे अक्सर यहां-वहां सफर करते रहना पड़ता है, जिसके चलते मुझे परिवार संग वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पाता है।

ऐसे में अभी परिवार के साथ यहां रहने की मुझे खुशी है। यह रिश्तों को बेहतर बनाने और साथ में मिलकर खूबसूरत यादें बनाने का सबसे अच्छा अच्छा तरीका है।

ऋचा चड्ढा ने अपने स्टाफ के लिए बनाया कोविड से जुड़ा वीडियो

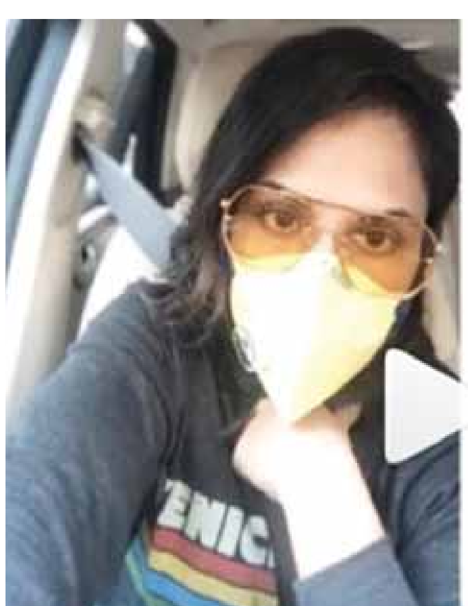

मैंने अपने फोन में वीडियो बनाए और उन्हें अपने स्टाफ को फॉरवर्ड किया क्योंकि मैं चाहती हूं कि वे इस घड़ी में स्वस्थ व सुरक्षित रहें। बेशक आर्थिक रूप से उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि किराने का सामना या जरूरी चीजें खरीदते वक्त घर से बाहर निकलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी उन्हें सही जानकारी हो।

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने इस बात को महसूस किया कि कोविड-19 के बारे में कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों के बारे में अपने स्टाफ को बताया जाना बहुत जरूरी है, जिनका पालन वह खुद पिछले दो महीनों से करती आ रही हैं।

ऋचा ने इसे ध्यान में रखते हुए आसान भाषा में समझ में आने वाले कुछ वीडियो बनाए हैं। इनमें इस अहम बात को साझा किया गया है कि इस महामारी की चपेट में आने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, मैंने अपने फोन में वीडियो बनाए और उन्हें अपने स्टाफ को फॉरवर्ड किया क्योंकि मैं चाहती हूं कि वे इस घड़ी में स्वस्थ व सुरक्षित रहें। बेशक आर्थिक रूप से उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि किराने का सामना या जरूरी चीजें खरीदते वक्त घर से बाहर निकलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी उन्हें सही जानकारी हो।

वह आगे कहती हैं, हमें शायद इस बात का अहसास नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत बड़ी बात है। जब एक ही कमरे में पांच लोग साथ रहते हैं, तो ऐसे में अगर घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान नहीं रखेंगे, तो हर कोई इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है।

सलमान के बिना बॉलीवुड में आने का सोच भी नहीं सकती थी- जरीन खान

अभिनेत्री जरीन खान ने अब से लगभग एक दशक पहले आई फिल्म वीर से बॉलीवुड में कदम रखा था। सुपरस्टार सलमान खान के होने के बावजूद भी यह फिल्म दर्शकों पर अपना जादू चलाने में नाकामयाब रही, लेकिन इससे जरीन के लिए कई अवसर खुले। वह खुशी-खुशी इसका श्रेय सलमान को देती हैं क्योंकि उन्होंने ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया।

जरीन ने बताया, इस सफर में कई उतार-चढ़ाव रहे। मैं एक ऐसी इंसान हूं, जिसने इंडस्ट्री का हिस्सा होने का सपना कभी नहीं देखा था। मुझे यह मौका दिलाने के लिए मैं सलमान की शुक्रगुजार हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनके बिना मैं फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन सकती थी।

वह आगे कहती हैं, फिल्मों में आने के लिए मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन इसका हिस्सा बनने के बाद मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ। मैं फिल्मी पृष्ठभूमि से ताल्लुक नहीं रखती हूं, इसलिए इंडस्ट्री में काम-काज करने के तरीकों को सीखने में मुझे कुछ वक्त लगा। मैं यह नहीं कहूंगी कि अब मुझे यहां दस साल हो गए हैं और मैंने सब कुछ सीख लिया है। सच कहूं, तो मैं अभी भी सीख रही हूं, लेकिन जब मैं पहले आई थी उसकी अपेक्षा आज कुछ बेहतर हूं।

अपनी आगामी परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए वह कहती हैं, मई में लंदन में एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। एक हॉरर फिल्म और डिजिटल में मेरे डेब्यू शो पर भी काम शुरू करना था।

अभी सब कुछ अनिश्चित है। मुझे नहीं पता कि जिंदगी कब पटरी पर आएगी। मौजूदा हालात को देखते हुए, ऐसा लगता है कि चीजों को ठीक होने में वक्त लगेगा - खासकर हमारी इंडस्ट्री में, जहां लोग टीम में रहकर काम करते हैं।

नैंसी ड्र अपनी पहचान दोबारा हासिल करने के बारे में है : मैकमैन

अभिनेत्री केनेडी मैकमैन का कहना है कि उनका शो नैंसी ड्रू अपनी पहचान को पुन- प्राप्त करने और इसके अंदर निहित रहस्यों का पता लगाने के बारे में है।

मैकमैन ने कहा, नैंसी ड्रू, नैंसी की कहानी है, जो कुछ किरदारों की मदद से अपनी पहचान को दोबारा हासिल करती है। वह अपने अतीत में गोते लगाकर इसके अंदर समाए कुछ रहस्यों का पता लगाती है। शो की कहानी नैंसी ड्रू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने आप को उस वक्त एक रहस्य से घिरा हुआ पाती है, जब वह और उसके दोस्त एक मर्डर केस में शामिल हो जाते हैं। शो के नए संस्करण के बारे में बात करते हुए मैकमैन ने कहा, नैंसी हाई स्कूल पास कर कॉलेज जाने वाली एक लड़की है। इस बीच अचानक उसकी मां की मौत हो जाती है, जिसके चलते उसकी जिंदगी टूटकर बिखर जाती है।

इस पूरे अनुभव से नैंसी पहले से काफी बदल जाती है और अब उसे अपने माता-पिता के बिना एक वयस्क के रूप में नए-नए अनुभवों की तलाश रहती है। नैंसी ड्रू सीजन वन को फिलहाल भारत में वूट सिलेक्ट पर प्रसारित किया जा रहा है।

युवावस्था में आने पर हम और ज्यादा बागी हो जाते हैं : ऋत्विक साहोरे

नई शॉर्ट फिल्म द ट्विस्ट में नवागंतुक अभिनेता ऋत्विक साहोरे, श्लोक का किरदार निभा रहे हैं, जो दसवीं कक्षा के छात्र हैं और उन्हें उनकी किसी सहपाठी द्वारा अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कहा जाता है। ऋत्विक ने इस बारे में बताया, मैं स्वभाव से अंतमुर्खी हूं, तो जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सुनी और मुझे पता लगा कि मुझे फिल्म में खूब सारा डांस करना होगा, तो मैं झिझक रहा था। यह मेरे लिए अजीब था, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे कोरियोग्राफर शाजेब शेख ने इसे वास्तव में कर दिखाया। इसके अलावा सान्या (मल्होत्रा) ने भी मेरी मदद की और तब यह और आसान हो गया क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे को दंगल के सेट से जानते हैं।

मैं स्वभाव से अंतमुर्खी हूं, तो जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सुनी और मुझे पता लगा कि मुझे फिल्म में खूब सारा डांस करना होगा, तो मैं झिझक रहा था। यह मेरे लिए अजीब था, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे कोरियोग्राफर शाजेब शेख ने इसे वास्तव में कर दिखाया।

चूंकि फिल्म की कहानी एक छात्र के इर्द-गिर्द घूमती है, तो इसमें एक कलाकार के रूप में ऋत्विक को संवेदनाओं की विभिन्न छवि को उकेरने का मौका मिला और उनके मुताबिक यह काफी रोचक रहा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से किशोरावस्था में लड़के-लड़कियों को आम चीजें करने में भी परेशानी होती है, जैसे कि दादा-दादी के साथ वक्त बिताना इत्यादि। वह कहते हैं, यह सच है कि वास्तविक जीवन में हमारे बीच जेनरेशन गैप मौजूद है, लेकिन किशोरावस्था में आकर ये सारी चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती है। मेरे ख्याल से किशोरावस्था में हम और ज्यादा बागी बन जाते हैं। हमें लगता है कि सारी सही चीजें बस हमें ही पता है और माता-पिता, दादा-दादी काफी पुराने ख्यालात वाले हैं, लेकिन यह बस उम्र और हारमोन्स से जुड़ी हुई एक बात है। हम वास्तव में बुरे नहीं होते हैं।